राष्ट्रीय संस्करण



भागवत बोले, सीएए और एनआरसी से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं >>3

वर्ष 5 अंक 42

दैनिक जागरण

मूल्य ₹8.00, नई दिल्ली, गुरुवार, 22 जुलाई, 2021

www.jagran.com

पृष्ठ 14

जागरण विशेष

सेहत को मिल रहा गोमाता का 'अनादि' आशीर्वाद



फरीदाबाद: बिल्व पत्र के साथ माटी की हांडी में पके 'अनादि' देशी घी का दुबई, अमेरिका, हांगकांग, सिंगापुर तक लोग सेवन कर रहे हैं। अनादि सेवा प्रकल्प वृद्धाश्रम में यह घी तैयार किया जाता है। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राजनीति ▶ पृष्ठ 4

भाजपा के खिलाफ एकजुट हों सभी विपक्षी दल : ममता

कोलकाता: बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की निगाहें अब दिल्ली पर हैं। 2024 के लोस चुनाव के मद्देनजर ममता, भाजपा की घेराबंदी करने के लिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में जुट गई हैं। बुधवार को शहीद दिवस पर तृणमूल कांग्रेस के सबसे बड़े वार्षिक कार्यक्रम के मौके पर ममता ने विपक्षी दलों से एकजुट होने और एक फ्रंट बनाने का आह्वान करते हुए भगवा दल को दिल्ली की गद्दी से हटाने की हुंकार भरी।

राष्ट्रीय फलक ▶ पृष्ठ 5

जम्मू एयरपोर्ट पर फिर मंडराता दिखा पाकिस्तानी ड्रोन

जम्मू : अतिसुरक्षित और संवेदनशील जम्मू एयरपोर्ट इलाके में बुधवार तड़के पाकिस्तानी ड्रोन दो बार देखा गया। सुरक्षाबलों की कार्रवाई से पहले ही वह लौट गया। ड्रोन देखे जाने के बाद एयरपोर्ट और सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए नए अलर्ट जारी किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां भी और सतर्क हो गई हैं। पिछले 19 दिन में जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के नौ मामले सामने आ चुके हैं।

राष्ट्रीय फलक ▶ पृष्ठ 6

फ्रांस से भारत को तीन राफेल लड़ाकू विमान और मिले

नई दिल्ली: फ्रांस से तीन और राफेल लड़ाकू विमान बुधवार को भारत पहुंच गए हैं। फ्रांस से मिलने वाली राफेल विमानों की यह सातवीं खेप है। इन विमानों के आने से वायु सेना की मारक क्षमता और मजबूत हो गई है। इन लड़ाकू विमानों को भारतीय वायु सेना के दूसरे स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा, जिसे चीन की सीमा के करीब बंगाल के हासिमारा एयरबेस पर बनाया गया है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 11

पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक की बेटी की इस्लामाबाद में हत्या

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक शौकत मुकादम की 27 वर्षीया बेटी नूर मुकादम की राजधानी इस्लामाबाद में गोली मार कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के राजदूत की बेटी के अपहरण व यातना देने को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पैदा हुए बड़े कूटनीतिक विवाद के बाद यह दूसरी बड़ी घटना हुई है।

बदलती तस्वीर ▶ जम्मू-कश्मीर में डोमिसाइल नियम में बड़ा बदलाव, जमीन-जायदाद खरीदने का मिलेगा अधिकार

सूबे के बाहर के दामाद भी होंगे स्थानीय निवासी

ऐसे डोमिसाइल धारक जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

दूसरे प्रदेश में ब्याही जम्मू-कश्मीर की बेटियों के पति भी आजादी के बाद पहली बार इस केंद्र शासित प्रदेश के स्थानीय निवासी (डोमिसाइल) बनने का हक हासिल कर सकेंगे। वह योग्यता के अनुसार जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे और जमीन-जायदाद भी खरीद सकेंगे।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 और जम्मू-कश्मीर सिविल सर्विसेज (डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट) एक्ट, 2010 के तहत डोमिसाइल प्रमाणपत्र (प्रक्रिया) नियमों में एक प्रविधान और जोड़ा है, जो यह सुनिश्चित करता है कि जम्मू-कश्मीर के डोमिसाइल से शादी करने वाला कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर का डोमिसाइल प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संदर्भ में आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी है।

इस बदलाव के बाद जम्मू-कश्मीर में डोमिसाइल प्राप्त करने के प्रविधान अब छह से बढ़कर सात हो गए हैं। सातवें प्रविधान के मुताबिक, अगर जम्मू-कश्मीर के डोमिसाइल युवक या युवती ने किसी अन्य राज्य में शादी की है या किसी गैर डोमिसाइल से शादी की है, तो वह जीवनसाथी (स्पाउस) भी जम्मू-कश्मीर का निवासी बनने का हकदार होगा। उसे शादी का प्रमाणपत्र व स्पाउस का डोमिसाइल प्रमाणपत्र तहसीलदार के समक्ष पेश करना होगा। डोमिसाइल जारी न होने पर आवेदक जिला उपायुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। इसके लिए जम्मू-कश्मीर सिविल सर्विसेज (डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट) एक्ट, 2010 में धारा 3ए (2)(3) जोड़ी गई है।



बड़ा निर्णय : जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। जागरण आर्काइव

डोमिसाइल प्रक्रिया में हुआ आवश्यक सुधार

पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू होने साथ ही राज्य दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में पुनर्गठित हुआ। अनुच्छेद 370 और 35ए समाप्त हो गए। सभी नागरिक बराबर हो गए। जम्मू-कश्मीर के लोगों द्वारा पहचान व रोजगार का मुद्दा उठाने पर केंद्र सरकार ने डोमिसाइल प्रमाणपत्र का प्रविधान किया। इसके मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में 15 वर्ष तक निवास करने वाला, वहां पैदा होने वाला, दसवीं की पढ़ाई करने वाला डोमिसाइल प्राप्त करने और जम्मू-कश्मीर सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। इस नियम में जम्मू-कश्मीर की स्थानीय निवासी युवती से शादी करने वाले अन्य राज्यों के युवक या गैर डोमिसाइल युवक का उल्लेख नहीं था। इससे वही समस्या पेश आने लगी थी जो अनुच्छेद 35ए के कारण थी। इसका संज्ञान लेते हुए उपराज्यपाल ने आवश्यक सुधार किया है।

पहले यह थी व्यवस्था

जम्मू-कश्मीर में पांच अगस्त 2019 से पहले अनुच्छेद 370 और 35ए लागू था। तब राज्य के डोमिसाइल धारक ही सूबे में सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते थे, जमीन- जायदाद खरीद सकते थे। मतदान कर सकते थे। अन्य लोग नहीं। अगर राज्य की कोई महिला चाहे वह डोमिसाइल ही क्यों न हो, अन्य राज्य के निवासी से शादी करती तो उसका जम्मू-कश्मीर की स्थानीय निवासी होने का हक समाप्त हो जाता था। उसके पति और बच्चों को जम्मू-कश्मीर में जमीन-जायदाद खरीदने या किसी सरकारी विभाग में नौकरी का अधिकार नहीं था।

बेटियों के अधिकार सुरक्षित : जितेंद्र सिंह



प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से शादी कर बाहर जाने वाली बेटियों व जम्मू-कश्मीर में शादी करने वाली अन्य प्रदेशों की बेटियों के अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सिंह ने दैनिक जागरण को बताया कि जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन होने के बाद ही यह फैसला कर लिया गया था। अब इसे प्रभावी बनाकर बेटियों के साथ इंसाफ किया जाएगा।

कश्मीर में अब कोई नहीं बनना चाहता आतंक का पोस्टर ब्वाय

श्रीनगर : इंटरनेट मीडिया पर अब कश्मीरी आतंकी नजर नहीं आते। अगर कोई आतंकी बनता भी है तो वह इसका एलान नहीं करता। उसके समर्थक भी उसकी तस्वीरें या वीडियो वायरल करना तो दूर सार्वजनिक जगहों पर उसका नाम तक नहीं लेते। पांच अगस्त, 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर में लगातार सुधर रहे सुरक्षा परिदृश्य में अगर कश्मीरी अवाम ने सबसे ज्यादा कोई सुखद बदलाव महसूस किया है तो यही कि अब कोई भी आतंकियों का पोस्टर ब्वाय नहीं बनना चाहता, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही वह ऐसा करेंगे, कुछ दिन में या तो पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे। (पेज-5)

खत्म हुई जद्दोजहद, इंसाफ मिलेगा पेज>>5

पेगासस मामले में अफसरों से पूछताछ कर सकती है संसदीय समिति

नई दिल्ली, प्रेट्र : पेगासस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी संसदीय समिति अगले हफ्ते गृह मंत्रालय समेत सरकार के शीर्ष अधिकारियों से सवाल जवाब कर सकती है। कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली इस समिति की 28 जुलाई को बैठक बुलाई गई है। इजरायली स्पाइवेयर पेगासस के जरिये कई नेताओं, पत्रकारों और अन्य नामचीन लोगों के फोन टैप कराए जाने के आरोप हैं।

हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया कंसोर्टियम ने यह दावा किया था कि राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं, दो केंद्रीय मंत्रियों, तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी, लगभग 40 पत्रकारों और उद्यमियों समेत कई नामचीन लोगों के फोन नंबर उस सूची में शामिल थे, जिसे पेगासस साफ्टवेयर के जरिये हैक किया जाना था। हालांकि, भारत सरकार और पेगासस स्पाइवेयर बेचने वाली इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप ने रिपोर्ट को खारिज किया था।

लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक 32 सदस्यीय संसदीय समिति की बैठक का एजेंडा 'नागरिक डाटा सुरक्षा एवं गोपनीयता' है। इसमें ज्यादातर सदस्य भाजपा के हैं। समिति ने इलेक्ट्रानिक्स, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों को तलब किया है।

पैनल के सूत्रों ने बताया कि बैठक में पेगासस फोन टैपिंग मुद्दा जरूर उठाया जाएगा और सरकारी अधिकारियों से इसके बारे में विस्तुत जानकारी ली जाएगी। इस मामले के सामने आने के बाद से संसद के मानसून सत्र में हंगामा मचा हुआ है। थरूर ने इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बताते हुए सरकार से जवाब भी देने को कहा था।

फोन टैपिंग मामला

- सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी संसदीय समिति की 28 जुलाई को बुलाई गई बैठक
- कांग्रेस नेता शशि थरूर हैं इस समिति के अध्यक्ष, इस मामले को लेकर मचा है हंगामा



कांग्रेस नेता एवं सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी संसदीय समिति के अध्यक्ष शशि थरूर। जागरण आर्काइव

नया नहीं है पेगासस मामला : कुमारस्वामी



समाचार एजेंसी एएनआइ की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने मंगलवार को बेंगलुरु में कहा कि उनके लिए पेगासस जासूसी मामला कोई नया मामला नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न सरकारों के दौरान फोन टैपिंग के मामले हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार गिरी थी तब भी फोन टैपिंग का मामला उठा था। विपक्षी दल बेवजह इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्हें सरकार की विफलताओं को सामने लाने पर ध्यान देना चाहिए। कुमारस्वामी ने यह भी कहा कि पेगासस जासूसी कांड की जांच कर दाताओं के पैसे की बर्बादी है।

एनएसओ ग्रुप के खिलाफ जांच का अध्ययन कर रहा इजरायली रक्षा मंत्रालय पेज>>3

दिल्ली-महाराष्ट्र ने क्यों कहा, आक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई : पात्रा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना की दूसरी लहर में बड़ा मुद्दा बनी आक्सीजन फिर से राजनीति का केंद्र बन गई है। विपक्षी दलों की ओर से केंद्र के उस जवाब को मुद्दा बनाया जा रहा है जिसमें उसने कहा है कि किसी भी राज्य ने आक्सीजन की कमी से मौत होने की सूचना नहीं दी है। जवाब में भाजपा ने भी राज्य सरकारों के रिकार्ड और हाई कोर्ट में उनके बयानों को तथ्य के रूप में रखकर लड़ाई को तीखा बना दिया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकारों ने संबंधित हाई कोर्टों में दिए हलफनामे में कहा है कि आक्सीजन की कमी के कारण एक भी मौत नहीं हुई। भाजपा उपाध्यक्ष व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राहुल गांधी को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा, अपने मुख्यमंत्री से क्यों नहीं पूछते कि वहां कितनी मौतें आक्सीजन की कमी से हुईं।

पात्रा ने मंगलवार को राज्यसभा में दिए गए केंद्र सरकार के बयान को सही बताते हुए कहा, स्वास्थ्य राज्य का विषय है। राज्यों की ओर से रिकार्ड भेजे जाते हैं और केंद्र उनका संकलन करता है। केंद्र की ओर से यही कहा गया कि किसी भी राज्य ने अब तक केंद्र को नहीं बताया कि उनके यहां कोई भी मौत आक्सीजन की कमी से हुई थी। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, महाराष्ट्र सरकार व राहुल गांधी से सवाल किया कि उन्होंने कोई जानकारी क्यों नहीं दी। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर जयपुर गोल्डन अस्पताल में 21 मरीजों की मौत की जांच रिपोर्ट में खुद दिल्ली सरकार ने कहा कि आक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुईं। महाराष्ट्र सरकार ने भी बांबे हाई कोर्ट में इसी तरह का दावा किया था।

रमन सिंह बोले, राहुल जी यह दोगलापन व दोमुंहापन क्यों? छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पताल में सात बच्चों की मौत हुई और परिवार के लोग कह रहे हैं कि आक्सीजन समय पर नहीं मिली। वहां कांग्रेस की सरकार है इसलिए मुख्यमंत्री से जवाब नहीं मांग रहे हैं। पात्रा ने कहा, विपक्ष इस संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति से बाज नहीं आ रहा है। अगर केंद्र दखल देना शुरू करे तो आरोप लगाते हैं कि उनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप हो रहा है। मौत के आंकड़े राज्य भेज रहे हैं, सवाल केंद्र से पूछा जा रहा है। केंद्र की मदद के बावजूद दिल्ली सरकार आक्सीजन आपूर्ति में चूकी। उस समय अस्पतालों की ओर से दिल्ली सरकार को काल किए जा रहे थे, लेकिन वह आक्सीजन नहीं पहुंचा पा रही थी। ज्ञात हो, स्वास्थ्य राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा था कि किसी भी प्रदेश ने केंद्र को यह नहीं बताया कि किसी की मौत आक्सीजन की कमी से हुई है।

सियासत आक्सीजन की

- दोनों राज्यों के हाई कोर्ट में दिए हलफनामे का दिया हवाला
- राहुल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से क्यों नहीं पूछते : रमन सिंह



संबित पात्रा। फाइल/इंटरनेट मीडिया

आक्सीजन की कमी से मौत के मुद्दे पर राउत बोले, केंद्र झूठ बोल रहा पेज>>3

राजस्थान में शिक्षामंत्री की बहू समेत तीन रिश्तेदारों को परीक्षा में मिले समान अंक, विपक्ष ने घेरा

जागरण संवाददाता, जयपुर

राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के तीन रिश्तेदारों के चयन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इनमें एक डोटासरा की पुत्रवधू हैं। साक्षात्कार में तीनों के एक समान 80-80 प्रतिशत अंक मिले हैं, जबकि लिखित परीक्षा में 50 फीसद से भी कम अंक हैं।

भाजपा नेता गुलाब चंद कटारिया कहते हैं, एक ही परिवार के तीन सदस्यों को साक्षात्कार में बराबर नंबर मिलना तो चमत्कार है। इससे साफ लगता है कि साक्षात्कार में गड़बड़ी हुई है। यह जांच का विषय है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि जांच होनी चहिए और तब तक डोटासरा को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं, संपर्क करने पर राजस्थान लोकसेवा आयोग (आरपीएससी) के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह यादव ने कहा कि आज बकरीद का अवकाश होने के कारण रिकार्ड नहीं देख सकता। रिकार्ड देखने के बाद ही कुछ कह सकूंगा।

- आरएएस की लिखित परीक्षा में 50% से भी कम और साक्षात्कार में मिले 80 %अंक
- भाजपा ने लगाया गड़बड़ी का आरोप, शिक्षा मंत्री डोटासरा से मांगा इस्तीफा

यह है मामला : आरपीएससी ने गत सप्ताह वर्ष 2016 और 2018 की परीक्षा का नतीजा जारी किया था। डोटासरा की पुत्रवधू प्रतिभा पूनिया, उनकी बहन प्रभा व भाई गौरव का आरएएस सेवा में चयन हुआ है। गौरव को लिखित परीक्षा में 47.44 फीसद, प्रभा को 45.81 व प्रतिभा को 50.25 अंक मिले। साक्षात्कार में तीनों को 80 फीसद अंक मिले हैं। ज्ञात हो कि प्रतिभा ने 2016 व गौरव तथा प्रभा ने 2018 में परीक्षा दी थी।

आरपीएससी पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराता है। मेरी पुत्रवधू ने परीक्षा दी तब भाजपा का शासन था, चाहे उसका साक्षात्कार अब हुआ हो। दरअसल, फेल हो गए लोग खीझ मिटा रहे हैं और विपक्ष उनका साथ दे रहा है। -गोविंद सिंह डोटासरा (शिक्षामंत्री)

उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति को मिली मंजूरी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति 2021 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस नई नीति के माध्यम से 2026 तक महिलाओं द्वारा सूचित व स्व निर्णय के माध्यम से सकल प्रजनन दर को 2.1 और 2030 तक 1.9 फीसद पर लाने का लक्ष्य तय किया गया है। दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 जुलाई को नई जनसंख्या नीति जारी कर चुके हैं। इसमें प्रजनन दर नियंत्रण करने, मातृ शिशु मृत्यु दर कम करने समेत कई प्रविधान किए गए हैं। जनसंख्या नीति 2021 में सभी समुदायों में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए कानून बनाने की बात भी कही गई है। जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के साथ-साथ नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने, पोषण की स्थिति में सुधार करने, किशोर-किशोरियों के स्वास्थ्य तथा पोषण से संबंधित सूचनाओं और सेवाओं में सुधार का भी प्रविधान किया गया है।

चीन में हजार साल की सबसे भीषण वारिश से तबाही

बीजिंग : चीन के हेनान प्रांत में मौसम का कहर टूटा है। एक हजार साल की सबसे भीषण बारिश से भयावह बाढ़ के हालात बन गए हैं। एक दर्जन से अधिक शहर जलमग्न हो गए। टनल में फंसी मेट्रो में पानी भर गया और स्टेशनों से लोग निकल नहीं पाए। यिचुआन में उफनती नदी के पानी को मोड़ने के लिए सेना को एक क्षतिग्रस्त बांध को उड़ाना पड़ा है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। (पेज-11)

ब्रिसवेन करेगा 2032 ओलिंपिक की मेजवानी

टोक्यो : अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति (आइओसी) ने बुधवार को ब्रिसबेन को 2032 ओलिंपिक की मेजबानी के लिए चुना। ब्रिसबेन के खिलाफ किसी शहर ने मेजबानी की दावेदारी पेश नहीं की। सिडनी में 2000 में खेलों के आयोजन के बाद ओलिंपिक 32 साल बाद एक बार फिर आस्ट्रेलिया लौटेंगे। (पेज-12)

ग्रेटर नोएडा के किसानों को मिलेगा बढ़ा मुआवजा

माला दीक्षित, नई दिल्ली

- शीर्ष अदालत ने जमीन की दर को 39 से बढ़ाकर 65 रुपये प्रति वर्ग गज किया
- एछर गांव के किसानों की याचिका पर फैसला, 1989 में अधिगृहीत हुई थी भूमि

सुप्रीम कोर्ट से ग्रेटर नोएडा के एछर गांव के किसानों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 1989 में अधिगृहीत की गई उनकी जमीन के मुआवजे को 39 रुपये से बढ़ाकर 65 रुपये प्रति वर्ग गज कर दिया है। साथ ही आठ हफ्ते के भीतर याचिका दाखिल करने वाले भूस्वामियों को बढ़ा मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा के कासना, एछर, गूजरपुर व हल्डोना गांव की करीब 534 एकड़ जमीन अधिगृहीत की थी। अधिग्रहण के समय यह जमीन बुलंदशहर जिले में आती थी, अब ग्रेटर नोएडा में आ गई है। कासना गांव के भूस्वामियों को 65 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से मुआवजा मिला था और एछर गांव के भूस्वामियों को 39 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से। कासना गांव के बराबर मुआवजा की मांग वाली एछर गांव के भूस्वामियों की याचिका पर मुआवजा बढ़ाने के बजाय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 16 सितंबर, 2019 को उसे वापस रिफरेंस कोर्ट भेज दिया था। इसके खिलाफ एछर के कुछ भूस्वामियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।



न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने भूस्वामियों के वकील ऋषि मल्होत्रा की दलीलें सुनने के बाद गत शुक्रवार 16 जुलाई को मुआवजा बढ़ा कर 65 रुपये प्रति वर्ग गज करने का फैसला सुनाया। मल्होत्रा ने कहा, जब हाईकोर्ट ने यह माना है कि याचिकाकर्ता के साथ अधिगृहीत जमीन के समान स्थिति वाले भूस्वामियों को 65 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजा मिला है तो फिर उसे इस मामले में भी मुआवजा बढ़ा कर 65 रुपये प्रति वर्गगज करने का आदेश देना चाहिए था।

नोएडा प्रशासन की दलीलें खारिज कीं : ग्रेटर नोएडा प्रशासन के वकील रविंद्र कुमार ने किसानों की याचिका का विरोध करते हुए कहा, मुआवजा बढ़ाए जाने के जिस मामले का हवाला दिया जा रहा है वह दूसरे गांव का है। शीर्ष अदालत ने उनकी दलीलें खारिज करते हुए कहा, जमीन का अधिग्रहण एक साथ हुआ था। जब सुप्रीम कोर्ट अधिग्रहण के दो मामलों में 5 दिसंबर, 2016 व 17 जुलाई, 2017 को मुआवजा 65 रुपये प्रति वर्ग गज करने का आदेश दे चुका है तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट का मामला वापस रिफरेंस कोर्ट को भेजने और अंतिम फैसले का इंतजार करने का आदेश देना ठीक नहीं था।

हाई कोर्ट में जो पक्षकार नहीं थे, उन्हें भी राहत : सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे याचिकाकर्ता भी पहुंचे थे जो हाई कोर्ट में पक्षकार नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने रिफरेंस कोर्ट में धारा 28ए के तहत अर्जी दाखिल करने वाले इन लोगों के बारे में आदेश दिया है कि इनकी अर्जियों को इस आदेश को देखते हुए तीन महीने के भीतर निपटाया जाए। रिफरेंस कोर्ट इस मामले में प्राधिकरण की आपत्तियां भी सुनेगा।

लगाम

घरेलू गैस एजेंसियों की मनमानी से लोगों को मिलेगी राहत, पहले चरण में अभी एक ही कंपनी की एजेंसियों में कनेक्शन ट्रांसफर की सुविधा, धीरे-धीरे पूरी तरह से पोर्टेबिलिटी की सुविधा की जाएगी लागू

ग्राहकों को मिली रसोई गैस एजेंसी बदलने की सुविधा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सरकार ने घरेलू गैस यानी एलपीजी के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब उपभोक्ता अगर मौजूदा गैस एजेंसी की सुविधा से संतुष्ट नहीं हैं तो दूसरी एजेंसी में अपना कनेक्शन ट्रांसफर करवा सकते हैं। फिलहाल एक ही कंपनी की एजेंसी में कनेक्शन ट्रांसफर की सुविधा होगी। पहले चरण में सरकार ने चंडीगढ़, पुणे, रांची, कोयंबटूर और गुरुग्राम में यह सुविधा शुरू की है। जल्द ही पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा।

पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव तरुण कपूर ने दैनिक जागरण को बताया है कि अभी प्रायोगिक तौर पर इसे लागू किया जा रहा है ताकि एलपीजी उपभोक्ताओं की सर्विस को लेकर गैस एजेंसियां और सतर्क हो सकें। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा इस योजना को ना सिर्फ पूरे देश में लागू करने की है बल्कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो बाद में ग्राहकों को दूसरी कंपनी की एजेंसी में भी कनेक्शन ट्रांसफर करने की सुविधा होगी। उनका मानना है कि इससे गैस एजेंसियों के बीच सेवा की गुणवत्ता को सुधारने को लेकर प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी और यह ग्राहकों के लिए बेहतर कदम साबित होगा।



फाइल/इंटरनेट मीडिया

29 करोड़ उपभोक्ता, सिर्फ तीन कंपनियां

भारत में इस समय 29 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं और सेवा में सिर्फ तीन सरकारी कंपनियां हैं। सरकार को ऐसा लगता है कि इन कंपनियों के बीच सर्विस की गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर काफी सुस्ती रहती है। डिलीवरी एजेंसी के चयन की सुविधा मिलने के बाद गैस एजेंसियों के लिए ग्राहकों की शिकायतों को टालने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी।

आनलाइन बुकिंग के समय एजेंसी चुनने की सुविधा

इस नई व्यवस्था में गैस एजेंसी की कोई भूमिका नहीं होगी। ग्राहक आनलाइन गैस सिलेंडर रिफिल के समय ही यह तय कर सकेंगे कि वह किस एजेंसी से सिलेंडर लेना चाहते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि चूंकि एक ग्राहक बनाने में तेल कंपनी को काफी पैसा खर्च करने पड़ते हैं इसलिए अभी तत्काल एक कंपनी से दूसरी कंपनी की एजेंसी में जाने की इजाजत नहीं होगी। एक बार जब यह सर्विस पूरे देश में लागू हो जाएगी तो अगले चरण में अपने इलाके की किसी भी कंपनी की किसी भी एजेंसी से गैस रिफिल करवाने की छूट दी जा सकती है।

71 हजार 997 लोगों को कोरोनारोधी टीका लगा बुधवार को राजधानी में। इनमें 42 हजार 140 लोगों को टीके की पहली डोज और 29 हजार 857 लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गई।

न्यूज गैलरी

कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर हुई 98.21 फीसद

नई दिल्ली : राजधानी में बुधवार को कोरोना से मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 98.21 फीसद हो गई। 62 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। चार मरीजों की मौत हो गई। 61 मरीज स्वस्थ हुए। मृत्यु दर 1.74 फीसद पर स्थिर रही। पिछले 24 घंटे में 65 हजार 811 सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 0.09 फीसद सैंपल पाजिटिव मिले। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 14 लाख 35 हजार 671 हो गई है, जबकि 14 लाख दस हजार 66 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 25 हजार 39 हो गया है। सक्रिय मरीजों की संख्या 566 है। 171 मरीज आइसोलेशन में हैं, जबकि अस्पतालों में 322 मरीज भर्ती हैं। कोविड केयर सेंटर में 11 मरीजों का इलाज हो रहा है। दूसरी तरफ कंटेनमेंट जोन की संख्या घटकर 403 रह गई है। (जासं)

अंबेडकर अस्पताल में गड्ढे में गिरे दो कर्मचारी, एक की मौत

नई दिल्ली : दक्षिणपुरी में स्थित अंबेडकर अस्पताल में सीढ़ियों पर ग्रिल न होने के कारण अस्पताल के दो कर्मचारी 25 फुट गहरे गढ्ढे में गिरे गए। हादसे में नर्सिंग स्टाफ अमर सिंह की मौत हो गई। सुरक्षाकर्मी दीपक मेहरा घायल हो गए। लापरवाही से हुई मौत के मामले में अंबेडकर नगर थाना पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार, पुलिस को मंगलवार शाम अंबेडकर अस्पताल में हादसे की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि अस्पताल के पिछले हिस्से में बने बेसमेंट में निर्माण कार्य चल रहा है। नर्सिंग स्टाफ अमर सिंह किसी काम से यहां आए थे। इस दौरान सीढ़ियों से फिसलकर वह गड्ढे में गिर गए। उन्हें बचाने के दौरान सुरक्षाकर्मी दीपक मेहरा भी गड्ढे में गिर गए। पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया जहां डाक्टरों ने अमर सिंह को मृत घोषित कर दिया। दीपक मेहरा का इलाज चल रहा है। (जासं)

कब्रिस्तान में कब्जा, नियमों के तहत कार्रवाई का आदेश

नई दिल्ली : बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे का आरोप लगाते हुए याचिका दायर कर कार्रवाई की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार, वक्फ बोर्ड और दक्षिणी दिल्ली निगम को तलब किया है। साथ ही कहा है कि मौका मुआयना कर नियमों के तहत उचित कार्रवाई करें। अगर कब्जा और अवैध निर्माण पाया जाता है तो जगह मुक्त करवाई जाए। युवा संघर्ष समिति की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि कब्रिस्तान की जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। यहां पर खाने के सामान की दुकानें और कई दफ्तरों का निर्माण कर काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं बीएसईएस ने इन अवैध निर्माण को बिजली कनेक्शन भी दिया है। (जासं)

ड्रोन से हमले की आशंका के मद्देनजर राजधानी में अलर्ट

सतर्कता ▸ आइबी के अलर्ट करने पर दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

15 अगस्त से पहले आतंकी ड्रोन से कर सकते हैं हमला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

राजधानी में 15 अगस्त से पहले आतंकी ड्रोन से हमला कर सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो (आइबी) ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट जारी कर पूरी तरह चौकसी बरतने को कहा, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। अलर्ट में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से आतंकी दिल्ली में हमले की साजिश रच रहे हैं। असामाजिक तत्व, आतंकवादी पैराग्लाइडर के उपयोग से आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को खतरा पहुंचा सकते हैं। वे ड्रोन, हैंग ग्लाइडर, माइक्रोलाइट विमान, गर्म हवा के गुब्बारे यहां तक कि पैराजंपिंग के जरिये भी हमले की कोशिश कर सकते हैं। अलर्ट के बाद पुलिस आयुक्त बालाजी श्रीवास्तव ने पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू करते उपरोक्त सभी हवाई प्लेटफार्मों की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

त्रिकोणीय सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम : स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस ड्रोन से 360 डिग्री पर नजर रखेगी। इसके लिए त्रिकोणीय सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही अत्याधुनिक कैमरों से लैस ड्रोन के जरिये हर किसी पर नजर रखी जाएगी। उत्तरी जिले की अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अनिता राय का कहना है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वायु सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के साथ यह प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हो रहा है।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा जांच के लिए पुलिसकर्मियों की लाल किले में तैनाती दो महीने से ही है। चांदनी चौक क्षेत्र के पास और लाल किले के अंदर आंतरिक जांच की जा रही है। लाल किले की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ लगातार संपर्क में है। इस बार सुरक्षा के लिए त्रिकोणीय व्यवस्था की गई है, जिसमें दिल्ली की प्रमुख सीमाओं के साथ-साथ लाल किले की ओर जाने वाली सभी मार्गों और लाल किले के आसपास के इलाकों में बैरिकेडिंग की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद भी देर शाम तक बैरिकेडिंग रहेगी।



तिलक ब्रिज पर तैनात आरएएफ के जवान आने-जाने वाले वाहनों पर कड़ी निगरानी करते हुए। ध्रुव कुमार

50 फीसद कम रहेंगे दर्शक

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में इस बार 50 फीसद लोगों को ही आने दिया जाएगा। सामान्य तौर पर छात्रों, मेहमानों समेत 10 हजार से अधिक लोग यहां उपस्थिति होते हैं, लेकिन इस बार यह संख्या आधी रहेगी।

एम्स में तीन बच्चों की बर्ड फ्लू की जांच की गई, तीनों निगेटिव

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

एम्स में एक बच्चे की बर्ड फ्लू से मौत के बाद के पीआइसीयू में भर्ती तीन अन्य बच्चों की भी जांच कराई गई। तीनों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं, बच्चे के इलाज के दौरान संपर्क में रहे डाक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों को अपने स्वास्थ्य की निगरानी रखने के लिए कहा गया है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वायरस इंसान से इंसान में नहीं फैलता है, साथ ही अस्पताल में सभी डाक्टर एन-95 मास्क लगाकर रहते हैं और पीपीई किट पहनकर ही मरीजों के बीच जाते हैं। इसलिए इनके संक्रमित होने का खतरा नहीं है और न ही अभी तक किसी में लक्षण आए हैं।

एम्स द्वारा बर्ड फ्लू से बच्चे की मौत को लेकर बयान जारी किया गया। बयान के मुताबिक बच्चे की कोरोना और स्वाइन फ्लू (इनफ्लुएंजा) की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसका सैंपल पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट आफ वायरोलाजी (एनआइवी) की लैब में भेजा गया था। एनआइवी की रिपोर्ट में बच्चे में एवियन इनफ्लुएंजा (एच5एन1) बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। एम्स द्वारा यह भी बताया गया कि बच्चे का पहले से ही एम्स में कैंसर का इलाज चल रहा था। उसे यहां कीमोथेरेपी के लिए लाया जाता था। निमोनिया होने के बाद दो जुलाई को यहां भर्ती किया गया। सांस लेने में तकलीफ के चलते दो दिन एचडीयू (उच्च निर्भरता इकाई) में रखा गया। फेफड़ों में संक्रमण बढ़ने से हालत गंभीर होने पर बच्चे को बाल चिकित्सा गहन देखभाल इकाई में शिफ्ट किया गया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

बर्ड फ्लू को लेकर चिड़ियाघर प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता

जासं, नई दिल्ली : देश में पहली बार बर्ड फ्लू से बच्चे की मौत होने के बाद चिड़ियाघर प्रशासन ने और अधिक सतर्कता बढ़ा दी है। हालांकि पशुपालन विभाग और अन्य एजेंसियों की ओर से अब तक चिड़ियाघर प्रबंधन को कोई निर्देश नहीं दिए गए। इसके बावजूद पक्षियों के बाड़े के बाहर पहले की तरह अब भी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है।

चिड़ियाघर के अधिकारियों का कहना है कि एक बच्चे की मौत होने से इस बात का अभी कहना मुश्किल होगा कि कि बर्ड फ्लू का खतरा पक्षियों पर भी मंडरा रहा है। कई बार अंडे और किसी पक्षी के मांस के खाने के कारण भी बर्ड फ्लू का संक्रमण व्यक्ति के शरीर में जा सकता है। हालांकि इस पर अभी शोध किया जाना बाकी है। वहीं पक्षी बच्चे की मौत के बाद भी चिड़ियाघर के पक्षियों के बाड़े के बाहर छिड़काव किया जा रहा है। चिड़ियाघर के निदेशक रमेश कुमार पांडेय ने बताया कि चिड़ियाघर को अभी इस मामले को लेकर कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं। हालांकि आदेशों का इंतजार किया जा रहा है। उससे पहले ही चिड़ियाघर प्रबंधन सभी तरीके की सतर्कता बरत रहा है।

पड़ोस की चिकन शाप से संक्रमित हुआ था बच्चा!

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में बर्ड फ्लू (एवियन इंफ्लूएंजा) के बेहद घातक स्ट्रेन एच5एन1 के संक्रमण के कारण मरा 11 वर्षीय बच्चा ब्लड कैंसर से पीड़ित था और उसका इलाज चल रहा था। सामने आया है कि उसके घर के पास चिकन शाप है, जहां राजस्थान से मुर्गे लाए जाते हैं। अंदेशा है कि इसी चिकन शाप से बच्चा बर्ड फ्लू की चपेट में आया।

गुरुग्राम के गांव चकरपुर रह रहे 11 वर्षीय बच्चे का परिवार मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला है। यहां उसके माता-पिता, भाई और नानी रहती हैं। स्वजन का कहना है कि बच्चे को ब्लड कैंसर था, जिसका एम्स में इलाज चल रहा था। एक जून से उसे कीमोथेरेपी के लिए ले जाया जा रहा था। आठ जुलाई को तबीयत ज्यादा खराब होने पर उसे एम्स में ही भर्ती कर लिया गया। वहां 11 जुलाई को उसकी मौत हो गई। जानकारी सामने आई है कि बच्चे के परिवार के साथ रहने वाली एक महिला पास में मीट की दुकान में काम करती है। वह बच्चे की नानी की सहेली है और साथ ही रह रही है। घर के साथ ही चिकन शाप है, जहां के लिए राजस्थान के पोल्ट्री फार्म से मुर्गे लाए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग इस नतीजे पर पहुंचा कि इस चिकन शाप से ही लड़का संक्रमित हुआ।

दिल्ली से आई टीम ने परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य की जांच की और बचाव के लिए दवा दी है। उनके नमूने भी लेकर जांच के लिए भेजे गए। आसपास के इलाके में लोगों के स्वास्थ्य जांच की जा रही है, लेकिन फिलहाल किसी में बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं मिले हैं। बुधवार को परिवार के संपर्क में रहने वाले 34 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई।

'तारीख पर तारीख...' चिल्लाते हुए कोर्ट में की तोड़फोड़, जेल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- 2016 से लंबित मामले में सुनवाई में देरी से था नाराज
- अगली सुनवाई की तारीख पता नहीं चलने पर खो बैठा आपा

बालीवुड अभिनेता सन्नी देओल के प्रसिद्ध डायलाग 'तारीख पर तारीख...' को लेकर अक्सर चर्चाएं होती हैं। लेकिन, दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में लोग एक अलग ही घटना से रूबरू हुए। सुनवाई में देरी से नाराज एक शख्स ने जोर-जोर से 'तारीख पर तारीख...' डायलाग चिल्लाते हुए न सिर्फ हंगामा खड़ा कर दिया, बल्कि तोड़फोड़ कर दी। उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

आरोपित रमेश शास्त्री पार्क स्थित झुग्गी बस्ती में रहता है। झुग्गी को लेकर उसका किसी से विवाद चल रहा है और मामला 2016 से कोर्ट में लंबित है। कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते कोर्ट में केवल जरूरी मामलों की वर्चुअल सुनवाई चल रही है। ऐसे में रमेश को पता ही नहीं चल पा रहा था कि उसके मामले में अगली सुनवाई कब होगी। वह तारीख पता करने के लिए 17 जुलाई को कड़कड़डूमा कोर्ट गया था। आरोप है कि कक्ष संख्या 66 में पहुंच कर उसने तारीख की जानकारी लेने का प्रयास किया। थका देने वाली अदालती कार्यवाही से वह परेशान चल रहा था। तारीख के बारे में पता नहीं चलने पर वह आपा खो बैठा। गुस्से में आकर उसने 'तारीख पर तारीख...' डायलाग चिल्लाते हुए वहां रखा कंप्यूटर और फर्नीचर तोड़ने लगा। उसका गुस्सा देख कर कुछ देर के लिए कोर्ट का स्टाफ सहम गया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। बाद में रमेश ने वहां से भागने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ पुलिस ने भादंसं की धारा 186 (लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने), धारा 353 (लोक सेवक पर हमला करने या आपराधिक बल का उपयोग करने) और धारा 427 (शरारत करने) और धारा 506 (धमकी देने) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

होटल में हिस्सा देने के नाम पर ठग ली पूरी संपत्ति

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पांच सितारा होटल में हिस्सेदारी देने का झांसा देकर एक एनआरआइ कारोबारी की संपत्ति ठगने के आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित राज कुमार खत्री विकासपुरी के लक्ष्मी विहार अपार्टमेंट में रहता है। उसने खुद को एक पांच सितार होटल का मालिक बता कर फर्जी कागजात के जरिये पीड़ित को झांसा दिया था।

मूलरूप से पंजाब के जालंधर से संबंध रखने वाले 78 वर्षीय सोहन लाल जिरह कनाडा में कारोबार करते हैं। 20 जनवरी को आर्थिक अपराध शाखा को दी शिकायत में उन्होंने बताया कि 2011 में राज कुमार खत्री आल इंडिया हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष और त्रिमूर्ति इंपेक्स का मालिक बन उनसे मिला था। इस दौरान फर्जी कागजात के जरिये उसने दावा किया कि वह आइजीआइ एयरपोर्ट के पास एयरो सिटी में एक निर्माणाधीन पांच सितारा होटल का मालिक है। उसने बताया कि इस होटल की कुल कीमत 1,500 करोड़ रुपये है। आरोपित ने पीड़ित को होटल में हिस्सेदार बनाने का झांसा दिया और उनकी कनाडा स्थित सभी 11 संपत्तियों को अपने नाम करा लिया।

तिहाड़ में कैदी की हत्या का आरोप, सीबीआइ जांच का दिया आदेश

सुशील गंभीर, नई दिल्ली

- न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने मृतक की मां की याचिका को किया मंजूर
- कुछ विचाराधीन कैदियों ने क्रिकेट बैट से की थी पिटाई

लूट के मामले में तिहाड़ जेल में विचाराधीन कैदी की मौत के मामले की अब सीबीआइ जांच होगी। दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने मृतक की मां की याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका में हत्या का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने भी हत्या का केस दर्ज किया था, लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन ने मृतक के शरीर पर किसी भी तरह की चोट से इन्कार करते हुए रिपोर्ट दायर की थी।

दिल्ली पुलिस ने श्रीकांत उर्फ पप्पू नाम के व्यक्ति को लूट के मामले में गिरफ्तार किया था। 13 जून, 2019 से वह तिहाड़ जेल में बंद था। याचिका में कहा गया है कि 14 मई, 2021 को श्रीकांत की तबीयत खराब होने पर डीडीयू अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी। मृतक की फोटो और वीडियो देखने पर पता चलता है कि उसके शरीर पर चोट के गहरे निशान थे। इसके अलावा मौत से एक दिन पहले श्रीकांत ने अपनी बहन को फोन कर कहा था कि उसे जेल में मारने की कोशिश हो रही है। श्रीकांत को कोविड महामारी के चलते अंतरिम राहत भी नहीं दी गई थी।

इस याचिका पर हाई कोर्ट ने जेल प्रबंधन से जवाब मांगा था। इसमें कहा गया था कि मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन न्यायिक हिरासत में मौत होने के चलते हरि नगर थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया है।

हाई कोर्ट ने पाया कि जेल प्रशासन की तरफ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट दायर नहीं की गई है। वहीं, जेल अधिक्षक की रिपोर्ट के मुताबिक घटना वाली सुबह करीब सात बजे वार्डर ने बैरक नंबर चार से किसी के चीखने की आवाज सुनी थी। जब जेल कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो पाया कि अरुण, आकाश, हनी, गनपत सहित कई अन्य विचाराधीन कैदी श्रीकांत को क्रिकेट बैट से मार रहे थे और उसके शरीर से खून बह रहा था।



हाई कोर्ट ने दिया निर्देश। फाइल

फुटेज सहेजने का आदेश

हाई कोर्ट ने पाया कि जेल प्रशासन अपनी एक रिपोर्ट में कह रहा है कि श्रीकांत को ऐसी चोट नहीं लगी थी कि मौत हो जाए। वहीं, याचिकाकर्ता गहरे घावों का दावा कर रही हैं। ऐसे में इस मामले की जांच सीबीआइ को ही करनी चाहिए। जेल प्रशासन को आदेश दिया गया है कि सभी सीसीटीवी फुटेज और फोटो सहेज लिए जाएं। सीबीआइ इस संबंध में केस दर्ज कर जांच शुरू करे और 29 सितंबर को प्रगति रिपोर्ट दाखिल करे।



सूना रहा परिसर...

कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने की वजह से इस वर्ष मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं मिली। बुधवार को ईद-उल-अजहा (बकरीद) पर प्रसिद्ध जामा मस्जिद परिसर में सन्नाटा पसरा है। यहां चुनिंदा लोगों को ही नमाज की इजाजत मिली थी। पुलिस ने भी मस्जिद के आसपास सुरक्षा के काफी कड़े प्रतिबंध किए थे। एएनआइ

दिल्ली दंगा : आरोपित छात्रों की रिहाई के विरोध वाली याचिका सुनेगा सुप्रीम कोर्ट

- हाई कोर्ट से राहत पाए तीनों छात्रों को नोटिस किया जारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : दिल्ली के दंगा मामलों में आरोपित तीन छात्रों को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के खिलाफ दायर दिल्ली पुलिस की याचिका की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मामले में हाई कोर्ट द्वारा आतंकवाद निरोधी कानून यूएपीए की व्याख्या पर शीर्ष न्यायालय 18 जून को नाखुशी जाहिर कर चुका है। साफ कर चुका है कि जमानत देने के हाई कोर्ट के इस आदेश को अन्यत्र कहीं नजीर के रूप में पेश न किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है। साथ ही जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्रा नताशा नरवल, देवांगना कलिता और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा के लिए नोटिस जारी किया है। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश का क्रियान्वयन स्थगित करने से इन्कार कर दिया है अर्थात तीनों छात्रों की जमानत बरकरार रहेगी और वे जेल से बाहर ही रहेंगे। मामले में दायर दिल्ली पुलिस की याचिका पर जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ गुरुवार को सुनवाई करेगी।

इस मामले में जून में सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उस पर चर्चा की थी। मेहता ने कहा था कि मामले में हाई कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के प्रविधानों के उलट व्याख्या कर आरोपितों को जमानत दी है। मेहता के अनुसार मामला महत्वपूर्ण है और नजीर के तौर पर इसका फायदा लेने का प्रयास पूरे देश में किया जा सकता है। इससे कानून व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

मेहता ने कहा था कि दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये दंगे ऐसे समय हुए थे, जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए थे और दिल्ली में थे। यह भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश थी। इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। हाई कोर्ट ने तीनों छात्रों को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए उन पर यूएपीए की धारा लगाए जाने पर सवाल उठाया था।

गौतमबुद्ध नगर जल्द करेगा पीएम, सीएम की अगवानी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास सितंबर के पहले सप्ताह में संभावित है। केंद्र सरकार ने प्रदेश से उन परियोजनाओं की जानकारी मांगी थी, जो शिलान्यास या लोकार्पण के लिए तैयार हैं। प्रदेश सरकार की ओर से भेजी सूची में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अगले माह गौतमबुद्ध नगर का दौरा कर सकते हैं।

विधानसभा चुनाव को लेकर अगले कुछ माह गौतमबुद्ध नगर में वीवीआइपी की गहमागहमी रहेगी। जिले में कई परियोजनाएं हैं, जिनका शिलान्यास होना है। इसमें सबसे प्रमुख नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार अपने स्तर से मेडिकल डिवाइस पार्क भी विकसित करने जा रही है। इनके शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौतमबुद्ध नगर आएंगे।

सितंबर में हो सकता है एयरपोर्ट का शिलान्यास : नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू कराने के लिए अधिकारी जुटे हैं। अधिगृहीत जमीन से ग्रामीणों के विस्थापन का कार्य तकरीबन पूरा हो चुका है। नागरिक उड्डयन विभाग ने अधिगृहीत जमीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड नियाल को लीज भी कर दी है। सितंबर के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का शिलान्यास कर सकते हैं। इसकी तारीख की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी होगा दौरा : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गौतमबुद्ध नगर का दौरा कर सकते हैं। नोएडा एयरपोर्ट के शिलान्यास की तैयारी का जायजा लेने के अलावा मुख्यमंत्री प्राधिकरण की परियोजनाओं का भी शिलान्यास कर सकते हैं। मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास भी जल्द होने की संभावना है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रदेश सरकार मेडिकल डिवाइस पार्क को जल्द से जल्द आगे बढ़ाना चाहती है।

अध्ययन

जामिया, बीएचयू के शोधार्थियों ने लाकडाउन में यमुना के सतह के जल का किया अध्ययन, नौ जगहों पर किए अध्ययन में दो जगह पानी नहाने लायक पाया गया

लाकडाउन में यमुना में प्रदूषण स्तर हुआ था कम

संजीव कुमार मिश्र, नई दिल्ली

जामिया मिल्लिया इस्लामिया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने पिछले वर्ष लाकडाउन (मार्च से मई 2020) के दौरान यमुना के जल का अध्ययन किया। नौ जगहों से लिए गए जल के नमूनों का प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया गया। इनमें से पल्ला व सूरघाट पर पानी नहाने लायक पाया गया था। आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद शोधार्थियों ने पाया कि यमुना के जल में प्रदूषण का स्तर घटा। इसके पीछे बड़ी वजह जल की अधिक उपलब्धता व औद्योगिक इकाइयों का बंद होना बताया गया है। अध्ययन में दावा किया गया है कि लाकडाउन के दौरान विभिन्न मानकों के आधार पर दिल्ली में यमुना के जल में 21 फीसद प्रदूषण कम दर्ज किया गया। इसके अलावा शोध में दावा किया गया है कि इस दौरान यमुना में जल की उपलब्धता पांच गुना तक बढ़ी थी।

पीएच का स्तर : लाकडाउन के दौरान पीएच (पावर आफ हाइड्रोजन) 7.24 से 8.06 के बीच मापा गया, जबकि औसत 7.26 रहा। लाकडाउन से पहले सीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक यह 8.7 तक था। लाकडाउन के दौरान सूरघाट पर सर्वाधिक पीएच 8.6 रिकार्ड किया गया, जबकि सबसे कम 7.24 खजूरी पुल पर मापा गया। जल का पीएच मान यह इंगित करता है कि जल कठोर कितना अम्लीय है।

डिजाल्व आक्सीजन का स्तर : जब हानिकारक रसायनों की मात्रा अधिक हो जाती है तो डीओ (डिजाल्व आक्सीजन) लेवल कम हो जाता है। दरअसल, यह जल में विलीन आक्सीजन की वह मात्रा है जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। जल में डीओ की मात्रा आठ मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाती है तो ऐसे जल को प्रदूषित माना जाता है। जैसे-जैसे यह मात्रा कम होती है, प्रदूषण का स्तर गंभीर होता चला जाता है। लाकडाउन के दौरान पल्ला घाट पर यमुना के जल में डीओ की मात्रा 8.3, आइटीओ पर 4.1, निजामुद्दीन पर 3.5 मिलीग्राम, आगरा कैनाल पर 4.2, ओखला बैराज पर चार मिलीग्राम पाया गया।



सोनिया विहार यमुना पुस्ता के पास यमुना में मछलियां पकड़ते मछुआरे। ध्रुव कुमार

इन जगहों पर किया गया अध्ययन

पल्ला घाट, सूरघाट, आइटीओ घाट, निजामुद्दीन, ओखला बैराज, खजूरी पुल, कुदेशिया घाट, आगरा कैनाल, शाहदरा ड्रेन

अध्ययन में इनकी पड़ताल की गई

- केमिकल आक्सीजन डिमांड (सीओडी)
- बायोकेमिकल आक्सीजन डिमांड (बीओडी)
- डिजाल्व आक्सीजन (डीओ)
- टोटल डिजाल्व सालिड (टीडीएस)
- इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी (ईसी)
- पीएच (पावर आफ हाइड्रोजन)
- तापमान

इन जगहों पर कम हुआ प्रदूषण

स्थान	प्रदूषण में कमी फीसद में
निजामुद्दीन	20
ओखला बैराज	33
आगरा कैनाल	26
शाहदरा ड्रेन	18

लाकडाउन के दौरान दिल्ली में यमुना का बीओडी

यह आक्सीजन की वह मात्रा है जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। बीओडी (बायोकेमिकल आक्सीजन डिमांड) लेवल में असंतुलन जलीय जीवों के लिए खतरनाक है। बीओडी की मात्रा एक मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। लाकडाउन से पहले शोध वाले स्थानों पर बीओडी लेवल तीन मिलीग्राम से ज्यादा था। शोध में पाया गया कि लाकडाउन के दौरान शाहदरा ड्रेन के पास यमुना जल में बीओडी लेवल में 66 फीसद तक की गिरावट देखी गई। इसी तरह सूरघाट और आगरा कैनाल पर लाकडाउन से पहले के मुकाबले क्रमशः 27 और 33 फीसद गिरावट रिकार्ड की गई। हालांकि, लाकडाउन के दौरान भी यह कहीं पर तय मात्रा से कम नहीं पाया गया।

27 जुलाई को दो दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन। इस दौरान उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने भारतीय समकक्ष जयशंकर से मिलने की संभावना है।

'सीएए, एनआरसी से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं'

साफ संदेश ▸ राजनीतिक लाभ के लिए सीएए-एनआरसी को हिंदू-मुसलमान का विषय बना दिया, यह हिंदू-मुसलमान का विषय नहीं

गुवाहाटी, प्रेट्र : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का हिंदू-मुस्लिम विषय से कोई लेना-देना नहीं है। इनसे किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन दोनों मुद्दों को सांप्रदायिक रूप देने में लगे हैं।

दो दिन के असम दौरे पर यहां पहुंचे संघ प्रमुख ने कहा कि सीएए किसी भारत के नागरिक के खिलाफ कानून नहीं है। भारत के मुसलमानों को नागरिकता कानून के कारण कोई नुकसान नहीं होगा। बुधवार को यहां एक कार्यक्रम में पुस्तक 'सिटिजनशिप डिबेट ओवर एनआरसी एंड सीएए-असम एंड द पालिटिक्स आफ हिस्ट्री' के विमोचन के बाद संघ प्रमुख ने कहा कि आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री (जवाहरलाल नेहरू) ने कहा था कि अल्पसंख्यकों का ध्यान रखा जाएगा। अब तक ऐसा ही किया गया है। हम आगे भी ऐसा ही करना जारी रखेंगे।

▸ **नेहरू ने कहा था- अल्पसंख्यकों का रखा जाएगा ध्यान, अब तक ऐसा ही किया गया है, हम आगे भी ऐसा ही जारी रखेंगे**

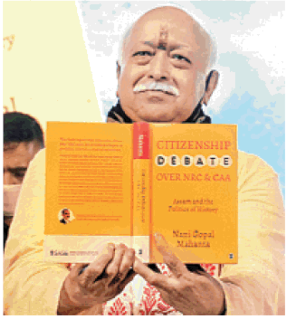
उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून पड़ोसी देशों में उत्पीड़न का शिकार अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करेगा। हम आपदा के समय इन देशों में बहुसंख्यक समुदायों की भी मदद करते हैं, इसलिए अगर कुछ ऐसे लोग हैं, जो उत्पीड़न और डर के कारण हमारे देश में आना चाहते हैं, तो हमें निश्चित रूप से उनकी सहायता करनी होगी। संघ प्रमुख ने एनआरसी को लेकर कहा कि सभी देशों को यह जानने का अधिकार है कि उनके नागरिक कौन हैं। यह मामला राजनीतिक क्षेत्र में है, क्योंकि इसमें सरकार शामिल है। लोगों का एक वर्ग इन दोनों मामलों को सांप्रदायिक रूप देकर राजनीतिक लाभ लेना चाहता है।

आइएएनएस के मुताबिक, संघ प्रमुख ने कहा कि 1930 से ही मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि की सुनियोजित योजना चल रही है। वे प्रभावकारी ताकत बनना चाहते हैं। ऐसा पंजाब, बंगाल और असम में हुआ। इन क्षेत्रों में वे बहुसंख्यक होना चाहते हैं ताकि उनकी शर्तों पर चीजें हों। ऐसा ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में हुआ। संघ प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान टूट गया और संकट में है।

उन्होंने कहा कि महाभारत काल से ही असम में बाहरी लोगों का इतिहास रहा है, लेकिन अवैधरूप से रह रहे लोगों से इतना डर कभी नहीं रहा। सभी समुदायों को मिलजुल कर रहना चाहिए, उनके मध्य डर नहीं होना चाहिए। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य इसे सत्ता से हासिल करना नहीं, बल्कि धर्म, सनातन और मानवता से है जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

ये भी बोले भागवत

- संघ का काम करने वाले हम सब लोग, हमारे मन में सबके भले की ही भावना रहती है और सत्य पर चलने का संकल्प।
- हमें दुनिया की किसी भाषा से, किसी धर्म से, किसी बात से परहेज नहीं है, क्योंकि हमारी दृष्टि वसुधैव कुटुंबकम की है।
- हमारे यहां पहले से ही पूजा की स्वतंत्रता है, कुछ बिगड़ता नहीं हमारा। हम भगवान को एक रूप में देखते हैं, आप किसी दूसरे रूप में देखते हैं ठीक है। अपनी भक्ति में हम पक्के हैं, अपनी भक्ति में आप भी पक्के रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं।
- सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, ये बातें दुनिया से हमको सीखनी नहीं हैं, ये हमारी परंपरा में, हमारे खून में हैं और इसलिए सबसे अधिक प्रामाणिकता से हमारे देश ने उसको जीवंत रखा।
- पहली बार मेरी प्रणब दा से भेंट हुई थी। उन्होंने ही कहा कि धर्मनिरपेक्षता को लेकर चर्चा चल रही है। धर्मनिरपेक्षता हमें कौन सिखाएगा। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है।
- ये हमारी भोग भूमि नहीं है। ये तो हमारी कर्मभूमि है, कर्तव्य की भूमि है। यहां रहने वाले प्रत्येक का इस भूमि के प्रति, समाज के प्रति कर्तव्य है। वह उस संस्कृति ने निर्धारित कर दिया है। वह किसी पंथ, संप्रदाय और पूजा पर आधारित नहीं है।



असम के गुवाहाटी में बुधवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पुस्तक 'सिटिजनशिप डिबेट ओवर एनआरसी एंड सीएए-असम एंड द पालिटिक्स आफ हिस्ट्री' का विमोचन करते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख डा. मोहन भागवत। एएनआइ

भारत जल्द खरीद सकता है 21 मिग-29 लड़ाकू विमान, रूस ने दिया प्रस्ताव

जुकोवस्की, एएनआइ : भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों का बेड़ा जल्द ही और शक्तिशाली होने जा रहा है। रूस ने भारत को 21 मिग-29 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव सौंपा है।

रूस के फेडरल सर्विस फार मिलिट्री-टेक्नीक कारपोरेशन के प्रवक्ता वेलेरिया रेशेतनिकोवा ने इस बारे में मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय एयरोस्पेस शो से इतर कहा, 'भारतीय वायुसेना स्टाफ के पास वर्ष 2021 में 21 विमानों की आपूर्ति के लिए निविदा प्रस्ताव पहुंच चुका है। रूस ने भारतीय साझेदार को वाणिज्यिक प्रस्ताव सौंप दिया है और उस पर विचार किया जा रहा है।'

21 मिग-29 की खरीद के प्रस्ताव को मिली थी मंजूरी : पिछले साल रक्षा खरीद मामलों की भारतीय परिषद ने 21 मिग-29 लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। रूसी संघीय सेवा ने फरवरी में कहा था कि भारत सरकार ने भी विमानों की खरीद के पक्ष में निर्णय लिया है। मास्को क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय एयरोस्पेस शो का आयोजन 21-25 जुलाई तक हो रहा है।

ईरान के मुद्दे पर अमेरिका को दो टूक जवाब दे सकता है भारत

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

रणनीति

▸ **अफगानिस्तान के हालात देख दोनों देशों में बढ़ा संपर्क, जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री जरीफ से की बात**

अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद बदले हालात और अपने रणनीतिक हितों पर संभावित खतरे को देखते हुए भारत ने ईरान के साथ संबंधों को लेकर साफ संकेत दे दिया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को अपने ईरानी समकक्ष जवाद जरीफ से टेलीफोन पर लंबी बातचीत की। बातचीत मुख्य तौर पर अफगानिस्तान के हालात और द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत बनाने पर केंद्रित रही। दोनों नेताओं के बीच पिछले एक पखवाड़े में यह दूसरी वार्ता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात कि अगले हफ्ते जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन भारत आने वाले हैं, यह बातचीत तब हुई है। संकेत साफ है कि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान के साथ पिछले तीन वर्षों से अपने रिश्तों को लेकर उदासीन रहे भारत का रवैया बदलेगा। जानकार बताते हैं कि केंद्र सरकार अपनी तेल कंपनियों को ईरान से क्रूड आयल खरीदने की इजाजत देने पर भी विचार कर रही है।

अफगानिस्तान में तालिबान के तेज होते हमलों को देखते हुए ईरान की भूमिका मौजूदा परिवेश में अहम हो गई है। ईरान लगातार तालिबान के एक बड़े धड़े के साथ न सिर्फ संपर्क में है, बल्कि अपने स्तर पर अफगान सरकार और तालिबान के बीच शांति बैठकें भी करवा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान पोषित तालिबानी आतंक का भारत व ईरान विरोध करते रहे हैं। जिस तरह भारत को डर है कि तालिबान का शासन कश्मीर में समस्या पैदा कर सकता है, उसी तरह का डर ईरान को भी है। पाकिस्तान पोषित तालिबानी आतंकियों ने पहले भी ईरान को परेशान किया है।


एस. जयशंकर। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

ईरान भी भारत की अहमियत समझ रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर दो हफ्ते पहले रूस की यात्रा के बीच में ईरान पहुंचे थे और वहां के नवनियुक्त राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी से मुलाकात की थी। राइसी की किसी भी दूसरे देश के विदेश मंत्री से यह पहली मुलाकात थी। जानकारों के मुताबिक, तेहरान में विदेश मंत्री जरीफ के साथ बैठक में जयशंकर ने भारत की तरफ से ईरान में बनाए जा रहे चाबहार पोर्ट को लेकर पूरा समर्थन जताया था। तालिबान के सत्ता में आने की आशंका के मद्देनजर जानकार बताते हैं कि इससे भारत की चाबहार परियोजना की प्रगति प्रभावित हो सकती है। भारत इस पोर्ट को अफगानिस्तान के अंदरूनी हिस्से से रेल व सड़क मार्ग से जोड़ने पर काम कर रहा है। साथ ही भारत की योजना यहां एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की भी है। अफगानिस्तान की अस्थिरता इन निवेश योजनाओं पर असर डाल सकती है, जिसकी चिंता ईरान को भी है।

ईरान को लेकर अमेरिका के रवैये में नरमी आई है, लेकिन भारत के लिए फिलहाल अपने इस ऐतिहासिक मित्र देश के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को नए सिरे से पटरी पर लाना अहम है। जानकारों का कहना है कि पहले ईरान के नए राष्ट्रपति से मुलाकात और अब विदेश मंत्री जरीफ से बातचीत कर भारत ने अपना मत स्पष्ट कर दिया है। देखना होगा कि ईरान से क्रूड आयल (कच्चा तेल) खरीद पर भारत कब फैसला करता है। वर्ष 2018-19 तक भारत ईरान से क्रूड आयल खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश रहा है। उसके बाद अमेरिका के नेतृत्व में लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से भारतीय तेल कंपनियों ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया है। यह न सिर्फ ईरान के लिए बड़ा आर्थिक झटका है, बल्कि भारत के लिए भी आर्थिक दबाव वाला फैसला है, क्योंकि ईरान हमेशा काफी सहूलियत वाली शर्तों पर भारत को क्रूड आयल बेचता रहा है।

एनएसओ ग्रुप के खिलाफ जांच का अध्ययन कर रहा इजरायली रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, आइएएनएस : इजरायल के रक्षा मंत्री बेनी गेंट्ज ने कहा कि एनएसओ ग्रुप के खिलाफ जांच का रक्षा मंत्रालय अध्ययन कर रहा है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब यह बात उजागर हुई है कि इजरायली साइबर कंपनी पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए अपने स्पाइवेयर विदेशी सरकारों को बेचती रही है।


बेनी गेंट्ज
फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

तेल अवीव यूनिवर्सिटी में आयोजित साइबर वीक में गेंट्ज ने किसी कंपनी का नाम लिए बिना कहा, 'कुछ इजरायली साइबर कंपनियों द्वारा विकसित प्रणालियों के इस्तेमाल से संबंधित हालिया प्रकाशनों के बारे में हमें पता है।' रविवार को पैगासस प्रोजेक्ट से पता चला था कि अजरबैजान, बहरीन, मैक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरब, हंगरी, भारत और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई देशों की सरकारों द्वारा निशाना बनाए गए लोगों के फोन में एनएसओ (पैगासस) द्वारा बेचे गए स्पाइवेयर की पहचान हुई थी। इस जांच को एमनेस्टी इंटरनेशनल के प्रायोजन और पेरिस स्थित जर्नलिज्म नानप्रोफिट फारबिडेन स्टोरीज के नेतृत्व में 17 मीडिया संगठनों ने अंजाम दिया था। इसके केंद्र में 50 हजार फोन नंबरों की लीक हुई एक सूची थी जो पत्रकारों, वरिष्ठ राजनीतिज्ञों और कारोबारी लोगों से जुड़ी थी।

आक्सीजन की कमी से मौत के मुद्दे पर राउत बोले, केंद्र झूठ बोल रहा

नई दिल्ली, एएनआइ : कोरोना की दूसरी लहर में आक्सीजन की कमी से कोई मौत रिपोर्ट नहीं होने संबंधी केंद्र सरकार के बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत ने बुधवार को केंद्र पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। वहीं, शिवसेना-कांग्रेस और राकांपा गठबंधन की महाराष्ट्र सरकार का अभी भी कहना है कि राज्य में आक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई।

राउत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं हैं। इस बयान को सुनने के बाद उन परिवारों पर क्या बीतेगी, जिन्होंने आक्सीजन की कमी से अपने प्रियजन को खोया है। सरकार के खिलाफ मामला दाखिल किया जाना चाहिए। वे झूठ बोल रहे हैं।' उन्होंने कहा कि दूसरी लहर में जिनके स्वजन की आक्सीजन की कमी से मौत हुई है, उन्हें केंद्र सरकार को कोर्ट में लेकर जाना चाहिए। केंद्र सरकार सच से भाग रही है।

पेगासस के मुद्दे पर उन्होंने कहा, 'विपक्ष ने संयुक्त संसदीय समिति और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग की है। अगर रविशंकर प्रसाद विपक्ष में होते तो वह भी यही मांग करते। सच उजागर होने दीजिए। अगर कुछ छिपाने के लिए नहीं है तो आप डर क्यों रहे हैं?' दूसरी तरफ, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, 'हमने कभी नहीं कहा कि राज्य में आक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हुई। उनमें से कइयों को अन्य बीमारियां थीं। आक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई।'

▸ **लेकिन महाराष्ट्र सरकार अपने रुख पर कायम, कहा- आक्सीजन की कमी से राज्य में नहीं हुई कोई मौत**


लगाए आरोप : संजय राउत।
फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

दूसरी लहर में हुईं 50 लाख मौतें : राहुल

आइएएनएस के मुताबिक, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को ट्वीट कर कहा, सच यह है कि कोरोना की दूसरी लहर में भारत सरकार के गलत फैसलों की वजह से हमारे 50 लाख बहनों-भाइयों और माता-पिता की मौत हुई। इस ट्वीट के साथ उन्होंने यह दावा करती हुई अमेरिकी थिंकटैंक सेंटर फार ग्लोबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट भी टैग की। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, 'अपने प्रियजन को खोने वालों के आंसुओं में सब कुछ दर्ज है।'

कोरोना वर्ष में आक्सीजन निर्यात 700 फीसद बढ़ाने से हुई मौतें : प्रियंका

एएनआइ के मुताबिक, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि महामारी के साल में सरकार ने आक्सीजन का निर्यात 700 फीसद बढ़ा दिया था, इस वजह से मौतें हुईं। सरकार ने आक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए टैंकरों का प्रबंध भी नहीं किया था।

आक्सीजन की कमी से आंध्र प्रदेश में 30 की मौत हुई : टीडीपी

एएनआइ के मुताबिक, तेलुगु देसम पार्टी (टीडीपी) के प्रवक्ता के. पट्टाभिराम ने दावा किया कि कोरोना की दूसरी लहर में आंध्र प्रदेश में आक्सीजन की कमी से 30 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाने की वजह से ये मौतें हुईं। वहीं, कांग्रेस ने राज्य में करीब 50 लोगों के मरने का दावा किया।

सीबीएसई ने 12वीं का परिणाम तैयार करने का बढ़ाया समय

जासं, नई दिल्ली

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम तैयार करने का समय बढ़ा दिया है। अब स्कूल 22 के बजाय 25 जुलाई को शाम पांच बजे तक परिणाम सीबीएसई को सौंप सकेंगे। दरअसल, अत्यधिक दबाव के कारण शिक्षक परिणाम तैयार करने में त्रुटियां कर रहे थे।

सीबीएसई ने बुधवार को जारी सर्कुलर में कहा कि परीक्षा परिणाम तैयार करने की अंतिम तारीख नजदीक आने से शिक्षक तनाव में आ रहे हैं और त्रुटियां कर रहे हैं। परिणाम सौंपने के बाद गलतियों को सही करने के लिए अनुरोध भेज रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मालूम हो कि कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाएं रद कर दी थीं। वैकल्पिक मूल्यांकन नीति के जरिये परीक्षा परिणाम तैयार किए जा रहे हैं।

16 अगस्त से होंगी स्वयंपाठी छात्रों की परीक्षाएं : सीबीएसई ने 10वीं-12वीं के स्वयंपाठी छात्रों की परीक्षा की संभावित तिथि की घोषणा कर दी है, ये परीक्षाएं 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच आयोजित होंगी। जल्द विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा। सीबीएसई ने कहा कि नियमित छात्रों का परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए मूल्यांकन प्रणाली तैयार की गई है, लेकिन प्राइवेट छात्रों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं बनाई गई है। स्वयंपाठी छात्र वह हैं, जो बीते वर्ष नियमित थे, लेकिन परीक्षा में फेल हो गए और सुधार के लिए परीक्षा दे रहे हैं, साथ ही दिल्ली पत्राचार बोर्ड से बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र भी स्वयंपाठी श्रेणी में आते हैं। सीबीएसई के मुताबिक काफी विचार विमर्श के बाद परीक्षा कराने पर सहमति बनी है।

'देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेल रही कांग्रेस'

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

पेगासस जासूसी विवाद में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए उनकी मानसिकता को देश विरोधी बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेल रही है।

विपक्षी नेताओं समेत कई नामी-गिरामी लोगों की जासूसी कराने के मामले को लेकर चल रहे हंगामे के बीच रूपाणी ने कहा है कि विपक्ष की मानसिकता ही देश विरोधी है। संसद सत्र से ठीक पहले जासूसी मामले को उछालना महज संयोग नहीं है। सत्ता से बेदखल कांग्रेस सत्ता के लिए तड़प रही है। राफेल, कृषि कानून या सेना की सर्जिकल स्ट्राइक, हर मामले में कांग्रेस ने नकारात्मक व देश विरोधी भूमिका निभाई है। देश की जनता द्वारा नकार दी गई कांग्रेस सत्ता हासिल करने के लिए तड़प रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों का परिचय संसद के सदस्यों से करा रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने कार्यवाही ठप कर दी। उन्होंने कहा कि 2013 में संप्रग सरकार ने 9,000 फोन व 500 ईमेल की जासूसी कराने की बात स्वीकार की थी। राजस्थान में कांग्रेस सरकार अपने ही मंत्रियों व विधायकों के फोन टेप कराती है। भारत में पेगासस साफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं हुआ है।

संभव है मेरी सरकार गिराने में भी हुआ हो पेगासस का उपयोग : कमल नाथ

नईदुनिया, भोपाल

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ भी पेगासस जासूसी कांड में कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा, जब भाजपा को कर्नाटक की सरकार गिरानी थी तो पेगासस का उपयोग कर रही थी। संभव है मध्य प्रदेश में मेरी सरकार गिराने में भी कर्नाटक की तरह पेगासस का ही उपयोग किया गया हो। जो लोग (तत्कालीन कांग्रेस विधायक) बेंगलुरु में थे, वे अपने फोन से बात करने में डरते थे। उन्हें मालूम था कि फोन टेप किए जा रहे हैं। मुझे रसोइए या अन्य कर्मचारियों के मोबाइल से फोन आते थे। कमल नाथ बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारवार्ता कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस सरकार के समय फोन टेप कराने के प्रश्न पर कहा कि न तो मैंने कभी ऐसा काम किया और न ही इसके लिए समय था। मुझे मुख्यमंत्री रहते पुलिस वालों ने न तो यह बताया कि इनके फोन टेप किए जा रहे हैं और न ही मैंने कहा।

'1,222 आक्सीजन संयंत्र 15 से पहले शुरू होने की संभावना'

नई दिल्ली, प्रेट्र : आवासीय एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बुधवार को कहा कि पीएम-केयर्स फंड के तहत 1,222 प्रेशर स्विंग अब्जार्पशन (पीएसए) आक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्वीकृत किए गए हैं और उनके 15 अगस्त से पहले शुरू होने की संभावना है। वर्तमान में 300 पीएसए संयंत्र काम कर रहे हैं।

सीआइआइ द्वारा आयोजित रियल इस्टेट कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए दुर्गा शंकर ने कहा कि कोरोना की वजह से प्रापर्टी सेक्टर काफी प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर काफी हद तक नियंत्रित हो चुकी है और अब संभावित तीसरी लहर के बारे में बात और आशंका जाहिर की जा रही है। कहा कि सरकार ने पिछले साल कोरोना की पहली लहर का प्रसार नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए थे जिनमें मार्च, 2020 में लगाया गया राष्ट्रीय लाकडाउन शामिल था। तब देश के पास इस महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त वेंटीलेटर्स, पीपीई किट्स और दवाएं नहीं थीं। इसके बावजूद पहली लहर के दौरान जिस तरह महामारी को नियंत्रित किया गया वो उल्लेखनीय है। भारत ने न सिर्फ घरेलू मांग को पूरा किया बल्कि अन्य देशों को भी चिकित्सकीय आपूर्ति उपलब्ध कराई। अप्रैल, 2021 में आई दूसरी लहर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि संक्रमण के मामले प्रतिदिन चार लाख तक पहुंच गए थे जो पहली लहर में करीब एक लाख प्रतिदिन थे। इस दौरान आक्सीजन आपूर्ति की कमी थी, लेकिन देश ने जिस तरह से इसका सामना किया वह उल्लेखनीय है। आक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए आक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई गईं और वायुसेना की सेवाएं भी ली गईं। आक्सीजन आपूर्ति बढ़ाने में उद्योग जगत के योगदान का उल्लेख करते हुए दुर्गा शंकर ने कहा कि हम इस बड़ी दूसरी लहर को तीन महीने में नियंत्रित करने में सफल रहे।

पते की बात

उपराष्ट्रपति व शिक्षा मंत्री ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट को किया संबोधित, विश्वविद्यालय जलवायु परिवर्तन, गरीबी और प्रदूषण जैसी चुनौतियों का खोजें समाधान

वर्चुअल शिक्षा पारंपरिक क्लास रूम का विकल्प नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना काल में वर्चुअल क्लास रूम के बाद इस दिशा में भविष्य की तैयारियां जरूर शुरू हो गई हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू का साफ मानना है कि वर्चुअल शिक्षा पारंपरिक क्लास रूम शिक्षा का विकल्प नहीं हो सकती है। इसकी जगह आफलाइन और आनलाइन शिक्षा के बेहतर पहलुओं को शामिल करते हुए भविष्य के लिए शिक्षा का एक ऐसा मिला-जुला माडल विकसित करने की जरूरत है, जो शिक्षा ग्रहण करने वालों के साथ-साथ शिक्षकों के लिए भी इंटरैक्टिव और दिलचस्प होनी चाहिए, जिससे अधिक से अधिक शिक्षण परिणाम सुनिश्चित हो सके।

उपराष्ट्रपति नायडू बुधवार को ओपी जिंदल विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान 'भविष्य के विश्वविद्यालय : संस्थागत लचीलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व व सामुदायिक प्रभाव का निर्माण' विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को जलवायु परिवर्तन, गरीबी और प्रदूषण जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान तलाशने के लिए आगे आना चाहिए। दुनिया के सामने खड़ी होती आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों पर भी विमर्श करना चाहिए और विचारों को सामने रखना चाहिए, ताकि सरकारें भी अपनी जरूरत और उपयोगिता के अनुसार इसे अपना सकें। नायडू ने इसके साथ ही विश्वविद्यालयों से अच्छे शिक्षाविद् , अर्थशास्त्री और राजनेता भी तैयार करने को कहा, जिनके पास अच्छा आचरण, क्षमता और चरित्र हो। उन्होंने कहा कि कोरोना काल ने शिक्षा के क्षेत्र को नवाचार के लिए मजबूत किया है, जिससे हमें शिक्षा प्रदान करने और सीखने की अधिक से अधिक न्यायसंगत प्रणाली के निर्माण में मदद मिल सकती है। उन्होंने इस दौरान आनलाइन शैक्षणिक इकोसिस्टम में लगातार सुधार के साथ शिक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) के उपयोग पर जोर दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस मौके पर समिट को संबोधित किया और कहा कि भारत की उच्च शिक्षा का गौरवशाली इतिहास रहा है। बीच के कालखंड में इसमें कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन अब समय आ गया है, हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार करने की जरूरत है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिये यही सोच है। कार्यक्रम में इसके साथ ही यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक चांसलर नवीन जिंदल, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सी राज कुमार आदि मौजूद थे। इस मौके पर 25 से अधिक देशों के 150 से अधिक विचारकों ने भी हिस्सा लिया था।


रखी बात : उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू
फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तीन दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे

नई दिल्ली, प्रेट्र : संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए अब्दुल्ला शाहिद बुधवार को तीन दिन के दौरे पर भारत पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुने जाने के बाद आधिकारिक रूप से शाहिद सबसे पहले भारत की यात्रा पर आए हैं। इस पद के लिए वह सात जून को चुने गए थे। भारत ने मालदीव के विदेश मंत्री शाहिद को इस प्रतिष्ठित पद का प्रत्याशी बनाए जाने का समर्थन किया था।

इस दौरे में शाहिद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिष्टाचार मुलाकात करेंगे और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय और आपसी हितों के द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इस यात्रा के दौरान मालदीव में भारत की आर्थिक सहायता से उच्च-प्रभाव वाले सामुदायिक विकास परियोजना लागू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर भी होंगे।

कह के रहेंगे माधव जोशी



9 नए मेडिकल कालेजों का उत्तर प्रदेश में उद्घाटन करेंगे 30 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश में स्थापित किए गए इन मेडिकल कालेजों में शैक्षिक सत्र 2021 से ही पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 22 जुलाई, 2021

सिद्धू ने दिखाई अपनी ताकत, इम्तिहान आज, ताजपोशी कल

कांग्रेस का अंतर्कलह ▸ मंत्रियों व विधायकों संग तीन बड़े धार्मिक स्थलों पर हुए नतमस्तक

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर खेमा तीसरे दिन भी रहा दूर

जागरण संवाददाता, अमृतसर

पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को अपनी ताकत दिखाई। दोपहर करीब एक बजे मंत्रियों और विधायकों के दल के साथ श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के बाद उन्होंने श्री दुर्ग्याणा मंदिर और श्री राम तीर्थ पहुंचकर माथा टेका। जलियांवाला बाग बंद होने के कारण गेट पर ही शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सिद्धू कैंप ने दावा किया कि इस दौरान चार मंत्रियों सहित 60 से ज्यादा विधायक मौजूद रहे। परंतु विरोधी खेमे ने कहा कि यह संख्या 40 के करीब ही थी।

अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धू ने पहली बार विधायकों के दल के साथ सिखों, हिंदुओं व दलितों के आस्था के केंद्र इन धार्मिक स्थानों पर माथा टेका। खास बात यह रही कि कैप्टन खेमे के मंत्री व विधायक लगातार तीसरे दिन सिद्धू से दूर रहे। अमृतसर के होने के बावजूद मंत्री ओपी सोनी व जिले के तीन अन्य विधायक सिद्धू के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे।



अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब में बुधवार को नतमस्तक होने पहुंचे पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को पैर में चोट के कारण चलने में तकलीफ हो रही थी। ऐसे में विधायक इंद्रबीर सिंह बुलारिया और कुलबीर सिंह जीरा ने उन्हें सहारा दिया। सर्बजीत सिंह

दूसरी ओर मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, सुखबिंदर सिंह सरकारिया, चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ सहित कई विधायक मौजूद रहे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सिद्धू या उनकी टीम के किसी सदस्य को सिरोपा देकर सम्मानित नहीं किया।

गुरु नगरी में शक्ति प्रदर्शन करने वाले सिद्धू का बतौर प्रदेश अध्यक्ष पहला इम्तिहान गुरुवार को होगा। हाईकमान ने जासूसी मामले में प्रदेश इकाइयों को केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए कहा है। राजभवन तक होने वाले प्रदर्शन को लेकर सिद्धू कितने मंत्रियों, विधायकों और अन्य वरिष्ठ नेताओं को इकट्ठा कर पाएंगे, यह प्रदर्शन के दौरान ही पता चलेगा।

ताजपोशी में प्रियंका को बुलाना चाहते हैं सिद्धू, कैप्टन के आने पर संशय : प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत सिंह नागरा ने कहा कि सिद्धू और चारों कार्यकारी अध्यक्ष शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस भवन में पदभार संभालेंगे। नागरा गुरुवार को कुछ अन्य नेताओं के साथ मुख्यमंत्री को विधिवत निमंत्रण देने जाएंगे। वैसे यह कहा जा रहा है कि सिद्धू अपने ताजपोशी समारोह में प्रियंका को बुलाना चाहते हैं।

रंधावा और परगट ने किया कैप्टन पर हमला : मुख्यमंत्री के माफी मांगने तक सिद्धू से न मिलने की बात दोहराने और मंत्री ब्रह्म मोहिंदरा के सिद्धू व कैप्टन मुद्दा सुलझने तक मुलाकात न करने के बयान पर मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने दोनों नेताओं पर तीखा हमला किया। रंधावा ने कहा कि कैप्टन को अपनी बात सोनिया गांधी और हरीश रावत के साथ हुई बैठक में स्पष्ट करनी चाहिए थी। परगट सिंह ने कैप्टन से सवाल किया कि सिद्धू उनसे माफी क्यों मांगें। सिद्धू ने कुछ भी गलत नहीं किया है।

कैप्टन की नाराजगी बनी हाईकमान का सिरदर्द

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ पंजाब कांग्रेस पर फैसले के बाद भी लड़ाई थामने के लिए नेतृत्व दोनों नेताओं को एक मंच पर लाने में जुटा



कैप्टन अमरिंदर सिंह। फाइल/इंटरनेट मीडिया

पंजाब कांग्रेस में बड़े बदलाव के बाद भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जारी लड़ाई पार्टी हाईकमान का सिरदर्द बनती जा रही है। सिद्धू के माफी नहीं मांगने तक उनसे न मिलने की कैप्टन की सार्वजनिक घोषणा में पार्टी नेतृत्व को पंजाब कांग्रेस की मौजूदा लड़ाई का दूसरा चरण दिखाई दे रहा है। पंजाब कांग्रेस में अपने समर्थन का दम दिखाने के सिद्धू के प्रयासों के बावजूद पार्टी में कैप्टन की नाराजगी को अभी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है और हाईकमान की ओर से कैप्टन-सिद्धू की मुलाकात कराने का अंदरूनी प्रयास किया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार पार्टी नेताओं के एक वर्ग ने आशंका जताई है कि जिस तरह सिद्धू आक्रामक तरीके से कैप्टन पर हमला बोल रहे हैं, वह कांग्रेस के लिए फायदे की जगह दोहरे नुकसान का सौदा हो सकता है। पहली बात यह है कि निसंदेह इस वक्त कैप्टन पंजाब की सियासत के सबसे प्रभावशाली शख्स हैं जिनकी अपनी प्रतिष्ठा भी है और उनका अपमान कांग्रेस को ही चोट पहुंचाएगा।

दूसरे पंजाब के अगले चुनाव में कांग्रेस फिलहाल कैप्टन की अगुआई में ही जाने वाली है और ऐसे में अपने चुनावी चेहरे की छवि को सवालों के कठघरे में खड़े करने की सिद्धू की रणनीति को पार्टी नेताओं के इस वर्ग में उचित नहीं माना जा रहा है। इसके मद्देनजर ही पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने हाईकमान को इस मामले में जल्द हस्तक्षेप कर सिद्धू व कैप्टन की लड़ाई खत्म करने की सलाह दी है।

प्रदेश के प्रभारी व कांग्रेस महासचिव हरीश रावत के अलावा एक-दो अन्य वरिष्ठ नेताओं को इस विवाद का पटाक्षेप करने की पहल करने के लिए लगाया गया है। हाईकमान की चिंता यह है कि चाहे कैप्टन ने नए प्रदेश अध्यक्ष पर उसकी पसंद को स्वीकार कर लिया हो मगर वे सिद्धू की टीका-टिप्पणियों के अपने अपमान को भूले नहीं हैं और राजनीतिक रूप से उनका कोई भी बड़ा कदम कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं को पलीता लगा सकता है। बताया जा रहा है कि हाईकमान सिद्धू को समझाने व राजी करने का प्रयास कर रहा है। कैप्टन की नाराजगी को दूर करने के लिए दो कदम आगे बढ़ना उनके और पार्टी दोनों के हित में होगा। सूत्रों का यह कहना है कि हाईकमान ने सिद्धू को अध्यक्ष बनाने के लिए तमाम विरोधों को जिस तरह दरकिनार कर दिया गया, उसे देखते हुए कैप्टन से कटुता खत्म करने की नेतृत्व की सलाह की सिद्धू अनदेखी नहीं करेंगे। संकेत यह भी हैं कि कैप्टन व सिद्धू को एक मंच पर लाने के लिए रावत को चंडीगढ़ भी भेजा जा सकता है।

चुनाव बाद हिंसा के खिलाफ भाजपा का बंगाल से लेकर दिल्ली तक धरना-प्रदर्शन

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की शहीद दिवस रैली के जवाब में बंगाल भाजपा की प्रदेश इकाई के आह्वान पर पार्टी नेताओं, सांसदों व विधायकों ने राज्य में चुनाव बाद हुई कथित हिंसा एवं पार्टी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाए जाने के खिलाफ बुधवार को बंगाल से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन किया और धरना भी दिया। हिंसा में कथित रूप से तृणमूल कार्यकर्ताओं के हाथों मारे गए पार्टी कार्यकर्ताओं को शहीद बताते हुए भाजपा ने शहीद श्रद्धांजलि दिवस के रूप में इस दिन का पालन किया।

इसके मद्देनजर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के नेतृत्व में कई नेताओं तथा बंगाल से भाजपा सांसदों ने नई दिल्ली स्थित राजघाट में धरना दिया और हिंसा में मारे गए पार्टी कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी तरह के कार्यक्रम कोलकाता सहित बंगाल के सभी जिलों व ब्लाकों में भी आयोजित किए गए, जहां भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने हिंसा में मारे गए कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से धरना दिया। इस अवसर पर दिलीप घोष ने राज्य में हिंसा के लिए ममता सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी की जीत के बाद राज्य प्रायोजित हिंसा में तृणमूल समर्थकों द्वारा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं व उनके परिवारों तथा संपत्तियों को निशाना बनाया गया।



नई दिल्ली स्थित राजघाट पर बंगाल में हिंसा के शिकार हुए भाजपा समर्थकों के मामले को लेकर धरना देते भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और अन्य नेता। एएनआइ

तानाशाही मानसिकता को नेस्तनाबूद करेंगे : नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक ट्वीट में कहा कि बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ चुनावी हिंसा को पूरा देश देख रहा है। इस हिंसा में सर्वाधिक अत्याचार महिलाओं, दलितों व बच्चों पर हुआ है। हम सभी लोकतांत्रिक तरीके से लड़ते हुए ममता बनर्जी की तानाशाही मानसिकता को नेस्तनाबूद करेंगे।

बंगाल भाजपा ने दावा किया कि प्रदेश में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद 40 से अधिक पार्टी कार्यकर्ता मारे गए हैं।बंगाल विस में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में गत दो माह में जो कुछ भी हुआ है, उसने 1946 के कलकत्ता हत्याकांड, नोआखाली दंगे व सिखों की हत्याओं को भी पीछे छोड़ दिया है। दूसरी ओर, तृणमूल ने भाजपा के आरोपों से इन्कार किया और दावा किया कि ममता के तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद से बहुत कम हिंसा हुई है।

उप्र के मंत्री ने कहा- जो भारतीयों के खिलाफ खड़े होंगे, एनकाउंटर में मारे जाएंगे

जागरण संवाददाता, बलिया : उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य राज्यमंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग भारतीयों के खिलाफ खड़े होंगे, वे एनकाउंटर में मार दिए जाएंगे। हाल ही में मशहूर शायर मुनव्वर राना ने योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर उत्तर प्रदेश छोड़ने की बात कही थी। उनके इस बयान से खफा शुक्ला ने पलटवार किया। बलिया में एक गेस्ट हाउस में मीडिया से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रविरोधी ताकतों की साजिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जो लोग यह बात कह रहे हैं कि वे यूपी छोड़ देंगे, तो वे समझ लें कि इसका वक्त आ चुका है। कहा कि मुनव्वर उन लोगों में से हैं जो 1947 में देश के बंटवारे के वक्त भारत में ही रुक गए थे और देश में रहकर देश को भीतर से तोड़ने की साजिश रचने वालों में शामिल हो गए।

राज्यमंत्री ने अयोध्या में राममंदिर को लेकर पूर्व में दिए गए कांशीराम के एक बयान की याद दिलाते हुए कहा कि मायावती को इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांशीराम ने बयान दिया था कि अयोध्या में मंदिर की जगह शौचालय बनवा देना चाहिए। शुक्ला ने कहा कि 2003 से 2007 के बीच मुलायम सरकार में गुंडों को बढ़ावा दिया गया था। तब ब्राह्मणों ने गुंडों के खिलाफ मायावती को तरजीह दी। अब प्रबुद्ध व ब्राह्मण समाज भाजपा के साथ है।

पंजाब के बाद राजस्थान में भी कांग्रेस में हो सकता है बड़ा बदलाव

जागरण संवाददाता, जयपुर

राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रहे विवाद को खत्म कराने की जिम्मेदारी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खुद संभाली है। एक वरिष्ठ पदाधिकारी के अनुसार आलाकमान उत्तर प्रदेश और पंजाब में विधानसभा चुनाव को देखते हुए पायलट को नाराज नहीं करना चाहता है। उसकी योजना है कि अगले माह से पायलट दोनों राज्यों का दौरा प्रारंभ करें। इसलिए संभावना है कि उससे पहले राजस्थान के विवाद का निस्तारण कर दिया जाए।

बताया जाता है कि राष्ट्रीय नेताओं का एक समूह पायलट को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पक्ष में है, हालांकि वह खुद इसके लिए तैयार नहीं हैं। मौजूदा अध्यक्ष डोटासरा गहलोत सरकार में शिक्षामंत्री भी हैं। ऐसे में उन्हें अध्यक्ष पद से हटाकर मंत्रिमंडल में ही रखा जा सकता है। डोटासरा खुद भी मंत्री रहना चाहते हैं। इस पदाधिकारी ने बताया कि राजस्थान में सरकार व संगठन में बदलाव को लेकर आलाकमान ने प्रारूप तैयार कर लिया है। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। इसके तहत पायलट को राष्ट्रीय महत्व का अहम पद दिया जा सकता है। चर्चा है कि कुछ ही दिनों में सोनिया गांधी सीएम गहलोत से टेलीफोन पर बात कर प्रारूप को लागू करने के लिए कहेंगी। इसे लागू करने की समय सीमा भी तय की जाएगी। गहलोत के विश्वस्त एक कैबिनेट मंत्री का कहना है कि सीएम मंत्रिमंडल में विस्तार करने को तैयार हैं, लेकिन जैसा पायलट चाहते हैं वैसा नहीं होगा। गहलोत अपनी मुताबिक बदलाव करना चाहते हैं।

कांग्रेस विधायक ने नहीं मानी गहलोत की बात

निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने और मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने से नाराज होकर विस की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले हेमाराम चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात मानने से इन्कार कर दिया है। दो दिन पहले गहलोत ने चौधरी को टेलीफोन कर विधानसभा की राजकीय उपक्रम समिति की बैठक बुलाने के लिए कहा था। चौधरी ने बताया कि मैंने उन्हे साफ कह दिया कि विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुका हूं, इसलिए मैं समिति का अध्यक्ष नहीं हूं। पायलट खेमे के विधायक चौधरी गहलोत की पिछली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पिछले साल पायलट खेमे की बगावत के समय वह उनके साथ थे।

गहलोत और माकन में बढ़ी दूरी: जानकारी के अनुसार, गहलोत प्रदेश प्रभारी अजय माकन के रवैये से नाराज हैं। शिकायत है कि माकन उन्हें दरकिनार कर विधायकों व संगठन के नेताओं से मिल रहे हैं और मंत्रिमंडल विस्तार व राजनीतिक नियुक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वहीं, माकन को गहलोत का अड़ियल रवैया पसंद नहीं आ रहा है। पिछले चार माह में माकन तीन बार गहलोत से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन वह पायलट खेमे को सरकार में प्राथमिकता देने को तैयार नहीं हैं। बताते हैं कि मानक ने पिछले दिनों राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा के समक्ष भी यह बात रखी है।

पायलट दिल्ली में सक्रिय: कुछ दिन पहले पायलट की संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल व अजय माकन के साथ लंबी मुलाकात हुई। दोनों ने आश्वासन दिया कि राजस्थान का मामला आलाकमान खुद देखेगा। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं ने पायलट से 15 अगस्त तक सभी फैसले करने की बात कही है। जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की घोषणा भी शीघ्र करने का वादा किया है।

भाजपा के खिलाफ एकजुट हों सभी विपक्षी दल : ममता

मिशन 2024

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

▸ ममता की हुंकार, भाजपा को सत्ता से बेदखल करने तक जारी रहेगा 'खेला'

▸ तृणमूल के शहीद दिवस पर भाजपा के खिलाफ फूंका बिगुल



शहीद दिवस के अवसर पर अपने आवास से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये लोगों को संबोधित करती बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। प्रेट्र

बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद आत्मविश्वास से लबरेज मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो ममता बनर्जी की निगाहें अब दिल्ली पर हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ममता, भाजपा की घेराबंदी करने के लिए एक बार फिर अभी से विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में जुट गई हैं। बुधवार को शहीद दिवस पर अपनी पार्टी टीएमसी के सबसे बड़े वार्षिक कार्यक्रम के मौके पर ममता ने भाजपा के खिलाफ सभी विपक्षी दलों से एकजुट होने और एक फ्रंट बनाने का आह्वान करते हुए भगवा दल को दिल्ली की गद्दी से हटाने की हुंकार भरी।

कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने आवास से वर्चुअल संबोधन में ममता ने भाजपा पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल की जनता ने धनबल और बाहुबल को नकार दिया और मां- माटी-मानुष को चुना है। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी तरह तानाशाही पर आमादा है। देश में लोगों की आजादी व लोकतंत्र खतरे में है। भाजपा देश को अंधकार में ले गई है। ममता ने कहा कि अभी तो भाजपा को सिर्फ बंगाल से भगाया है, जब तक देश की सत्ता से उसे बेदखल नहीं करते तब तक 'खेला' जारी रहेगा। उन्होंने 16 अगस्त को हर साल 'खेला होबे दिवस' के रूप में मनाने की भी घोषणा की। दरअसल, बंगाल चुनाव के दौरान ममता का 'खेला होबे' का नारा काफी लोकप्रिय हुआ था। ममता ने कहा कि बंगाल के बाद अब गुजरात, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में भी खेला होगा।

जासूसी पर खर्च किया जा रहा देश का पैसा : ममता ने पेगासस जासूसी विवाद को लेकर भी मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार पेगासस के जरिये फोन टैप करा रही है। जासूसी के लिए देश का पैसा खर्च किया जा रहा है। विपक्षी नेताओं ही नहीं, केंद्रीय मंत्रियों व जजों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। इस मामले में उन्होंने संज्ञान लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध किया। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ममता ने दावा किया कि उनके भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर का फोन भी टैप किया गया था। इसके साथ ही आशंका जताई कि मेरी भी फोन टैपिंग हुई होगी।

गंगा में तैरते शव सबने देखे

ममता ने आगे कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में देश ने गंगा में तैरते शव देखे हैं। आक्सीजन की कमी के चलते बहुत से लोगों की मौत हुई है और केंद्र सरकार कहती है कि आक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। तीसरी लहर की भी कोई तैयारी नहीं की है।

बंगाल में चुनाव बाद नहीं हुई हिंसा

ममता ने बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के आरोपों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा के कुछ सदस्य मानवाधिकार संगठन के सदस्य हैं। उन्होंने गलत रिपोर्ट दी है। चुनाव के बाद कोई हिंसा नहीं हुई।

बंगाल के बाहर ममता के भाषण का हुआ प्रसारण

यह पहली बार है जब शहीद दिवस पर ममता के भाषण का बंगाल के बाहर कई राज्यों में सीधा प्रसारण किया गया हो। दिल्ली समेत गुजरात, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, त्रिपुरा व तमिलनाडु में एलईडी स्क्रीन पर इसका प्रसारण किया गया। वर्चुअल प्रसारण के अवसर पर दिल्ली के कंस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम में एनसीपी प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव आदि रहे।

ममता की रैली के बाद दो गुटों में फायरिंग, भगदड़ में दो की मौत

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की शहीद दिवस रैली में बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वर्चुअल संबोधन के बाद उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट इलाके में पार्टी के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई है। इस दौरान फायरिंग के बाद मची भगदड़ में बुजुर्ग महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई। वहीं, सात लोगों के घायल होने की भी खबर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सूत्रों के अनुसार, यह घटना तब हुई जब सीएम के वर्चुअल संबोधन के बाद कार्यक्रम स्थल से लौट रहे टीएमसी समर्थकों पर दूसरे गुट के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। बशीरहाट में कार्यक्रम स्थल के ठीक पास में ही यह घटना घटी। दोनों समूहों के बीच मारपीट हुई और बाद में बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इससके बाद भगदड़ मच गई। इसमें दो लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस घटना के बाद तनाव का माहौल है। घटनास्थल पर बड़ी भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

ममता के 16 अगस्त को 'खेला होबे दिवस' घोषित करने की स्वपन दासगुप्ता ने की कड़ी आलोचना

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

▸ यह वही दिन है, जब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे शुरू किया था

▸ कोलकाता में 1946 में शुरू हुआ था 'ग्रेट कलकत्ता किलिंग'



स्वपन दासगुप्ता। फाइल/इंटरनेट मीडिया

भाजपा के राज्यसभा सदस्य स्वपन दासगुप्ता ने बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी द्वारा 16 अगस्त को 'खेला होबे दिवस' घोषित किए जाने की कड़ी आलोचना की है। ममता के शहीद दिवस अभिभाषण के खत्म होने के तुरंत बाद दासगुप्ता ने ट्वीट कर कहा कि दिलचस्प बात है कि ममता बनर्जी ने 16 अगस्त को खेला होबे दिवस घोषित किया है। यह वही दिन है, जब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे शुरू किया था और कोलकाता में 1946 में ग्रेट कलकत्ता किलिंग शुरू हुआ था। आज के बंगाल में खेला होबे विपक्षी दलों पर आक्रमण के आतंक की लहर बन गई है।

गौरतलब है कि अपने अभिभाषण में ममता ने कहा कि 16 अगस्त को बंगाल में खेला होबे दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन विभिन्न क्लबों में फुटबाल वितरित किए जाएंगे। दासगुप्ता पिछले दिनों तृणमूल के निशाने पर रहे थे, जब उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य के तौर पर भाजपा ने फिर से राज्यसभा भेजा था। दासगुप्ता ने बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। चुनाव हारने के बाद उन्हें फिर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। तृणमूल ने इसपर आपत्ति जताते हुए कहा था कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सिर्फ वही मनोनीत किए जा सकते हैं, जो राजनीति से ताल्लुक नहीं रखते। दासगुप्ता भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के बाद गैर-राजनीतिक व्यक्ति नहीं रह गए थे। इसलिए उन्हें इस तरह से मनोनीत नहीं किया जाना चाहिए था।

इससे पहले दासगुप्ता ने बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले की तुलना 1960 के दशक में चीन में हुई सांस्कृतिक क्रांति से थी, जो पीपुल्स रिपब्लिक आफ चाइना द्वारा चलाया गया एक उग्र आंदोलन था। उसमें बहुत से लोग मारे गए थे।

हमारे नेताओं का फोन टैप कराती हैं ममता : भाजपा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : पेगासस जासूसी मामले को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। इस बीच बंगाल में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर खुद उनका फोन टैप करवाने का आरोप लगाया है।

उन्होंने कहा कि आमने-सामने या वाट्सएप पर बात करने के अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि, ममता सरकार की ओर से भाजपा नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं यहां तक कि कई और लोगों की फोन टैपिंग कराई जा रही है। बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि तृणमूल नेता वाट्सएप पर मैसेज करने के अलावा दूसरे माध्यम से बात नहीं करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ममता खुद उनके फोन टैप कराती हैं। वह और उनकी सरकार पेगासस साफ्टवेयर का उपयोग करती है। फोन टैपिंग हमारा काम नहीं, कांग्रेस का है, जहां से ममता आई हैं।

सत्ता में आए तो देंगे पक्का घर और मुफ्त बिजली : अखिलेश

घोषणा

कहा-बड़े दलों के साथ समाजवादियों का अनुभव नहीं रहा ठीक, छोटों का लेंगे साथ, किसी की जासूसी करवाकर भाजपा ने किया सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह

जागरण संवाददाता, उन्नाव

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि उप्र में अब बदलाव की जरूरत है। यह बदलाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा। प्रदेश में 2022 में सपा की सरकार बनी तो मुफ्त बिजली, प्रत्येक जरूरतमंद को लोहिया आवास के लिए तीन लाख रुपये व छात्रों को लैपटाप देंगे। सपा का घोषणा पत्र गरीबों, किसानों के लिए होगा और पहले से बेहतर होगा।

उन्होंने उन्नाव मे सरोसी गांव स्थित मनोहर लाल इंटर कालेज में समाजवादी नेता पूर्व मंत्री स्व. मनोहर लाल की जयंती पर उनकी प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के दौरान कहा कि बड़े दलों के साथ समाजवादियों का अनुभव ठीक नहीं रहा। इसलिए आने वाले समय में छोटे दलों को ही साथ लेंगे। बसपा के संबंध में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जनता ने उनकी सरकार देखी है। भाजपा को हराने की मंशा रखने वालों के लिए समाजवादी पार्टी के रास्ते खुले हैं। इससे उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बसपा से गठबंधन को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर भी विराम लगा दिया।



उन्नाव के सरोसी गांव में कार्यक्रम को संबोधित करते समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। जागरण

बोले-महिलाओं के कपड़े खींचने तक से नहीं चूके अनुशासित भाजपाई

अखिलेश ने कहा कि समाजवादियों को प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत इसलिए नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जिला पंचायत, ब्लाक प्रमुख चुनाव में देख लिया है। जिस ईमानदारी से उन्होंने चुनाव कराए, पूरे देश और दुनिया ने देखा है। भाजपा के अनुशासित सिपाही इस सीमा तक पहुंच गए कि महिलाओं के कपड़े तक खींचने से नहीं चूके।

अखिलेश ने कहा कि डीएम, एसपी, नेता, मंत्री, सांसद व विधायक सब भाजपा के हैं, फिर भी सरकार लोगों की जासूसी करा रही है। किसी की जासूसी कराना सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। तंज कसा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कमाल के हैं, उनका एक ही संविधान है, ठोको संविधान। सपा ने युवाओं को शिक्षित करने के लिए लैपटाप बांटे। यह लैपटाप कोरोना काल में बहुत काम आए। मौजूदा सीएम ने लैपटाप नहीं बांटे, क्योंकि वह लैपटाप चलाना नहीं जानते और वह क्या करना जानते हैं, यह नहीं बताएंगे। बोले, किसानों और जनता के साथ धोखा हुआ है। किसानों से आय दोगुनी करने का भाजपा ने वादा किया था, लेकिन साढ़े चार साल में कुछ नहीं किया। देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है। भाजपा ने अपना संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया है। कोरोना से लाखों गरीबों की जान चली गई, उन्हें इलाज नहीं मिला, पर सरकार राज्यसभा में बयान दे रही है कि आक्सीजन की कमी से कोई भी मौत नहीं हुई। इन मौतों की जिम्मेदार, केवल भाजपा सरकार है।

2018 तक के लंबित मामलों पर रिपोर्ट तलब की है मानवाधिकार आयोग (एनचआरसी) ने उप्र सरकार से। जानकारी मिलने के बाद तेजी से मामलों के निस्तारण में मदद मिलेगी।

न्यूज गैलरी

व्यवसायी के अपहरण में वन मंत्री विश्नोई के पुत्र का नाम

जयपुर : राजस्थान के जालौर जिले में तीन दिन पहले एक मार्बल व्यवसायी के अपहरण के मामले में राज्य के वन मंत्री सुखराम विश्नोई के बेटे भूपेंद्र विश्नोई पर आरोप लग रहे हैं। हालांकि वन मंत्री का कहना है कि उनके पुत्र पर राजनीतिक साजिश के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं। उसके मोबाइल की काल डिटेल निकलवा कर जांच की जाए तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अपहर्ताओं के चंगुल से छूटने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे मार्बल व्यवसायी प्रकाश विश्नोई ने बताया कि तीन पहले उनका जालौर के नया मोड़ से अपहरण कर लिया गया था। अपहर्ता उन्हें हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर ले गए। व्यवसायी ने आरोप लगाया कि अपहरण की साजिश में वन मंत्री के बेटे भूपेंद्र का हाथ था। अपहर्ताओं ने जालौर से ले जाते समय गाड़ी में उसकी भूपेंद्र से मोबाइल पर बात कराई थी। भूपेंद्र ने कहा था कि तुम 50 लाख की रकम देकर छूट जाओ। व्यवसायी ने पुलिस के समक्ष अपने शरीर पर चोट के निशान दिखाते हुए आरोप लगाया कि लगातार दो दिन तक उसके साथ मारपीट की गई। (जासं)

छेड़खानी मामले में केरल के मंत्री को हटाने की मांग

तिरुअनंतपुरम : कांग्रेस सांसद बेन्नी बेहानन ने केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान को पत्र लिखकर राज्य के वन मंत्री एके शशिधरन को हटाने की मांग की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता के खिलाफ यौन प्रताड़ना की शिकायत में मंत्री पर हस्तक्षेप करने का आरोप है। कांग्रेस सांसद ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से भी शशिधरन को हटाने के लिए कहा है। शशिधरन के खिलाफ छेड़खानी पीड़िता के परिवार पर दबाव बनाने का आरोप है। (एएनआइ)

एनआइए की पूछताछ के 24 घंटे बाद जहर खाकर जान दी

मेरठ : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की पूछताछ के 24 घंटे बाद परमजीत सिंह ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। एनआइए ने केएलएफ (खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स) के सदस्य गगनदीप के साथ उसकी फोटो देखकर शक के आधार पर दो बार पूछताछ की थी। एनआइए को संदेह था कि परमजीत भी केएलएफ के लिए हथियार सप्लाई कर रहा था। स्वजन का कहना था कि एनआइए की पूछताछ के बाद से वह सहमा हुआ था। (जासं)

देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार को बनेगी हाई पावर कमेटी

उत्तरकाशी : उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों और हक-हकूकधारियों के बीच से उठ रहे विरोध के सुरों को थामने की दिशा में प्रदेश सरकार ने कदम बढ़ाया है। उत्तरकाशी के दौरे पर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार का निर्णय लिया गया है। इस कड़ी में हाई पावर कमेटी गठित की जा रही है। कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनेगी और इसमें कौन-कौन सदस्य होंगे, यह जल्द ही तय किया जाएगा। (जासं)

नपुंसक कहने पर हथौड़े व कैंची से कर दी भाभी की हत्या

वाराणसी : वाराणसी में बुधवार सुबह करीब सवा 11 बजे नपुंसक कहने पर देवर ने हथौड़े और कैंची से सिर पर वार कर कैंसर विशेषज्ञ डा. सपना गुप्ता दत्ता की उनकी क्लीनिक में हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपित ने समर्पण कर दिया। आरोपित अनिल कुमार दत्ता कांग्रेस के पूर्व विधायक डा. रजनीकांत दत्ता का पुत्र है। वारदात में उसके नौकर रोशन ने भी मदद की। (जासं)

सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डाक्टर बने रघु राम

हैदराबाद : हैदराबाद के डाक्टर और केआइएमएस उषालक्ष्मी सेंटर फार ब्रेस्ट डिजीज के संस्थापक निदेशक पी.रघु राम को एसोसिएशन आफ सर्जन आफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड (एएसजीबीआइ) की फेलोशिप प्रदान की गई है। यह प्रतिष्ठित फेलोशिप पाने वाले वे पहले भारतीय डाक्टर हैं। (आइएएनएस)

कृषि कानूनों के खिलाफ जंतर-मंतर पर कर सकेंगे प्रदर्शन

आज से प्रदर्शन ▶ एलजी के निर्देश पर पुलिस व संयुक्त किसान मोर्चा में बनी सहमति, सुबह 11 से शाम पांच बजे तक मिली इजाजत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों को संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए जगह मिल गई है। अब वे जंतर-मंतर पर सुबह 11 से शाम पांच बजे तक यानी छह घंटे प्रदर्शन कर सकेंगे। रोज 200 प्रदर्शनकारी ही प्रदर्शन में शामिल होंगे। 22 जुलाई से नौ अगस्त तक प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई है। पुलिस आयुक्त बालाजी श्रीवास्तव ने जंतर-मंतर जाकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से बात की।

गौरतलब है कि इस मुद्दे को लेकर दिल्ली पुलिस और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच दो बार की बैठक नतीजा रही थी। मोर्चा के नेता संसद के सामने धरना देना चाहते थे, जबकि पुलिस इसके लिए तैयार नहीं थी। वह कहीं अन्यत्र धरने का विकल्प सुझा रही थी। अब उपराज्यपाल अनिल बैजल के निर्देश पर जंतर मंतर पर धरने की अनुमति दी गई। प्रदर्शनकारियों ने भी इस पर सहमति जताई है।

पुलिस ने बताया कि पुलिसकर्मियों के सुरक्षा घेरे में हर दिन बसों में सवार होकर केवल 200 प्रदर्शनकारी जंतर मंतर आ सकेंगे। एक एसयूवी में छह नेता अलग से आ सकेंगे। प्रदर्शन के बाद सभी को वापस सीमाओं पर भेज दिया जाएगा। बुधवार को दिल्ली सरकार के तरफ से डीडीएमए के एडिशनल सीईओ राजेश गोयल ने पुलिस मुख्यालय के एडिशनल सीपी दीपक पुरोहित को पत्र भेज कर बताया कि एलजी के निर्देश पर प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी गई है।



आंदोलन को समर्थन देने के लिए कुंडली बार्डर पहुंचने ओमप्रकाश चौटाला। जागरण

चार बसों में जाएंगे 200 आंदोलनकारी

जासं, सोनीपत : कृषि कानून विरोधी आंदोलनकारी बृहस्पतिवार को संसद भवन पर प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए चार बसों से आंदोलनकारी और उसके नेता संसद भवन जाएंगे। मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने प्रदर्शन की तैयारी का मंच से जिक्र करते हुए कहा कि प्रदर्शन में शामिल आंदोलनकारियों की पूरी सूची मोर्चा के पास होगी। रोजाना इसी तरह 200 लोगों की सूची बनाई जाएगी और इससे इतर एक भी व्यक्ति इस प्रदर्शन में शामिल नहीं होगा। राजेवाल ने कहा कि यदि संसद में कृषि कानूनों का विरोध नहीं किया तो भाजपा की ही तरह कांग्रेस का भी विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार से आंदोलनकारी संसद भवन के सामने बैठकर अपनी संसद चलाएंगे।

'चंबल के डाकू चुनाव लड़ सकते हैं, किसान क्यों नहीं'

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

संयुक्त किसान मोर्चा से निलंबित किए गए हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक बार फिर किसानों से चुनाव में उतरने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब चंबल के डाकू चुनाव लड़ सकते हैं तो कर्मठ किसान क्यों नहीं। उन्होंने किसानों से पारंपरिक पार्टियों के बजाय अपने में से अच्छे उम्मीदवारों को उतारने की अपील की। गौरतलब है कि उन्हें इन्हीं बयानों के कारण एक सप्ताह के लिए निलंबित किया गया था।

उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा अगर उन्हें बर्खास्त भी कर दे तो भी वह किसानों और मोर्चे के प्रोग्राम को सफल करने के लिए लड़ते रहेंगे। चढ़ूनी बुधवार को चंडीगढ़ में किसान मजदूर दलित फ्रंट और मनरेगा वर्कर फ्रंट के एक सेमिनार में हिस्सा लेने पहुंचे थे।

चढ़ूनी ने पंजाब विधानसभा के चुनाव लड़ने के बारे में पूछे सवाल पर कहा कि इस बारे में पंजाब के लोग जो भी फैसला लेंगे वह उन्हें मंजूर होगा। किसानों व दलितों को एकजुट होकर इस मिशन को फतेह करना होगा। जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों चाहते हैं कि पंजाब में किसान चुनाव लड़ें। इस पर उन्होंने कहा कि पंजाब ने हमेशा लीड किया है। हालांकि, यह काम कांग्रेस को करना चाहिए था। किसान आंदोलन भी पंजाब से ही शुरू हुआ है। मैं चुनाव लड़ने की अपनी विचारधारा पर टिका हुआ हूं। हमें पंजाब में अपने उम्मीदवार खड़े करके जीत हासिल करनी होगी। हरियाणा सरकार के खिलाफ तीन आंदोलन चलाए, लेकिन किसानों के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। मिशन 2024 से पहले हमें मिशन 2022 को सफल बनाना होगा।

नहीं खुली जीटी रोड तो गांव की सड़कें भी करेंगे बंद

जागरण संवाददाता, सोनीपत

- ग्रामीणों ने आंदोलन तेज करने पर जताई सहमति, आपस में बैठक कर तय करेंगे समय-सीमा
- राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच के बैनर तले एजुकेशन सिटी से जीटी रोड तक किया पैदल मार्च

कृषि कानून विरोधी आंदोलन के कारण पिछले करीब आठ महीने से बंद जीटी रोड के एक लेन को खुलवाने के लिए कुंडली और आसपास के ग्रामीणों व व्यापारियों ने पैदल मार्च निकाला। राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच के बैनर तले मार्च में शामिल लोगों ने सरकार व प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि जल्द रोड नहीं खोला गया तो वे भी गांव की सड़कों को जाम कर देंगे। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी से आगे निकलकर जीटी रोड पर कुछ दूर चलते ही पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए मार्च को रोक दिया। शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे लोगों ने भी पुलिस का कोई प्रतिरोध नहीं किया और अपना मार्च समाप्त कर दिया।

रास्ते खोलने की मांग को लेकर पूर्व निर्धारित पैदल मार्च के लिए सुबह साढ़े नौ बजे से ही लोग राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में जुटना शुरू हो गए। करीब 11 बजे मार्च शुरू हुआ, लेकिन एजुकेशन सिटी से जीटी रोड पर फ्लाईओवर के आगे भारी पुलिस बल के साथ बैरिकेडिंग के पास मार्च ठहर गया। पुलिस-प्रशासन की ओर से पूर्व में आंदोलनकारियों के उपद्रव को देखते हुए सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए थे। राई एजुकेशन सिटी के पास फ्लाईओवर के नीचे जीटी रोड पर दोनों ओर मजबूत बैरिकेडिंग की गई थी। यहां वज्र वाहन, वाटर कैनन आदि के साथ 100 से ज्यादा पुलिस कर्मी व इतने ही पारा मिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात किए गए थे। बैरिकेडिंग के पास मौजूद ड्यूटी मजिस्ट्रेट, डीएसपी व अन्य पुलिस अधिकारियों ने मार्च निकाल रहे लोगों से कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए मार्च को इससे आगे नहीं ले जाने का अनुरोध किया। मार्च निकाल रहे लोगों ने भी अनुरोध स्वीकार करते हुए कहा कि वे आंदोलनकारी नहीं हैं जो पुलिस के साथ हाथापाई करें या बैरिकेड तोड़कर कानून व्यवस्था खराब करें। उनका आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि इसके बाद भी सरकार ने रोड का एक लेन नहीं खुलवाया तो वे जल्द ही बैठक कर आंदोलन को तेज करने व गांवों की सड़कें बंद करने का निर्णय लेंगे। राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच के अध्यक्ष हेमंत नांदल ने कहा कि आठ माह से रोड बंद होने के कारण क्षेत्र में रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है।

भिवानी में मतांतरण करने वाले पांच परिवारों ने की हिंदू धर्म में वापसी

जागरण संवाददाता, भिवानी : हरियाणा में भिवानी जिले के गांव उमरावत में मतांतरण कर ईसाई धर्म अपनाने वाले पांच परिवार वापस हिंदू धर्म में आ गए। ग्रामीणों ने उनको काफी समझाया और मानने के बाद चौपाल में हवन यज्ञ किया।

गौरतलब है कि उमरावत गांव के करीब 80 लोगों ने ईसाई मत अपना लिया था। पता चलने पर गांव वालों ने काफी समझाया-बुझाया। मंगलवार को पांच परिवार के करीब 30 लोगों ने वापस हिंदू धर्म अपना लिया। हवन यज्ञ के दौरान सभी सदस्यों ने प्रण लिया कि वे हिंदू धर्म छोड़कर अन्य दूसरे धर्मों में नहीं जाएंगे। अन्य बचे हुए लोगों को भी भाईचारे से बातचीत करके घर वापसी कराई जाएगी। धर्म जागरण समन्वय के युवा मुकेश हिंदू उमरावत ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा समाज को तोड़ने का प्रयास चल रहा है।

मुखबिरी नहीं करने की चेतावनी देकर नक्सलियों ने ग्रामीणों को छोड़ा

नईदुनिया, सुकमा

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने सुकमा जिले के कुंदेड़ गांव से अगवा किए गए नौ ग्रामीणों समेत उन्हें छुड़ाने गए 25 अन्य ग्रामीणों को सकुशल रिहा कर दिया है। मगर इसके पहले नक्सलियों ने तोलावर्ती इलाके में जनअदालत लगाकर सभी को पुलिस की मुखबिरी नहीं करने की सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि यह उनके लिए आखिरी मौका है। मंगलवार की रात सभी ग्रामीण अपने घरों को पहुंच गए, जिसके बाद स्वजन और पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली।

नक्सलियों ने 17 जुलाई को दो और 18 जुलाई को कुंदेड़ के सात ग्रामीणों को अगवा कर लिया था। एक दिन बीतने के बाद भी जब वे घर नहीं लौटे तो उन्हें छुड़ाने के लिए 25 अन्य ग्रामीण भी जंगल गए थे। इन्हें भी नक्सलियों ने बंधक बना लिया था। सर्व आदिवासी समाज ने सभी अगवा ग्रामीणों को छोड़ देने की अपील मीडिया के माध्यम से नक्सलियों से की थी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस जब कुंदेड़ पहुंची तो गांव में केवल महिलाएं मिलीं। इसके बाद से पुलिस ग्रामीणों की तलाश में जुटी हुई थी। एसपी सुनील शर्मा ने बताया कि मंगलवार की रात सभी ग्रामीण अपने घर पहुंच गए हैं। सर्व आदिवासी समाज के युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष रामदेव बघेल ने भी पुष्टि करते हुए बताया सभी ग्रामीण लौट आए हैं।

> ग्रामीणों को मंगलवार की रात नक्सलियों ने छोड़ दिया है। सभी गांव लौट आए हैं। अगवा करने के पीछे क्या कारण है, इसके बारे में बताया लगाया जा रहा है।
> – सुनील शर्मा, एसपी, सुकमा

दिसंबर तक 50 हजार और युवाओं को देंगे नौकरी : योगी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि दिसंबर, 2021 तक 50 हजार और युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। लखनऊ के लोक भवन में आबकारी निरीक्षक पद पर चयनित 130 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में योगी ने कहा कि अब पूरी पारदर्शीता व शुचिता के साथ भर्तियां की जा रही हैं। युवा किसी के भी बहकावे में न आएं। 2002 से लेकर 2017 तक पंद्रह वर्षों में जो भर्तियां हुई हैं उनमें गड़बड़ियों का बोलबाला रहता था। भर्ती की एक समांतर व्यवस्था चलती थी। उसमें भाई-भतीजाबाद, क्षेत्रवाद और धन उगाही की जाती थी। भर्ती प्रक्रिया भी तमाम बार कोर्ट रद कर देता था। पहले 15 वर्षों में जितनी भर्ती नहीं हुई उससे ज्यादा साढ़े चार वर्षों में नौकरियां हमारी सरकार में दी गईं।

आज झारखंड में भारी बारिश की संभावना, उप्र में नदियां उफनाईं

जागरण टीम, नई दिल्ली

- रांची सहित कई जिलों में अगले एक सप्ताह तक बारिश होने के आसार
- उप्र में वज्रपात से तीन की मौत, नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराया

झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। झारखंड के कई जिलों में गुरुवार को भारी बारिश की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक चक्रवातीय क्षेत्र बना हुआ है। इसका प्रसार पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और झारखंड के उत्तरी हिस्सों तक है। वहीं कम दबाव का चक्रवातीय क्षेत्र दक्षिणी बांग्लादेश और बंगाल की तरफ बढ़कर अपना प्रभाव दिखा रहा है। इसका असर भी राज्य में अगले 48 घंटों में दिख सकता है। उप्र में भी नदियों ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। उफनाती नदियों से कुछ जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ जाने लगे हैं। सूबे में बुधवार को वज्रपात से तीन लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग के निदेशक डा. जेपी गुप्ता ने बताया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ अलग अलग जिलों में हल्की और मध्यम बारिश होगी। अभी अगले दो-तीन दिनों तक भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। लखनऊ में सिर्फ बूंदाबांदी और आंशिक बारिश, फुहार इत्यादि ही पड़ती रहेगी।लखनऊ के आसपास के आधा दर्जन से अधिक जिलों में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। कहीं बाढ़ से भारी तबाही हो रही है तो कहीं अलर्ट जारी होते ही गांव के गांव खाली हो रहे हैं।



हालचाल पूछते रक्षामंत्री

लखनऊ के एसजीपीजीआइ अस्पताल में भर्ती उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी लेते रक्षामंत्री राजनाथ सिंह। प्रेट्र

जम्मू एयरपोर्ट के पास फिर मंडराता दिखा ड्रोन

राज्य ब्यूरो, जम्मू : अति सुरक्षित एवं अति संवेदनशील जम्मू एयरपोर्ट इलाके में बुधवार तड़के पाकिस्तानी ड्रोन दो बार देखा गया है। सुरक्षाबलों की कार्रवाई से पहले ही यह पाकिस्तान की ओर लौट गया। ड्रोन देखे जाने के बाद एयरपोर्ट और सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए नए सिरे से फिर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां और अलर्ट हो गई हैं। पिछले 19 दिन में जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के नौ मामले सामने आ चुके हैं।

बुधवार तड़के करीब चार बजे सतवारी एयरपोर्ट के ऊपर मंडराते ड्रोन की लाल रोशनी देखी गई। इसके पांच मिनट बाद पास में ही स्थित पीरबाबा इलाके में भी ड्रोन देखा गया। ड्रोन काफी ऊंचाई पर था। सुरक्षाबलों के कार्रवाई करने से पहले ही ड्रोन पाकिस्तान की ओर लौट गया। हालांकि, बाद में सुरक्षाबलों ने क्षेत्र को खंगाला। अलबत्ता, अभी तक इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 27 जून को ड्रोन हमले के बाद से ही सेना, सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। इसके बाद से पाकिस्तान की ओर से ड्रोन की घुसपैठ की लगातार कोशिशें हो रही हैं।

खत्म हुई जद्दोजहद, इंसाफ मिलेगा

केस-01

जम्मू की निवासी परीक्षा ने कहा कि मेरे पति कौशल की फैक्टरी गांधीनगर, गुजरात में हैं। वह जम्मू-कश्मीर में अपनी एक फैक्टरी लगाना चाहते थे। पति के लिए डोमिसाइल तभी मिलता, जब वह 15 साल जम्मू-कश्मीर में रहते। ऐसा करने के लिए हमें गुजरात में अपना सबकुछ बेचकर जम्मू आना पड़ता। फिर जम्मू में कारोबार लगाना मुश्किल होता। ऐसे हालात में कई पारवारिक, सामाजिक व आर्थिक दिक्कतें भी पैदा होती। आज जो सुविधा मिली है, वह वाकई क्रांतिकारी है।

केस-02

स्थानीय निवासी मुहम्मद इमरान ने कहा कि यह फैसला बहुत सही है। मेरे एक परिचित हैं, उनके कारोबारी मित्र मेरठ में रहते हैं। वह अपने बेटे की शादी मेरे परिचित की बेटी से करना चाहते थे, लेकिन बात अटक गई, क्योंकि लड़के का डोमिसाइल नहीं बनता। मुझे लगता है कि अब यह रिश्ता हो जाएगा। इसी तरह मेरी चचेरी बहन असमा खान की शादी मलेरकोटला, पंजाब में हुई है। पति अबरार चाहते हैं कि वह यहां आकर बसें, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रहे थे।

राज्य ब्यूरो, जम्मू

हिमाचल के कांगड़ा जिले में शादी होने के बाद पति और बच्चों के लिए डोमिसाइल बनाने के लिए सुषमा देवी की जद्दोजहद अब खत्म हो गई है। डोमिसाइल कानून में संशोधन से अब उनके पति प्रवीण चौधरी और बच्चों को जम्मू-कश्मीर का निवासी होने का अधिकार मिल जाएगा।

सुषमा ने बताया कि उनकी शादी करीब 20 साल पहले हिमाचल प्रदेश में हुई थी। शादी के बाद जम्मू-कश्मीर में उनके सभी अधिकार समाप्त हो गए थे, लेकिन अनुच्छेद-370 का रोड़ा हटने के बाद उन्हें तो अधिकार मिल गया, लेकिन परिवार के साथ इंसाफ नहीं हुआ। उनका कहना है कि उन्होंने और उनके पति ने डोमिसाइल बनवाने के लिए दफ्तरों के कई चक्कर काटे, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ।

> यह एक अच्छा कदम है। अब जम्मू कश्मीर की बेटियों को इसका लाभ होगा ही। अनुच्छेद-370 व 35 ए समाप्त होने के बाद भी इसे लेकर अड़चन थी, क्योंकि डोमिसाइल पाने के लिए 15 साल यहां रहने की अनिवार्यता है। इसे लेकर कुछ लोगों ने अदालत में भी केस दायर किया था।
> -शेख शकील, एडवोकेट

पॉर्न एप से नियमित धन पाता था राज कुंद्रा

नई दिल्ली, आइएएनएस : फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का पति और उद्योगपति राज कुंद्रा पॉर्न एप हॉटहिट से नियमित रूप से लाखों रुपये पाता था। कुंद्रा के बैंक अकाउंट की जांच में हाल के महीनों में 9.65 लाख रुपये की आमद का पता चला है। मुंबई पुलिस ने इस एप का इस साल के शुरू में पता लगाया था। यह एप बेस्ट इंडियन मूवीज एंड वेब सीरीज दिखाने का दावा करते हुए अश्लील सामग्री परोसता था। इसके लिए वह अलग से धन की वसूली करता था। बाद में राज कुंद्रा भी इसी एप से जुड़ा मिला।

इसी साल फरवरी में मुंबई पुलिस ने नवोदित अभिनेता और अभिनेत्रियों को पॉर्नोग्राफिक फिल्मों में न्यूड सीन देने का ऑफर देने वाले नौ लोगों को गिरफ्तार किया था। ये लोग फिल्मों में काम करने के लिए आए युवाओं को निशाना बनाकर अपने जाल में फंसाते थे। यह गिरोह पॉर्न फिल्में बनाकर उन्हें पेड वेबसाइटों और मोबाइल एप्लीकेशनों के जरिये लोगों तक पहुंचाता था। कई टीवी सीरियल में काम कर चुकी गहना वशिष्ठ इसी गिरोह के साथ थी।

बदलाव

समझ चुके हैं आतंकी, पहचान होने के बाद या तो पकड़े जाएंगे या जल्द मारे जाएंगे, 2015 में आतंकी बुरहान की साथियों संग तस्वीर वायरल होने के बाद तेज हुआ था सिलसिला

कश्मीर में अब कोई नहीं बनना चाहता आतंक का पोस्टर ब्वाय

नवीन नवाज, श्रीनगर

इंटरनेट मीडिया पर अब कश्मीरी आतंकी नजर नहीं आते। अगर कोई आतंकी बनता भी है तो वह इसका एलान नहीं करता। उसके समर्थक भी उसकी तस्वीरें या वीडियो वायरल करना तो दूर सार्वजनिक जगहों पर उसका नाम तक नहीं लेते। पांच अगस्त, 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर में लगातार सुधर रहे सुरक्षा परिदृश्य में अगर कश्मीरी अवाम ने सबसे ज्यादा कोई सुखद बदलाव महसूस किया है तो यही कि अब कोई भी आतंकियों का पोस्टर ब्वाय नहीं बनना चाहता, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही वह ऐसा करेंगे, कुछ दिन में या तो पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे।

जम्मू-कश्मीर में आतंकी हिंसा पर नजर रखने वाले और आम कश्मीरी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि वादी में 2013 के बाद आतंकी संगठनों में स्थानीय युवकों की भर्ती में इंटरनेट मीडिया की भूमिका सबसे अहम रही है। आतंकी संगठनों ने आतंकी बुरहान को अपने पोस्टर ब्वाय की तरह इस्तेमाल किया था। बुरहान के आतंकी बनने के बाद से ही उसकी तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर अक्सर वायरल होती थीं। 2015 में उसने अपने साथियों संग एक तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर वायरल की और उसके बाद जो भी आतंकी बनता, वही अपनी तस्वीर को वायरल करता। आठ जुलाई 2016 को बुरहान की मौत के बाद भी यह सिलसिला जारी रहा। आतंकी कमांडर जाकिर मूसा, रियाज नाइकू व अन्य कई आतंकी कमांडरों ने भी इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल किया और आतंकियों को एक नायक बनाने का दुष्प्रचार किया। इससे आतंकी संगठनों में नए लड़कों की भर्ती में तेजी आई।

अब स्थिति बदल गई है। इस साल भी 60-70 लड़के अपने घरों से गायब हुए हैं। इनमें से अधिकांश आतंकी बने हैं, लेकिन कुछ को छोड़कर शायद ही किसी ने इंटरनेट मीडिया पर अपनी तस्वीर वायरल की हो या आतंकी बनने की पुष्टि की हो। बीते दो साल के दौरान करीब एक दर्जन लड़कों ने ही सोशल मीडिया पर आतंकी बनने का एलान किया है। इनमें तीन-चार लड़के अल-बदर से थे। इस समय सिर्फ द रजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) जम्मू-कश्मीर ही नए लड़कों के आतंकी बनने का एलान कर रहा है और वह भी तब जब टीआरएफ का कोई आतंकी मारा जाता है तो उसके बाद वह तस्वीर नहीं सिर्फ आडियो मैसेज जारी करता है। दो दिन पहले शोपियां में मारे गए दो आतंकियों में शामिल माजिद ने आतंकी बनने पर कोई तस्वीर जारी नहीं की थी। इससे पूर्व पांच जुलाई को हाजन पुलवामा में मारे गए पांच आतंकियों ने भी आतंकी बनने का एलान नहीं किया था। वहीं, कश्मीर में लश्कर के प्रमुख कमांडरों में शामिल खालिद, हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर अशरफ मौलवी, जैश आतंकी समीर डार का कोई आडियो, वीडियो या तस्वीर पांच अगस्त, 2019 के बाद से नहीं देखी गई है।

दो दर्जन लड़कों को आतंकियों की चंगुल से मुक्त कराया : जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपना नाम न छापने की शर्त पर कहा कि आम कश्मीरी भी अक्सर प्रशासन से आग्रह करता था कि अगर कश्मीरी नौजवानों को जिहादियों से बचाना है तो सबसे पहले इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने वाली आतंकियों की तस्वीरें और उनके महिमामंडन पर रोक लगाई जाए। पांच अगस्त, 2019 के बाद स्थिति बदल गई है। ऐसे में उसे मुख्यधारा में पुनर्वासित करना आसान रहता है। इस साल करीब दो दर्जन के करीब लड़कों को आतंकियों की चंगुल से मुक्त कराया गया है।

कई ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज बंद कराए गए

कश्मीर के साइबर सेल के प्रभारी एसपी ताहिर अशरफ के अनुसार, पांच अगस्त, 2019 के बाद इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय जिहादियों की फौज भी लगातार घटी है। हमने ऐसे कई जिहादी तत्वों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की है। कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कई ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज बंद कराए गए हैं।

उत्तराखंड में एलएसी पर चीनी सेना की सक्रियता बढ़ी !

राज्य ब्यूरो, देहरादून

- चमोली जिले की मलारी घाटी में बाड़ाहोती के पास देखे गए चीनी सैनिक
- शासन और स्थानीय प्रशासन ने ऐसी किसी सूचना से किया इन्कार

भारत और चीन के बीच लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच उत्तराखंड में भी सीमा पर चीनी सेना की सक्रियता की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि चमोली जिले की मलारी घाटी में बाड़ाहोती के निकट वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सेना की सक्रियता देखी गई है। हालांकि शासन और स्थानीय प्रशासन ने ऐसी किसी जानकारी से इन्कार किया है।

उत्तराखंड की 345 लंबी सीमा चीन से सटी है। जोशीमठ से 102 किलोमीटर दूर स्थित भारत की अंतिम पोस्ट रिमखिम से बाड़ाहोती तीन किलोमीटर दूर है। करीब 30 वर्ग किलोमीटर में फैले बाड़ाहोती चारागाह में स्थानीय लोग मवेशी लेकर आते हैं। इस संवेदनशील क्षेत्र में पहले कई बार चीनी सेना अतिक्रमण करती रही है। हालांकि सेना और भारत-तिब्बत सेना पुलिस बल (आइटीबीपी) के जवानों ने हर बार चीनी सैनिकों की हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है।

बताया जा रहा है कि पिछले दिनों चीनी सेना की एक प्लाटून बाड़ाहोती इलाके के आसपास देखी गई। सेना चीनी सैनिकों की गतिविधियों पर पैनी निगाह रखे हुए है। पिछले वर्ष लद्दाख में तनाव के बाद उत्तराखंड से लगी सीमा पर भी सेना के जवानों की संख्या बढ़ा दी है। दूसरी ओर अपर मुख्य सचिव (गृह) आनंद वर्द्धन ने बताया कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। वहीं, चमोली के पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने भी ऐसी किसी सूचना से इन्कार किया। लंबे समय से वायुसेना चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर परीक्षण उड़ान भरती रही है।

महामारी ने 1.19 लाख भारतीय बच्चों को बनाया अनाथ

अंतरराष्ट्रीय मेडिकल जर्नल लैंसेट में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक कोविड-19 महामारी ने पहले 14 महीनों में दुनिया के 21 देशों में 15 लाख बच्चों को अनाथ और बेसहारा बना दिया। इनमें 1.19 लाख बच्चे सिर्फ भारत से हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित होकर इन बच्चों के पहले और दूसरे स्तर के देखभाल करने वाले लोग काल-कवलित हो गए। हालांकि जून में नेशनल कमीशन फार प्रोटेक्शन आफ चाइल्ड राइट्स (एनसीपीसीआर) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि भारत में ऐसे बच्चों की संख्या 9346 है।

हमारे बाल-गोपाल का हाल: अध्ययन के मुताबिक भारत में 25,500 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस महामारी में अपनी मां को खो दिया। जबकि 90,751 बच्चे अपने पिता को खो चुके हैं। 12 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने माता और पिता दोनों को खोया है। 2898 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने संरक्षक दादा या दादी को खोया जबकि नौ बच्चे ऐसे रहे जिनके संरक्षक दादा और दादी दोनों इस महामारी में काल-कवलित हुए।

परदेस की स्थिति: 15.62 लाख ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता-पिता में से किसी एक को या किसी देखभाल करने वाले को या साथ में रह रहे दादा-दादी को खो चुके हैं। 10.42 लाख बच्चे अपनी मां, पिता या दोनों को खो चुके हैं। हालांकि इनमें उनकी ज्यादा संख्या है जिनके माता-पिता में से एक की जान गई है। (प्रेट्र)

इन देशों में हुए सर्वाधिक अनाथ

दक्षिण अफ्रीका, पेरू, अमेरिका, भारत, ब्राजील और मेक्सिको

देखभाल करने वालों की मौतें

एक हजार बच्चों पर ऐसे अभिभावकों या संरक्षकों की एक से अधिक मौतों के मामलों वाले देशों में पेरू, दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको, ब्राजील, कोलंबिया, ईरान, अमेरिका, अर्जेंटीना और रूस हैं।


अनाथ बच्चों को सहारा देने बढ़े हाथ। फाइल फोटो

अभिभावक या देखभाल करने वालों को खोने के बाद बच्चा एक भयावह सदमे से गुजरता है। इस बात के प्रमाण हैं कि इस हालात के बाद बच्चे गलत दिशा में मुड़ सकते हैं, जिन्हें हमें उपयुक्त सुविधाओं से रोकना होगा। महामारी में अपनों को खोने वाले बच्चों को ये सुविधाएं, सहूलियतें सुनिश्चित कराना हम सबकी जिम्मेदारी है।

नोरा डी वोल्कोव, निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रगल एब्यूज (नीडा), अमेरिका (शोध को वित्त पोषित करने वाली संस्था)

देश, प्रति हजार बच्चों पर अभिभावकों की मौतें	
भारत	0.5
दक्षिण अफ्रीका	6.4
पेरू	14.1
ब्राजील	3.5
कोलंबिया	3.4
मेक्सिको	5.1
रूस	2.0
अमेरिका	1.8

उत्तराखंड में पर्यटन व्यवसायियों के लिए 200 करोड़ का राहत पैकेज

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी

कोरोना संक्रमण के कारण चारधाम और अन्य पर्यटक स्थलों के बंद होने के कारण परेशानी झेल रहे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। उत्तरकाशी के दौरे पर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होटल, परिवहन, पोर्टर समेत पर्यटन की अन्य गतिविधियों से जुड़े व्यवसायियों के साथ ही सांस्कृतिक दलों के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये के आर्थिक राहत पैकेज का एलान किया। इससे प्रदेशभर में 163661 लोग लाभान्वित होंगे। लाभार्थियों को सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।

मुख्यमंत्री धामी ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चारधाम यात्रा और पर्यटन राज्य की आर्थिकी का मुख्य आधार हैं। पर्यटन और चारधाम यात्रा से हर तरह का व्यवसायी किसी न किसी रूप से जुड़ा है। कोरोना संक्रमण के कारण चारधाम यात्रा और पर्यटन गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसे देखते हुए पर्यटन से जुड़े व्यक्तियों को राहत देने के लिए सरकार ने 'कोविड-19 राहत पैकेज-2021' की व्यवस्था की है। इससे कार्य करने वालों को मदद मिलने के साथ ही आर्थिकी में भी तेजी आएगी।

महाराष्ट्र ने फिर सुधारा कोरोना का आंकड़ा, पहले हुई 3,509 मौतें जोड़ीं

आंकड़ों की बाजीगरी ▶ देश में 24 घंटे में मिले 42 हजार नए केस, मृतकों की संख्या 3,998

सक्रिय मामलों में भी हजार से ज्यादा की वृद्धि, एक्टिव केस 4.07 लाख हुए

जेएनएन, नई दिल्ली : महाराष्ट्र ने कोरोना से जुड़े आंकड़ों को सुधारना शुरू कर दिया है और एक दिन में पहले हुई 3,509 मौतें और 2,479 मामलों को जोड़ा है। इससे देश के आंकड़े में उछाल आ गया है और बीते 24 घंटे में 42 हजार से ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं। एक दिन पहले 30 हजार नए मामले मिले थे। सक्रिय मामलों में भी वृद्धि दर्ज की गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बुधवार सुबह आठ बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र की तरफ से पिछले दिनों हुई मौतों को जोड़ने से पिछले एक दिन में मृतकों की संख्या 3,998 हो गई है, इसमें महाराष्ट्र में 3,656 और केरल में 104 मौतें शामिल हैं। महाराष्ट्र 14वीं बार कोरोना के आंकड़ों को जोड़ने का सिलसिला शुरू किया है। दैनिक आंकड़ों के बढ़ने से सक्रिय में भी एक हजार से ज्यादा की वृद्धि हुई है और एक्टिव केस कुल मामलों का 1.30 फीसद हो गए हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि राज्य के कई हिस्सों से दैनिक डाटा उपलब्ध न हो पाने के कारण मंगलवार को एक साथ 3,656 मौतों के आंकड़े जारी किए गए।

11 राज्यों से उप्र आने वालों को चाहिए निगेटिव रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

यूपी में कोरोना का संक्रमण दोबारा न बढ़े इसके लिए सख्त उपाए किए जा रहे हैं। ऐसे 11 राज्य जहां पर पाजिटिविटी रेट ज्यादा है, वहां से आने वाले यात्रियों को कोरोना की आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट या फिर टीके की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इन दोनों में से कोई एक अभिलेख दिखाने पर ही उन्हें यूपी में आने की इजाजत होगी। पिछले चार दिनों में कराई गई कोरोना की जांच रिपोर्ट ही मान्य होगी।

अपर मुख्य सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 24 जुलाई से प्रदेश में यह नई व्यवस्था लागू होगी। सभी हवाई अड्डे, रेलवे व बस स्टेशनों पर बाहर से आने वाले लोगों पर सख्ती की जाएगी। जिन 11 राज्यों में साप्ताहिक पाजिटिविटी रेट तीन प्रतिशत से अधिक है उनमें महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नगालैंड व अरुणाचल प्रदेश शामिल है। प्रदेश में 80 हजार निगरानी कमेटियों को अलर्ट कर दिया गया है।

बुधवार शाम छह बजे तक किस राज्य में कितने टीके	
उत्तर प्रदेश	4.13 लाख
राजस्थान	2.91 लाख
पंजाब	1.76 लाख
महाराष्ट्र	0.98 लाख
झारखंड	0.76 लाख
दिल्ली	0.61 लाख
छत्तीसगढ़	0.35 लाख
उत्तराखंड	0.28 लाख
हरियाणा	0.24 लाख
बिहार	0.13 लाख
जम्मू-कश्मीर	0.08 लाख

देश में कोरोना की स्थिति	
24 घंटे में नए मामले	42,015
कुल सक्रिय मामले	4,07,170
24 घंटे में टीकाकरण	34.18 लाख
कुल टीकाकरण	41.54 करोड़

नए मामले	कुल मामले
42,015	3,12,16,337
सक्रिय मामले	**ठीक होने की दर**
4,07,170	97.36%

मौतें (24 घंटे में)-3,998 (इसमें महाराष्ट्र में पिछले दिनों हुई 3509 मौतें शामिल हैं)

मृत्यु दर	1.34 फीसद

देश में टीकाकरण के मामले में चेन्नई अव्वल

कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश भर में तेजी से टीकाकरण चल रहा है। अब तक 41 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। पांच मेट्रो शहरों में चेन्नई सबसे तेजी से टीका लगाने वाला शहर बन गया है। कोविन एप के मुताबिक 20 जुलाई तक यहां नौ लाख 11 हजार लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। बता दें कि शहर की कुल आबादी 78.53 लाख है, जिसमें 59.46 लाख लोगों को टीका लगाया जाना है। (स्रोत: प्रेट्र)

टीके के दोनों डोज (20 जुलाई तक)	
चेन्नई	12%
बेंगलुरु	10%
मुंबई	8%
दिल्ली	7%
हैदराबाद	6%

अधिकांश बच्चों को संक्रमित नहीं कर पाएगी तीसरी लहर

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कोरोना की तीसरी लहर खासकर बच्चों के लिए काफी खतरनाक मानी जा रही है। मगर प्रवेश द्वार पर एंटीबाडी का सख्त पहरा है। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर अधिकांश बच्चों को संक्रमित नहीं कर पाएगी, क्योंकि ज्यादातर बच्चों में एंटीबाडी विकसित हो चुकी है। यह दावा है कोलकाता के इंस्टीट्यूट आफ चाइल्ड हेल्थ के चिकित्सकों का।

एंटीबाडीज का मतलब मजबूत इम्युनिटी होता है। शरीर आमतौर पर दो तरह से प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। पहला किसी बीमारी से संक्रमित होने के बाद और दूसरा उसी बीमारी का टीका लगाए जाने के बाद। यही हाल कोविड-19 का भी है। हाल में इंस्टीट्यूट आफ चाइल्ड हेल्थ में 18 साल से कम उम्र के 100 बच्चों के लिए कोरोना टीका का ट्रायल शुरू किया गया था। इस दौरान 50 से अधिक बच्चों को जाइडस कैडिला का टीका नहीं लगाया जा सका, क्योंकि उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में एंटीबाडी पाई गई। इस सिलसिले में संस्थान के बाल रोग विशेषज्ञ डा. प्रभासप्रसून गिरि ने बताया कि दरअसल यह सभी बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके थे, लेकिन कोई लक्षण नहीं होने के कारण उनके परिजनों को पता नहीं चला। ये बच्चे खुद ब खुद ठीक भी हो गए तथा कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए प्रोटीन कोशिकाएं (एंटीबाडी) अर्जित कर चुके हैं।

संक्रमण से बनने वाली एंटीबाडी की सीमा थोड़ी अधिक : अब सवाल यह है कि यह एंटीबाडी बच्चों को कब तक सुरक्षा मुहैया कराएगी? बाल रोग विशेषज्ञ डा. जयदीप चौधरी का कहना है कि इसका स्तर धीरे-धीरे घटता है इसलिए यह नहीं कह सकते हैं कि एंटीबाडी कब तक रहेगी।

मां बनाने वाले हार्मोन ने बचाई कोरोना से महिलाओं की जान

अजय दुबे, आगरा

मां बनाने वाले हार्मोन (एस्ट्रोजन) ने कोरोना से महिलाओं की जान बचा ली। कोरोना संक्रमित पुरुषों की तुलना में महिलाओं की मौत कम हुई। एसएन (सरोजिनी नायूडू) मेडिकल कालेज में 720 कोरोना संक्रमित मरीजों पर हुई स्टडी में सामने आया है कि एस्ट्रोजन हार्मोन ने कोरोना वायरस के रिसेप्टर को ब्लाक कर दिया। इससे जिन महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर अधिक था, उनकी जान बच गई।

सात महीने के अंतराल में संक्रमितों पर किया अध्ययन: यह स्टडी एसएन मेडिकल कालेज में मार्च 2020 से सितंबर 2020 के बीच भर्ती हुए कोरोना संक्रमित मरीजों पर की गई। स्त्री रोग विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डा. रुचिका गर्ग ने बताया कि स्टडी में शामिल कोरोना मरीजों में 427 पुरुष और 293 महिलाएं थीं। इनमें से 83 पुरुषों (19.43 फीसद) की मौत हुई, जबकि सिर्फ 33 महिलाएं (11.26 फीसद) दुनिया से विदा हुईं।

एस्ट्रोजन ने वायरस के रिसेप्टर को कर दिया ब्लाक: महिला और पुरुषों के इलाज की गाइडलाइन एक ही थी। इन मरीजों की इलाज के दौरान शुगर के स्तर से लेकर हीमोग्लोबिन सहित अन्य जांच का आकलन किया गया। स्टडी में सामने आया कि महिलाओं में पीरियड और गर्भधारण के लिए जरूरी एस्ट्रोजन हार्मोन ने कोरोना वायरस के रिसेप्टर को ब्लाक कर दिया।

टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रिसेप्टर पर कोई असर नहीं: पुरुषों में पाए जाने वाले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन (सेक्स हार्मोन) का कोरोना वायरस के रिसेप्टर पर कोई असर नहीं दिखा। इससे महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा संक्रमित हुए और मौत भी ज्यादा हुई। एसएन मेडिकल कालेज के प्राचार्य डा. संजय काला ने बताया कि यह स्टडी जर्नल आफ मिड लाइफ हेल्थ में प्रकाशित हुई है।

शोध

- एसएन मेडिकल कालेज में 720 कोरोना संक्रमित मरीजों पर की गई स्टडी
- पुरुषों की तुलना में महिलाओं की मौत हुई कम, हार्मोन से रिसेप्टर हुआ ब्लाक


हार्मोन का सुरक्षा चक्र। फाइल फोटो

रजोनिवृत्ति के बाद संक्रमित होने पर महिलाओं की मौत ज्यादा

स्टडी में महिलाओं के दो ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप में जिन महिलाओं के पीरियड आ रहे थे और मां बन सकती थीं। दूसरे ग्रुप में जिन महिलाओं के पीरियड बंद (रजोनिवृत्ति, मीनोपाज) हो गए। रजोनिवृति में स्ट्रोजन का स्तर कम हो जाता है। इसलिए कोरोना संक्रमित 108 रजोनिवृत्त महिलाओं में से 17 (15.07 फीसद) की मौत हुई, जबकि दूसरे ग्रुप की 185 महिलाओं में से 16 (8.64 फीसद) की मौत हुई।

राष्ट्रीय फलक

नई पीढ़ी की आकाश समेत दो मिसाइलों का परीक्षण

नई दिल्ली, एएनआइ

आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और भारतीय सेना की ताकत और मजबूत करने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने बुधवार को दो स्वदेशी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। इनमें से एक कम वजन, फायर एंड फार्गेट मैन पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (एमपी-एटीजीएम) और दूसरी सतह से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल (आकाश-एनजी) है।

आधिकारिक बयान के मुताबिक मैन-पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल को थर्मल साइट के साथ एकीकृत मैन पोर्टेबल लांचर से दागा गया और इसने एक टैंक की नकल कर रहे लक्ष्य को सफलतापूर्वक दागा। इसे मनुष्य द्वारा ढो सकने वाले ट्राइपाड से दागा गया। डीआरडीओ ने बताया कि एमपी-एटीजीएम ने सीधे हमले मोड में लक्ष्य को भेदा और उसे सटीक तरीके से नष्ट कर दिया। इसके साथ ही परीक्षण ने न्यूनतम सीमा को सफलतापूर्वक सत्यापित किया। मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया गया। इस मिसाइल का अधिकतम सीमा के लिए सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया जा चुका है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप में विकसित इस मिसाइल में एक छोटा अत्याधुनिक इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर भी लगाया गया है। इस परीक्षण के साथ ही तीसरी पीढ़ी की इस मिसाइल के विकास का काम लगभग पूरा हो गया है। बालेश्वर से हमारे संवाददाता के मुताबिक इसमें हवाई खतरों को बेअसर करने की उच्च क्षमता है। नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल को डीआरडीओ की प्रयोगशाला के साथ मिलकर हैदराबाद स्थित डीआरडीएल द्वारा विकसित किया गया है। 560 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर व्यास वाली यह मिसाइल 60 किलोग्राम वजन विस्फोटक ढोने की क्षमता रखती है।


भारत ने बुधवार को ओडिशा के चांदीपुर तट पर आकाश मिसाइल की नई पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एएनआइ

फ्रांस से तीन राफेल विमान और मिले

नई दिल्ली, प्रेट्र : फ्रांस से तीन राफेल लड़ाकू विमान और भारत पहुंच गए हैं। फ्रांस से मिलने वाली राफेल विमानों की यह सातवीं खेप है। इन विमानों के आने से वायु सेना की मारक क्षमता और मजबूत हो गई है। इन विमानों को भारतीय वायु सेना के दूसरे स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा, जिसे चीन की सीमा के करीब बंगाल के हासिमारा एयरबेस पर बनाया गया है। राफेल विमानों का पहला स्क्वाड्रन अंबाला वायु सेना स्टेशन में है। एक स्क्वाड्रन में करीब 18 लड़ाकू विमान होते हैं। इन तीन विमानों के आने के साथ ही फ्रांस से अब तक 24 राफेल विमान मिल चुके हैं। दोनों देशों के बीच हुए सौदे के तहत भारत को कुल 36 राफेल विमान मिलने हैं। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद इन विमानों ने आठ हजार किलोमीटर की दूरी बिना रुके तय की। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की वायु सेना ने रास्ते में हवा में ही इन विमानों को ईंधन उपलब्ध कराया। इसके लिए भारतीय वायु सेना ने यूएई वायु सेना का आभार जताया है।

दो साल बाद सरहद पर साझा हुई बकरीद की खुशियां

राज्य ब्यूरो, जम्मू

जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा से लेकर उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) तक सरहद पर गत पांच माह से शांति का सुखद परिणाम बुधवार को भारत और पाकिस्तान के बीच साझा हुईं ईद-उल-जुहा (बकरीद) की खुशियों के रूप में सामने आया है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के छह सेक्टरों में बीएसएफ की चौकियों पर दो साल बाद भारत और पाकिस्तान के बीच मिठाइयों का आदान-प्रदान हुआ है। वर्ष 2019 में पुलवामा हमले के बाद से दोनों देशों के बीच सरहद पर मिठाई के आदान-प्रदान की प्रक्रिया को रोक दिया गया था। पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि, नियंत्रण रेखा पर बीते तीन माह में यह दूसरा अवसर है जब दोनों देशों के बीच मिठाइयों का आदान-प्रदान हुआ है। इसके पहले रमजान माह में एलओसी पर मिठाइयां भेंट की गई थीं।

जम्मू संभाग में 192 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बुधवार को हीरानगर, सांबा, रामगढ़, आरएसपुरा, अरनिया व परगवाल सेक्टरों में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पाकिस्तानी रेंजरों को मिठाई भेंट की। इसके अलावा एलओसी पर भी यही नजारा रहा।


बकरीद के अवसर पर बुधवार को अटारी बार्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल मुहम्मद हसन को मिठाई भेंट करते बीएसएफ के कमांडेंट अंजन भोला। सौ. बीएसएफ

'कुर्बानी' के विरोध में मुस्लिम युवक का रोजा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

देश भर में बुधवार को ईद-उल-अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। यूं तो देश के तमाम हिस्सों में इस दिन जानवरों की कुर्बानी देने की रवायत पूरी की जा रही है, लेकिन बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक शख्स ऐसा भी है जो कुर्बानी की इस प्रथा का अनोखे तरीके से विरोध कर रहा है। कोलकाता निवासी अल्ताब हुसैन ने जानवरों की कुर्बानी के विरोध में 72 घंटे का रोजा रखा है। अल्ताब कहते हैं कि पशुओं के प्रति क्रूरता की ऐसी परंपराओं को रोकना चाहिए। ये बताने के लिए कि पशुओं की बलि जरूरी नहीं है, मैंने स्वयं भी 72 घंटों का रोजा रखा है। 2014 में पशुओं के अधिकारों के लिए काम शुरू करने वाले अल्ताब मांसाहारी खाना नहीं खाते और चमड़े से बने उत्पादों का प्रयोग भी नहीं करते हैं। अल्ताब का कहना है कि तीन साल पहले उनके भाई एक जानवर को कुर्बानी के लिए घर लाए थे।

बदरीनाथ धाम में नमाज के दौरान शारीरिक दूरी न होने पर 15 पर मुकदमा

जासं, चमोली : बदरीनाथ धाम में 15 श्रमिकों के नमाज पढ़ने पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताते हुए इसे आस्था पर प्रहार बताया है। इस प्रकरण में इन संगठनों के प्रतिनिधियों ने पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। इस पर पर्यटन मंत्री ने चमोली के पुलिस अधीक्षक को जांच के आदेश दिए। इसके बाद पुलिस ने सभी श्रमिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि इन सभी ने एक ही कमरे में नमाज पढ़कर शारीरिक दूरी के मानकों का उल्लंघन किया है।

इन दिनों बदरीनाथ धाम में आस्था पथ पर पार्किंग का निर्माण चल रहा है। वहां 15 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। ये सभी पार्किंग एरिया में ही रहते हैं। बुधवार को ईद के दिन इन सभी ने नमाज पढ़ी। इस पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई। पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की थी।

जल सेवा

श्योपुर के 70 साल के रामपाल प्रजापति का मानवता की सेवा का अनूठा जज्बा, भीषण गर्मी हो या हाड़ कंपा देने वाली ठंड, तिराहे पर पानी पिलाना नहीं भूलते

24 साल पहले किया वादा, आज भी निभा रहे हैं

देवेंद्र गौड़, ग्वालियर

दोस्त ने मरते समय वचन लेते हुए कहा था... प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा पुण्य कोई नहीं। यह काम करोगे तो मेरी आत्मा को बड़ा सुकून मिलेगा। बचपन के दोस्त की बात मानकर एक बुजुर्ग पिछले 24 साल से राहगीरों को पानी पिला रहे हैं। चाहे कोई भी मौसम हो, वह एक भी दिन राहगीरों को पानी पिलाना नहीं भूलते। अगर वह कहीं बाहर गए तो पत्नी इसका निर्वाह करती हैं।

यह कहानी है श्योपुर जिले में जावदेश्वर गांव के 70 साल के रामपाल प्रजापति की। वह श्योपुर से 20 किलोमीटर दूर पाली हाइवे के भोगिका तिराहे पर बाल्टी में पानी लेकर दिनभर मौजूद रहते हैं। जैसे ही कोई बस या अन्य वाहन रुकता है, वे बाल्टी व लोटे में पानी लेकर उसके पास पहुंच जाते है। पैदल हो या बाइक से गुजर रहा कोई राहगीर, अगर वह भोगिका तिराहे पर रुकता है तो रामपाल उससे पानी पीने का आग्रह जरूर करते हैं। पिछले 24 साल से वे प्यासों को पानी पिलाने का काम कर रहे हैं।

हर मौसम में रामपाल मुस्तैद: जावदेश्वर के पूर्व सरपंच सुल्तान मीणा बताते हैं कि रामपाल को हर मौसम में पानी पिलाते देखा है। भीषण गर्मी में जब सड़क पर निकलना दूभर होता है, तब भी रामपाल बाल्टी में ठंडा पानी लेकर यात्रियों के पास पहुंच जाते हैं। रामपाल के परिवार में पत्नी रामनाथी बाई के अलावा दो बेटे हैं। बड़े बेटे की शादी हो गई तो वह पत्नी को लेकर अलग रहने लगा। छोटा बेटा दिव्यांग है जो रामपाल के साथ ही रहता है। उन्हें और उनकी पत्नी के अलावा दिव्यांग बेटे को शासन से जो पेंशन मिलती है, उसी से परिवार का खर्चा चलाते हैं।


भोगिका तिराहे से गुजरने वाले हर वाहन तक रामपाल की ओर से मुफ्त पानी की सेवा दिनभर हाजिर रहती है। नईदुनिया

आत्मा को सुकून मिलेगा...

रामपाल बताते हैं कि मेरा दोस्त पहले यह काम करता था। उसने मौत से पहले वचन लिया था कि प्यासे को पानी पिलाओगे तो हमेशा खुश रहोगे। दोस्त ने भी कहा था, पैसा नहीं, आत्मा को इतना सुकून मिलेगा कि किसी भी चीज की चाह नहीं रहेगी। जिस दिन मैं नहीं आता तो पत्नी रामनाथी बाई आती हैं, लेकिन यह काम कभी नहीं छोड़ा।

'अटल जी राम तो लक्ष्मण थे बाबूजी'

जागरण संवाददाता, लखनऊ

पूर्व मंत्री, बिहार व मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की प्रथम पुण्यतिथि पर बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य ने उनकी साढ़े बारह फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। नगर निगम की ओर से हजरतगंज में मल्टीलेवल पार्किंग के सामने यह प्रतिमा लगाई गई है। यह वही स्थान है जहां पहले हजरतगंज कोतवाली हुआ करती थी और बाबूजी ने कई बार धरना दिया था।

प्रतिमा के अनावरण के बाद रक्षा मंत्री ने लालजी टंडन के साथ बिताए समय की स्मृतियां साझा की। उन्होंने कहा कि टंडन जी को लोग विकास पुरुष के नाम से पुकारते थे। अटल जी के साथ उनकी विशेष भूमिका रही। मैं अटल जी को श्रीराम तो टंडन जी को लखनऊ के लक्ष्मण की तरह देखता हूं। बाबूजी को लखनऊ के बारे में जितनी बारीक जानकारी थी, उतना किसी के पास नहीं थी। संबंधों का निर्वाह करना उनसे सीखना चाहिए। हर पार्टी के लोगों से उनके संबंध अच्छे थे। मायावती जब मुख्यमंत्री थीं तो उन्होंने कहा था कि टंडन जी मेरे भाई हैं। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं मनभेद नहीं।

इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लालजी टंडन को श्रद्धांजलि अर्पित की और नगर निगम बोर्ड व महापौर को बधाई दी। उन्होंने कहा कि टंडन जी ने पार्षद से लेकर नगर विकास मंत्री तक का सफर तय किया। दो राज्यों में राज्यपाल रहे। समाज के हर तबके में उनके प्रशंसक हैं। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन इस अवसर पर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैं मंत्री के रूप में एक जनप्रिय राजनेता की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर शामिल हूं। इस स्थान से बाबूजी का बहुत गहरा नाता रहा है। हालांकि एक पुत्र के रूप में उनकी प्रतिमा को देखना मेरे लिए भावुक क्षण है।

रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री को सराहा: राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री की सराहना की। बोले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अराजकता का माहौल समाप्त कर देश भर में शोहरत पाई है। उनके नेतृत्व में विकास को रफ्तार मिली है। मुख्यमंत्री ने मास्क हटाकर भाषण नहीं दिया तो मैं भी मास्क नहीं हटाऊंगा।


पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी साढ़े बारह फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का लोकार्पण करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। साथ में हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जागरण

बायजूस ने 3700 करोड़ में एपिक को खरीदा

नई दिल्ली : देश की सबसे मूल्यवान स्टार्ट-अप में शुमार बायजूस ने अमेरिका स्थित डिजिटल रीडिंग प्लेटफार्म एपिक का अधिग्रहण किया है। यह सौदा 50 करोड़ डालर (लगभग 3,729.8 करोड़ रुपये) में हुआ। इसके अतिरिक्त कंपनी उत्तर अमेरिकी बाजार में एक अरब डालर (लगभग 7,459.7 करोड़ रुपये) का और निवेश करेगी। एपिक के पास दुनिया के 250 से अधिक सर्वश्रेष्ठ प्रकाशकों की 40,000 से अधिक पुस्तकों के साथ ही आडियो और वीडियो का संग्रह है। (प्रेट्र)

सहकारी संस्थाओं को सरकार द्वारा नया मंत्रालय बनाने के बाद बड़ी उम्मीद जगी थी। लेकिन 97वें संविधान संशोधन कानून की कुछ धाराओं को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खत्म कर दिए जाने से इस सेक्टर पर बुरा असर पड़ेगा।
– दिलीप संघानी, प्रेसिडेंट, एनसीयूआइ



ग्राहकों को पसंद नहीं आनलाइन डिस्काउंट पर सरकार का प्रतिबंध

नई दिल्ली, प्रेट्र : करीब 72 फीसद आनलाइन कस्टमर नहीं चाहते हैं कि ई-कामर्स प्लेटफार्म पर बिकने वाले उत्पादों पर मिलने वाली भारी-भरकम छूट पर सरकार किसी तरह की रोक लगाए। लोकल सर्किल द्वारा हाल ही में किए गए एक शोध में सामने आया है कि पिछले 12 महीनों के दौरान 49 फीसद ग्राहकों ने खरीदारी के लिए आनलाइन का विकल्प चुना। बड़ी संख्या में उपभोक्ता इस माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। यह उनके लिए न केवल सुविधाजनक है बल्कि सुरक्षित भी है। इतना ही नहीं प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रदान करने के साथ ही पसंद नहीं आने पर रिटर्न की गारंटी भी देता है।



394 जिलों में हुआ सर्वे

82,000 से पूछे गए सवाल

छह से 12 महीनों तक रहेगा अनिश्चितता का दौर

सर्वे में कहा गया है कि लगभग 47 फीसद उपभोक्ताओं का मानना है कि कोरोना महामारी के चलते पैदा हुई अनिश्चितता का असर अगले छह से 12 महीनों तक रहेगा। ऐसे में अगर ई-कामर्स प्लेटफार्म पर मिलने वाले प्रोडक्ट पर दी जाने वाली छूट में कमी की जाती है तो इससे उनके बजट पर फर्क पड़ेगा।

43 फीसद उपभोक्ताओं ने मैन्युफैक्चरिंग देश की जानकारी मांगी

सर्वे के दौरान यह भी पाया गया कि लगभग 43 फीसद उपभोक्ताओं ने पिछले छह महीनों के दौरान आनलाइन खरीदारी करते समय सामान किस देश में बना (मैन्युफैक्चरिंग कंट्री) है, इसकी जानकारी मांगी। हालांकि कंज्यूमर इस बात पर एकमत नहीं थे कि सामान किस देश में बना है, इसकी जानकारी टेक्स्ट या इमेज प्रारूप में प्रदर्शित की जानी या नहीं।

फ्लैश सेल पर लग सकती है पाबंदी

केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कामर्स) नियम, 2020 का एक मसौदा तैयार किया है। फिलहाल इस पर लोगों से सुझाव मांगे गए हैं, लेकिन अगर नए नियम लागू हो जाते हैं तो बहुचर्चित फ्लैश सेल पर पाबंदी लग सकती है। इतना ही नहीं नए नियमों के तहत ई-कामर्स प्लेटफार्म पर गलत जानकारी और बंपर छूट के साथ धोखाधड़ी पूर्ण बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और डीपीआइआइटी के साथ इन कंपनियों का पंजीकरण अनिवार्य करने का भी प्रस्ताव है।

स्वदेशी जागरण मंच ने कहा, व्यापारियों के हितों का भी रखा जाए ध्यान

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोगी संगठन स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने बुधवार को प्रस्तावित उपभोक्ता संरक्षण ई-कामर्स नियमों में कई संशोधनों का सुझाव दिया। मंच ने कहा कि सरकार को इससे जुड़े व्यापारियों और सर्विस प्रोवाइडरों की सुरक्षा के लिए भी प्रविधान करना चाहिए। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को दिए गए सुझाव में मंच ने कहा कि यह एक आम धारणा है कि ई-कामर्स के लिए जो नियम तैयार किए गए हैं, उसमें सभी पक्षों को शामिल किया गया है। यह पूरी सच नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण कानून व्यापारियों और सर्विस प्रोवाइडरों पर लागू नहीं होता है। मंच ने ई-कामर्स कंपनियों के डीपीआइआइटी में अनिवार्य पंजीकरण का जहां स्वागत किया है, वहीं बहुत छोटी ई-कामर्स कंपनियों को पंजीकरण की अनिवार्यता से बचाने के लिए एक सीमा निर्धारित करने का सुझाव दिया है।

दिवालिया प्रक्रिया के नियमों में संशोधन

नई दिल्ली, प्रेट्र : इंसाल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड आफ इंडिया ने कारपोरेट व्यक्तियों से जुड़ी दिवालिया प्रक्रिया के नियमों में संशोधन किया है। माना जा रहा है कि ऐसा करने से पारदर्शिता बढ़ेगी और अनुशासन व जवाबदेही को भी बढ़ावा मिलेगा। संशोधित नियम 14 जुलाई से लागू हो गए हैं।

नय नियमों के तहत एक समाधान पेशेवर यह पता लगाने के लिए कर्तव्यबद्ध है कि कारपोरेट देनदार (सीडी) जबरन कर्ज लेनदेन, धोखाधड़ी और गलत व्यापार में शामिल है या नहीं। ऐसा होने से न सिर्फ ऐसे लेनदेन में डूबी रकम वापस मिल सकती है, बल्कि समाधान योजना के माध्यम से कारपोरेट देनदार के रिस्ट्रक्चरिंग की संभावना बढ़ जाती है।

इस संशोधन के तहत सीआइआरपी (कारपोरेट इंसाल्वेंसी रिजाल्यूशन प्रोसेस) का संचालन करने वाले इंसाल्वेंसी प्रोफेशनल (आइपी) के लिए यह आवश्यक होगा कि वे कारपोरेट देनदार के वर्तमान नाम और पंजीकृत कार्यालय के पते के साथ दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने से दो वर्ष पूर्व तक की अवधि में उसके नाम अथवा पंजीकृत कार्यालय के पते में हुए बदलावों को बताएं। इतना ही नहीं सभी तरह के रिकार्ड में भी इसका जिक्र किया जाए।

चीन का टेक्सटाइल आइटम अमेरिका में प्रतिबंधित, भारतीय निर्यातकों के लिए मौका

हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बांग्लादेश व वियतनाम से करना होगा कड़ा मुकाबला

राजीव कुमार • नई दिल्ली

चीन के शिनजियांग के काटन से बने टेक्सटाइल व अपैरल उत्पाद पर अमेरिका में प्रतिबंध से भारतीय निर्यात को फायदा मिल सकता है। टेक्सटाइल निर्यातकों ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। लेकिन उन्हें वियतनाम और बांग्लादेश से कड़ा मुकाबला करना होगा। हालांकि हाल ही में गारमेंट निर्यात के लिए रिबेट आफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स एंड लेवी (आरओएससीटीएल) स्कीम को फिर से शुरू करने से निर्यातकों को इसका फायदा मिल सकता है। चीन का 80 फीसद काटन उत्पादन शिनजियांग में होता है। वैश्विक रूप से भी शिनजियांग काटन उत्पादन का सबसे बड़ा इलाका है, जहां विश्व का कुल 20 फीसद उत्पादन होता है। यहां की फैक्ट्रियों में जबरन मजदूरी कराने के चलन से अमेरिका ने चीन के इस इलाके में बने काटन से सभी उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

निर्यातकों के मुताबिक अमेरिका के टेक्सटाइल व अपैरल बाजार में चीन की हिस्सेदारी लगभग 30 फीसद है। अमेरिका सालाना लगभग 110 अरब डालर यानी करीब आठ लाख करोड़ रुपये मूल्य का टेक्सटाइल व अपैरल आयात करता है। ऐसे में भारत चीन की पांच फीसद हिस्सेदारी भी अपनी तरफ लाने में कामयाब हो जाता है तो यहां से निर्यात में दो अरब डालर तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

कंफेडरेशन आफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज (सिटी) के पूर्व अध्यक्ष संजय जैन कहते हैं, 'शिनजियांग के काटन से बने सभी उत्पादों को अमेरिका में प्रतिबंध लगाने से भारत को निश्चित रूप से फायदा मिलेगा और इसका असर दिखने भी लगा है। अमेरिका से भारतीय अपैरल निर्यातकों के पास आर्डर बढ़ रहे हैं। अमेरिका के कई बड़े गारमेंट ब्रांड भारतीय निर्यातकों से संपर्क भी कर रहे हैं।' गारमेंट निर्यातक एवं अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नार्दर्न चेयरमैन ललित ठुकराल ने बताया, चीन इन दिनों भारत से भारी मात्रा में काटन और यार्न का आयात कर रहा है। उससे अपैरल बनाकर चीन 'मेड फ्राम इंडियन काटन' लिखकर अमेरिका को सप्लाई कर सकता है। पिछले कुछ माह से काटन और यार्न के निर्यात में भारी वृद्धि से गारमेंट निर्माण की लागत बढ़ गई है।


अमेरिका के टेक्सटाइल आयात में चीन की हिस्सेदारी हो रही कम • फाइल फोटो

30 फीसद हिस्सेदारी है अमेरिका के टेक्सटाइल और अपैरल बाजार में चीन की

80 फीसद काटन उत्पादन शिनजियांग में होता है चीन का, वैश्विक रूप से यह सबसे बड़ा इलाका

काटन के निर्यात में 69 फीसद की हुई बढ़ोतरी

इस साल जनवरी से मई के दौरान काटन, यार्न, फैब्रिक और मेडअप्स के निर्यात में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 69 फीसद की बढ़ोतरी हुई है जबकि भारतीय गारमेंट निर्यात में इस अवधि में 39 फीसद का इजाफा हुआ है। पिछले साल अक्टूबर से लेकर इस साल मई तक कच्चे काटन के निर्यात में 55 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी मान रहे हैं कि पिछले दो-तीन वर्षों से अमेरिका के टेक्सटाइल आयात में चीन की हिस्सेदारी कम हो रही है, लेकिन इसका फायदा अभी भारत को नहीं मिला है क्योंकि भारतीय उत्पाद बांग्लादेश और वियतनाम के उत्पाद के मुकाबले महंगे होते हैं। 2019 में टेक्सटाइल और अपैरल का वैश्विक निर्यात बाजार 818 अरब डालर का था, जिसमें चीन की हिस्सेदारी सबसे अधिक 32 फीसद थी। भारत का टेक्सटाइल व अपैरल निर्यात 2019 में मात्र 35.50 अरब डालर का था।

भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को शीर्ष तीन में शामिल करना लक्ष्य

नई दिल्ली, प्रेट्र : डिजिटल स्टार्टअप थिंकटैंक एडीआइएफ ने भारतीय स्टार्टअप से जुड़े परिवेश को 2030 तक वैश्विक स्तर पर शीर्ष तीन में शामिल करने के लिए एक योजना तैयार की है। इसके लिए ज्ञान का आधार बढ़ाना, सहयोग में वृद्धि और सही नीतिगत ढांचे की स्थापना पर जोर दिया जाएगा।

एलायंस आफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक सिजो कुरुविला जार्ज ने बताया कि स्टार्टअप को गूगल प्ले स्टोर और एपल एप स्टोर के साथ जिन मुद्दों का सामना करना पड़ता है, उस पर बातचीत करके दोनों पक्षों के लिए उपयुक्त रास्ते का पता लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा, 'अब हम वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप बाजार हैं और हमारे यहां 50 यूनिकार्न स्टार्टअप हैं। हम सिर्फ अमेरिका (122) और चीन (92) से पीछे हैं। हम आकार के मामले में तीसरे सबसे बड़े हैं, लेकिन भारतीय स्टार्टअप परिवेश रैंकिंग के मामले में 20वें स्थान पर है। अगर हम आकार में तीसरे सबसे बड़े हैं, तो हमें रैंकिंग में भी तीसरे स्थान पर रहने का लक्ष्य तय करना चाहिए। हमारा लक्ष्य भारतीय स्टार्टअप परिवेश को 2030 तक शीर्ष तीन में लाना है।

किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर सरकार ने काम किया तेज

सुरेंद्र प्रसाद सिंह • नई दिल्ली


केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर • फाइल फोटो

उत्पादन के साथ आय बढ़ाने पर रहा जोर, रफ्तार रही धीमी, कृषि कानूनों पर बढ़े विवाद से भी मंजिल हुई दूर

किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए एक वर्ष का समय और बचा है, लेकिन लक्ष्य अभी दूर है। कोरोना काल की इन विकट परिस्थितियों में कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन अन्य क्षेत्रों के मुकाबले बेहतर रहा, इसके बावजूद यह अपेक्षित रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। किसानों की आमदनी को दोगुना करने को लेकर केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर बड़े कदम उठाए हैं। इनमें खेती की लागत में कमी लाने और उसकी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया गया है। खेती में पैदावार के साथ आय बढ़ाने पर पूरा जोर दिया गया। कृषि कानूनों पर बढ़े विवाद से भी किसानों की डबल इनकम की मंजिल दूर हुई है।

2016-17 के आम बजट में सरकार ने किसानों की दशा सुधारने के लिए उनकी आमदनी को 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। किसानों की आमदनी के लिए वर्ष 2015-16 को आधार वर्ष मानकर नेशनल सैंपल सर्वे आफ इंडिया के अनुमान को लक्षित किया गया। उसके मुताबिक 2015-16 में मूल्यों के आधार पर किसानों की प्रति वर्ष औसत आमदनी 96,703 रुपये आंकी गई थी। उसे अगले छह वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके लिए मात्र वर्षभर का समय बचा है। लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने लोकसभा में पूछे गए एक लिखित सवाल के जवाब में बताया कि किसानों की आमदनी को लेकर अभी कोई ताजा सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

'डबलिंग फार्मर्स इनकम' यानी किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए 2016 में ही एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया था। दो वर्षों बाद उसकी रिपोर्ट आई, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि इस लक्ष्य को पाने के लिए कृषि की वार्षिक विकास दर अनवरत 10.4 फीसद रहना जरूरी होगा। लेकिन वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र की विकास दर 3.4 फीसद आंकी गई है।

आमदनी को दोगुना करने के लिए सरकार ने इस दिशा में कई लगातार प्रयास भी शुरू कर दिए। वर्ष 2013-14 में कृषि का बजट जहां मात्र 21,933 करोड़ रुपये था, वह वर्ष 2020-21 में 5.5 गुना बढ़कर 1,23,018 करोड़ रुपये पहुंच गया। सरकार का पूरा दबाव उत्पादकता के साथ पैदावार बढ़ाने और आमदनी में वृद्धि पर रहा। इसके लिए वर्ष 2018 में ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 50 फीसद की वृद्धि घोषित कर दी गई। दलहन का एमएसपी 95.93 गुना और तिलहनी फसलों का 10.80 गुना बढ़ा दिया गया। देश के हर क्षेत्र के किसानों को नकद सहायता के रूप में उसके बैंक खाते में सालाना 6,000 रुपये पीएम-किसान सम्मान निधि से दिया जाने लगा। फसलों को आपदाओं से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 23 करोड़ किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें से 7.6 करोड़ किसानों को उनकी फसलों के मुआवजे के रूप में 17,000 करोड़ रुपये प्रीमियम के मुकाबले 91,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

राष्ट्रीय फलक

न्यूज गैलरी

फ्लैट दिलाने का झांसा देकर हड़पे 98.60 लाख रुपये

लुधियाना : खरड़ में फ्लैट दिलाने का झांसा देकर गुरुग्राम व बरनाला के दो लोगों ने लुधियाना की एक स्कूल प्रिंसिपल के 98.60 लाख रुपये हड़प लिए। हैबोवाल थाना पुलिस ने बरनाला के माहल नगर के हरनेशपाल सिंह और गुड़गांव के फेस-1 स्थित सुशांक लोक के रहने वाले अनुराग शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। (जासं)

गुजरात में लाकअप में बंद दो संदिग्धों ने फांसी लगाई

अहमदाबाद : दक्षिण गुजरात के चीखली थाने के लाकअप में चोरी के संदेह में बंद दो संदिग्धों ने तार का फंदा लगाकर खुदकशी कर ली। पुलिस अधीक्षक की निगरानी में घटना की जांच की जाएगी। नवसारी के पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि बुधवार सुबह सुनील पंवार व रवि जाधव के शव लाकअप में मिले। आदिवासी जिले डांग के वघई के रहने वाले दोनों युवक चोरी के एक मामले में संदिग्ध थे। खुदकशी के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पूछताछ के लिए लाया गया था। (जासं)

भारत-पाक सीमा पर स्थित डिफेंस ड्रेन से लोहे के गेट व सामान चोरी

सुरक्षा में सेंध

जागरण संवाददाता, तरनतारन

भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित डिफेंस ड्रेन की मोर्चाबंदी पर लगाए गए लोहे के दरवाजे व अन्य सामान चोरी हो गया है। चोरी का यह मामला उस समय सामने आया जब एक वर्ष पहले सीमा पर तैनात बीएसएफ की यूनिट का तबादला हुआ। नई यूनिट द्वारा चार्ज संभालने के दौरान जब क्षेत्र का जायजा लिया गया तो वहां से उक्त सामान चोरी हुआ पाया गया। थाना खालड़ा में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

भारत-पाक सीमा स्थित सेक्टर खालड़ा के पास माड़ीमेघा से खालड़ा को जाती डिफेंस ड्रेन पर बीएसएफ द्वारा पक्के तौर पर मोर्चाबंदी की गई है। इस मोर्चाबंदी पर फौज व बीएसएफ के जवान उस समय तैनात होते हैं, जब सीमा पर तनाव की स्थिति पैदा होती है। डिफेंस ड्रेन की मोर्चाबंदी के बीच वाले रास्तों पर लोहे के दरवाजे लगाए गए थे। बीएसएफ की 103 बटालियन का यहां से तबादला दूसरी जगह होने पर नई बटालियन की तैनाती के दौरान जब नई बटालियन के जवानों ने डिफेंस ड्रेन का भी दौरा किया गया। बीएसएफ के रिकार्ड में डिफेंस ड्रेन पर स्थित पक्के मोर्चों पर लगाए गए 63 डोर प्लेट, 25 लूप होल व अन्य प्रकार का लोहे का सामान गायब पाया गया। गोरखा रेजिमेंट अंबाला कैंट से संबंधित सूबेदार शेर बहादुर कंवर ने थाना खालड़ा की पुलिस को लिखित शिकायत दी।

मोर्चाबंदी की जाती है: भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा की कंटीली तार से 50 से 200 मीटर की दूरी के बीच अपरबारी दोआब नहर आती है। इस अपरबारी दोआब नहर से 300 मीटर से 700 मीटर के घेरे में डिफेंस ड्रेन आती है। डिफेंस ड्रेन पर बीएसएफ द्वारा आपातकालीन स्थिति में मोर्चाबंदी की जाती है।


तरनतारन में पाक सीमा से सटी अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास डिफेंस ड्रेन का मुख्य रास्ता। जागरण

सुरक्षा में सेंध, व्यवस्था पर उठे सवाल

डिफेंस ड्रेन की दो माह पहले ही बीएसएफ द्वारा सफाई करवाई गई थी। ड्रेन के आसपास स्थानीय पुलिस द्वारा भी नजर रखी जाती है। ऐसे में डिफेंस ड्रेन की मोर्चाबंदी के दरवाजे आदि चोरी होना सुरक्षा-व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। थाना खालड़ा के प्रभारी इंस्पेक्टर तरसेम सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

पटना विवि के क्लोन चेक मामले में कंपनी का खाता सीज, प्रबंधक पर केस

जागरण संवाददाता, पटना : पटना कालेज के बैंक खाते से क्लोन चेक से 62.80 लाख रुपये की निकासी के मामले में पीरबहोर थाने की पुलिस ने इंडियन बैंक की पटना विश्वविद्यालय शाखा के प्रबंधक के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच में पता चला है कि खाते से रुपये गुजरात की ग्रीन वेजिटेबल कंपनी द्वारा अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्थित बैंक शाखा से निकाले गए हैं। बैंक खाते में बचे कंपनी के 42 लाख रुपये को फ्रीज कर दिया गया है। जांच के लिए पुलिस की टीम जल्द ही गुजरात जाएगी।

विदित हो कि पटना कालेज के मुख्य बैंक खाते से गुजरात की एक सब्जी कंपनी द्वारा क्लोन चेक से 62.80 लाख की निकासी कर ली गई है। कालेज प्रबंधन को तब चला जब किसी को दिया 16 हजार का चेक 17 जुलाई को बाउंस हो गया। कालेज प्रबंधन ने इंडियन बैंक की पटना विश्वविद्यालय शाखा के प्रबंधक को पत्र लिखकर पूछा था कि लापरवाही के लिए क्यों न उनके खिलाफ एफआइआर कराई जाए। क्योंकि, 50 हजार से अधिक की रकम निकालने से पहले बैंकों द्वारा सूचित करना होता है।

पति मृत्युशैय्या पर, पत्नी बनना चाहती है मां, अस्पताल ने की मदद

चाहत!

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

गुजरात हाई कोर्ट में दाखिल अपनी तरह के पहले मामले में अदालत के आदेश के बाद अस्पताल प्रबंधन ने गंभीर रूप से बीमार मरीज के स्पर्म को संरक्षित कर लिया। हाई कोर्ट ने यह आदेश एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को दिया था, जिसमें उसने बीमार पति के बच्चे की मां बनने की इच्छा जताई थी। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।

वडोदरा के एक अस्पताल में भर्ती मरीज की हालत अत्यंत गंभीर बताई जाती है। चिकित्सक कोविड-19 के इस मरीज के बचने की संभावना बेहद कम बता रहे हैं। वह चेतन अवस्था में नहीं है। इस बीच महिला ने अस्पताल प्रबंधन से अपने पति के बच्चे की मां बनने की इच्छा जताई। अस्पताल प्रबंधन व चिकित्सकों ने मरीज की स्थिति का हवाला देते हुए महिला को अदालत से इजाजत लेने की सलाह दी। उसने मंगलवार को अधिवक्ता निलय पटेल के जरिये गुजरात हाई कोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए एक याचिका दाखिल की। इसमें महिला ने कहा है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आइवीएफ) / असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलाजी (एआरटी) से उसे गर्भधारण की मंजूरी दी जाए। गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस एजे शास्त्री ने अपने अंतरिम आदेश में अस्पताल प्रबंधन को आइवीएफ / एआरटी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए मरीज के स्पर्म का नमूना लेकर उसे चिकित्सा पद्धति से अच्छी तरह संरक्षित करने का निर्देश दिया। अदालत ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार व अस्पताल प्रबंधन को 23 जुलाई को जवाब दाखिल करने को कहा है। हास्पिटल प्रबंधन ने बताया अदालत का आदेश मिलने के एक घंटे के भीतर मरीज का स्पर्म संरक्षित कर लिया गया।

64 सिम उगलेंगे राज, फर्जी एक्सचेंज से पाकिस्तान व खाड़ी देशों में लगे काल

जागरण टीम, पटना

पटना के अनीसाबाद में पकड़े गए फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज मामले में पुलिस ने मौके से बरामद कंप्यूटर, सीपीयू व 64 सिम कार्ड का डाटा खंगालना शुरू कर दिया है। प्रारंभिक जांच के अनुसार, सबसे अधिक काल पाकिस्तान व खाड़ी देशों जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरब, ओमान में किए गए हैं।

जांच टीम के अनुसार, फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का पूरा सिंडिकेट काम करता है। इसके मुख्य संचालक दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में बैठते हैं और छोटे-छोटे शहरों में अपना नेटवर्क तैयार करते हैं। अनीसाबाद में पकड़े गए फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज के तार सिलीगुड़ी से भी जुड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसका मुख्य संचालक सबीउल्लाह सिलीगुड़ी में रहता है। इसके पहले पिछले साल गांधी मैदान में पकड़े गए फर्जी एक्सचेंज मामले में भी नेपाल और दिल्ली का लिंक सामने आया था मगर कोई बड़ा खुलासा नहीं हो सका। इसी माह दिल्ली में लाल किले के पास भी फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश हुआ है।

फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज चलाने वाले सगे भाइयों, अनिल चौरसिया और सुशील चौरसिया को बुधवार को जेल भेज दिया गया। इस बाबत गर्दनीबाग थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

मासिक किराये पर कराते थे बात : पुलिस को पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वह सस्ती दर पर विदेशों में बात कराने के नाम पर कमाई करते थे। इस काम के लिए उनके क्लाइंट फिक्स थे जो एक बार में मासिक किराया देते थे। यह किराया हर दिन होने वाली बातचीत के समय पर आधारित होता था। जब उनसे खाड़ी देशों में ज्यादा बातचीत के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि बिहार के सिवान, गोपालगंज, छपरा आदि जिलों के अधिसंख्य लोग खाड़ी देशों में रोजगार के लिए रहते हैं, इसलिए वहां के काल ज्यादा हैं।

ऐसे काम करता था फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज

पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि विदेश से काल आने पर वह वीओआइपी (वायस ओवर इंटरनेट प्रोटोकाल टेक्नोलाजी) व राउटर की मदद से इंटरनेशनल काल को लोकल में कन्वर्ट कर देते थे। इसके लिए फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे में जिनके नंबर पर विदेशों से काल जाता था, उस पर लोकल नंबर ही दिखाई देता। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि बातचीत खुफिया विभाग या सरकार के गेटवे से होकर नहीं गुजरती है।

मणप्पुरम डकैती में शामिल बदमाश ने एनकाउंटर के डर से किया समर्पण

जागरण संवाददाता, आगरा

साहब! मैं प्रभात शर्मा। मणप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी की शाखा में डकैती डालने वालों में मैं भी शामिल था। मुझे एनकाउंटर का डर है, इसलिए आत्मसमर्पण करने आया हूं। बुधवार को यह शब्द कहने वाले युवक पर आगरा की कमलानगर थाना पुलिस को एकाएक विश्वास नहीं हुआ। पूछताछ में वह नरेंद्र उर्फ लाला गैंग का सदस्य ही निकला। उसने बताया कि गैंग के आगरा व नोएडा की तीन और शाखाओं में डकैती डालने की योजना थी।

कमला नगर स्थित मणप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी की शाखा में पड़ी डकैती में पुलिस लाला गैंग के चार सदस्यों को जगह-जगह तलाश रही है। गैंग का एक सदस्य प्रभात खुद ही बुधवार दोपहर थाने पहुंच गया। बकौल आइजी रेंज नवीन अरोरा प्रभात शर्मा थाने आने से पहले अपने कई परिचितों को आत्मसर्मपण करने के बारे में जानकारी देकर आया था। उसने घटना में शामिल होना स्वीकार किया है। प्रभात ने पुलिस को बताया कि सबसे पहले वह शाखा पर पहुंचा था। उसके संकेत देने पर ही अन्य बदमाश आए थे। बदमाश शाखा में प्रवेश कर गए तो वह पार्क में खड़ा होकर निगरानी करता रहा। वारदात के बाद वह अन्य साथियों के साथ निकल गया था।

सातवें बदमाश के बारे में भी मिली जानकारी

प्रभात शर्मा से पुलिस को सातवें बदमाश संतोष जाटव उर्फ चाचा के बारे में भी जानकारी मिली है। अब तक पुलिस घटना में छह बदमाशों का शामिल होना मानकर चल रही थी। पुलिस की 10 टीमें गैंग के सरगना व अन्य बदमाशों की तलाश में दबिश दे रही हैं।

बुजुर्ग अभिभावकों की देखभाल करना नैतिक ही नहीं बल्कि बाध्य कर्तव्य : हाई कोर्ट

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपनी मां के खिलाफ एक बेटे की अपील को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि बुजुर्ग अभिभावकों की देखभाल करना नैतिक कर्तव्य ही नहीं बल्कि मेंटेनेंस आफ पेरेंट्स एंड वेल्फेयर आफ सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत बाध्य भी है। अपील दाखिल करते हुए बेटे ने बताया कि फतेहाबाद में उसकी मां ने मेंटेनेंस आफ पेरेंट्स एंड वेलफेयर आफ सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया कि याची ने उससे दुकान ट्रांसफर करने को कहा था लेकिन धोखे से मकान भी ट्रांसफर करवा लिया। शिकायत पर एसडीएम ने मां द्वारा बेटे के नाम की गई मकान और दुकान की ट्रांसफर डीड को खारिज कर दिया था और याची को आदेश दिया था कि वह अपनी मां को हर माह दो हजार रुपये गुजारा भत्ता दे। इसके खिलाफ याचिका लगाई गई थी। जिसमें बेटे को राहत दे दिया गया था। इस आदेश को हाई कोर्ट ने पलट दिया।

बच्चे से कुकर्म के आरोपित को जमानत देने से हाई कोर्ट का इन्कार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आठ साल के बच्चे के साथ कुकर्म के एक आरोपित को यह कहते हुए जमानत देने से इन्कार किया कि अगर उसे रिहा किया गया, तो वह अन्य मासूम बच्चों को भी शिकार बना सकता है। जस्टिस एचएस मदान ने कहा कि ऐसे लोग समाज के लिए गंभीर खतरा हैं। आरोपित ने अपने घृणित कृत्यों से एक छोटे बच्चे के जीवन को खराब कर दिया है। याचिकाकर्ता विकृत यौन कृत्यों में लिप्त है। उसके इस तरह के आचरण को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में आरोपित मनमोहन सिंह के खिलाफ पुलिस स्टेशन झुनीर (मानसा) में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत इसी साल एक जनवरी को मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि वह दूसरी कक्षा के बच्चे को पैसे का लालच देकर कमरे में ले गया शोषण किया।

दैनिक जागरण

अपनी प्रसन्नता के निर्धारक आप स्वयं होते हैं

शरारत भरे आरोप

यह दोगलेपन और बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि जिन राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार को यह सूचना दी कि उनके यहां आक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, उन्हीं के नेता केंद्रीय सत्ता पर यह आरोप मढ़ रहे हैं कि वह सच्चाई को छिपा रही है। ऐसे शरारत भरे आरोप यह जानते हुए भी लगाए जा रहे हैं कि इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका बस इतनी ही है कि वह राज्यों की ओर से दिए गए आंकड़ों को संकलित कर उन्हें सार्वजनिक करती है। चूंकि स्वास्थ्य राज्य सरकारों का विषय है इसलिए केंद्र के पास यह जानने का कोई उपाय ही नहीं कि किस राज्य में कितने लोग आक्सीजन की कमी से मरे अथवा कोविड महामारी का शिकार बने? इस मामले में तो वह वही बता सकता है, जो राज्यों ने उसे बताया हो। यह कोई ऐसा तथ्य नहीं जिससे विपक्षी दल अनभिज्ञ हों, फिर भी वे राज्य सरकारों के हिस्से का दोष केंद्र सरकार पर मढ़ रहे हैं। आक्सीजन की कमी से हुई मौतों के मामले में केंद्र सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगा रहे विपक्षी नेता यदि यह समझ रहे हैं कि वे उसे अपने झूठ के कठघरे में खड़ा करके अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे अथवा राज्य सरकारों की भूमिका को छिपा ले जाएंगे तो यह संभव नहीं। जनता यह अच्छी तरह जानती है कि बीमारी-महामारी अथवा अन्य किन्हीं कारणों से होने वाली मौतों को दर्ज करने का अधिकार राज्यों के पास है।

हर लिहाज से यह राज्यों की जिम्मेदारी थी कि वे केंद्र को ईमानदारी से सूचित करते कि उनके यहां कितने लोग आक्सीजन की कमी से मरे, क्योंकि केंद्र सरकार तो चाहकर भी इस बारे में जानकारी हासिल नहीं कर सकती। बेहतर हो कि केंद्र पर निष्ठुर होने का आरोप मढ़ रहे विपक्षी नेता खुद को आईने में देखें और राज्य सरकारों को कठघरे में खड़ा करें, क्योंकि सच यही है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जब चरम पर थी, तब न जाने कितने लोग आक्सीजन की कमी से मरे। कई तो अस्पतालों में मरे। राज्य सरकारों को कम से कम आक्सीजन की कमी से अस्पतालों में मरे लोगों का विवरण तो रखना और केंद्र सरकार को बताना ही चाहिए था। कोई भी समझ सकता है कि यह विवरण इसीलिए सामने नहीं लाया गया, क्योंकि जो लोग आक्सीजन की कमी से मरे, उनकी मौत का कारण जानबूझकर कुछ और दर्ज किया गया। आखिर यह किसके कहने पर किया गया? यह लज्जाजनक है कि केंद्र सरकार को संवेदनशीलता का पाठ पढ़ा रहे विपक्षी नेता अपने शासन वाली राज्य सरकारों की गैर जिम्मेदाराना हरकत की अनदेखी करने पर तुले हैं।

सतर्कता आवश्यक

झारखंड के साइबर अपराधी पूरे देश की की नाक में दम किए हुए हैं। क्या नेता क्या अधिकारी, आम से लेकर खास तक हर वर्ग को साइबर ठग निशाना बना रहे हैं। हाल ही में साइबर अपराधियों ने आइपीएस अधिकारी जया राय के पिता साहिबगंज निवासी डा. एनआर राय के खाते से 5.90 लाख रुपये उड़ा लिए। वहीं, पिछले साल चेक क्लोनिंग कर महाराजगंज के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की सांसद निधि से 89 लाख रुपये निकालने के मामले में शामिल एक अपराधी बुधवार को ही साहिबगंज से गिरफ्तार हुआ है। अब तक साइबर अपराधियों का गढ़ जामताड़ा माना जाता था, लेकिन धीरे-धीरे साइबर ठग देवघर, गिरिडीह, रांची, साहिबगंज समेत अन्य इलाकों में भी फैल गए हैं। देश के दूसरे राज्यों और शहरों में भी झारखंड के ठगों ने बड़ी संख्या में लोगों को ठगा है। यही वजह है कि यहां के अपराधी दूसरे राज्यों की पुलिस के भी रडार पर हैं। ठगी कर ये अपराधी करोड़ों की संपदा अर्जित कर चुके हैं। नतीजा प्रवर्तन निदेशालय की नजरें भी इन पर टिकी हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि सरकार साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पूरी शिद्दत से जुटे। साइबर ठगी के लगातार बदलते तरीके को देखते हुए लोगों को जागरूक करते रहना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी जागरूकता से बड़ा नुकसान टाला जा सकता है। लोगों को मुफ्त में कुछ उपलब्ध करा रहे लोगों से भी सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं अपनी निजी और गोपनीय जानकारियां शेयर करने से पहले पूरी तरह जांच-परख कर आश्वस्त हो लेने की जरूरत है। ठग कस्टमर केयर नंबर, लिंक भेजकर, छोटी सी रकम मांगकर भी खाताधारकों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। फोन पर खुद को बैंक या किसी कंपनी का अधिकारी बताकर लोगों को झांसे में लेने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। किसी के कहने पर अनजान एप को डाउनलोड करने से भी लोग बचें। जागरूकता हमें ठगी से बचा सकती है। प्रशासन को भी ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए तत्परता दिखानी होगी। इन अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने की व्यवस्था हो, ताकि ठग लोगों को झांसा देने से पहले सौ बार सोचें।

साइबर ठगी का जाल फैलता जा रहा है, जिस पर लगाम लगाने के लिए गंभीर प्रयास करने ही होंगे। जागरूकता इसका सबसे अहम पहलू है

एक देश दो विधान वाले हालात



प्रदीप सिंह

ऐसा बार-बार क्यों देखने को मिलता है कि अदालतें हिंदू त्योहारों के प्रति एक रवैया अपनाती हैं और दूसरे त्योहारों के प्रति दूसरा?

क्या हमारे देश में दो विधान हैं? एक हिंदुओं के लिए और दूसरा बाकी पंथों को मानने वालों के लिए? यह सवाल देश की बहुसंख्यक आबादी के मन में बार-बार उठता है। यह धारणा किसी नेता के कहने से नहीं अदालतों और सरकारों के समय-समय पर किए गए निर्णयों और कामों से बनती है। नेता उसके बाद आते हैं। ताजा संदर्भ देश की सर्वोच्च अदालत के रवैये का है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर एक रुख और केरल में बकरीद पर बाजार खोलने के केरल सरकार के फैसले को लेकर दूसरा रुख। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। अब तीसरी लहर की आशंका बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार और अदालतें इस बात की चिंता करें कि ज्यादा लोग कहीं इकट्ठा न हों और कोविड प्रोटोकाल का पालन करें तो इसका स्वागत होना चाहिए। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में हर साल सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा की खबरों का स्वतः संज्ञान लिया तो अच्छा लगा कि शायद राज्य सरकार जो खतरा नहीं देख पा रही, वह अदालत ने देख लिया। कांवड़ यात्रा 25 जुलाई से शुरू होने वाली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके थे कि यात्रा पूरे कोविड प्रोटोकाल के तहत सीमित दायरे में होगी, पर सुप्रीम कोर्ट ने दस दिन पहले ही सरकार से कहा कि पुनर्विचार कीजिए नहीं तो हम रोक देंगे। कांवड़ यात्रा रुक गई। फिर केरल सरकार ने घोषणा की कि बकरीद के लिए लोग खरीदारी कर सकें, इसलिए 18 से 20 जुलाई तक दुकानें खुलेंगी। यह एकपक्षीय न लगे, इसलिए यह भी कहा कि इस बीच हिंदू सबरीमाला मंदिर जा सकते हैं।

केरल में इस समय कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा केस हैं। वहां संक्रमण की दर दस फीसद है और उत्तर प्रदेश में दशमलव दो फीसद। केरल में रोज दस हजार नए मामले सामने आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में सौ भी नहीं। पूरे देश को उम्मीद थी कि बस अभी सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा और केरल सरकार को रोकेगा। किसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सारे तथ्य रखे। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से जवाब मांगा जो सोमवार देर रात आया। कहा गया कि व्यापारियों के दबाव में आदेश दिया। सवाल है कि फिर सबरीमाला में दर्शन की छूट क्यों दी? सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को सरकार को लताड़ तो लगाई, पर आदेश रद नहीं किया, क्योंकि उसकी मियाद उसी दिन पूरी हो रही थी।

मकसद इस मुद्दे के कानूनी पहलुओं पर टिप्पणी करने का नहीं है। सवाल अलग-अलग रवैये से बनने वाली आम धारणा का है। कहते हैं न्याय होना ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। ऐसा बार-बार क्यों होता है कि अदालतें हिंदू त्योहारों के प्रति एक रवैया अपनाती हैं और दूसरे त्योहारों के प्रति दूसरा? इसी से लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या देश में दो विधान हैं। यदि नहीं तो फिर ऐसा क्यों होता है कि एक ही कानून की जो व्याख्या हिंदुओं के मामले में प्रस्तुत की जाती है, वह दूसरे पंथों के मामले में बदल जाती है?

ऐसा लगता है कि कानून के व्याख्याकार भी अपने को सेक्युलर कहने वाले दलों की ही तरह सोचते हैं। ये दल और इनके नेता हिंदुओं के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। कभी भगवा आतंकवाद तो कभी सांप्रदायिक हिंसा विरोधी विधेयक के जरिये कहा जाता है कि दंगा होने पर हिंदू ही आरोपित होंगे और उन्हें ही साबित करना होगा कि वे निर्दोष हैं। क्या इन दलों को हिंदुओं के वोट की जरूरत नहीं? मुसलमान मतदाताओं को लुभाने के लिए क्या हिंदुओं का विरोध जरूरी है? पता नहीं पर हो तो ऐसा ही रहा है। नेता ऐसा क्यों करते हैं? अदालतें और सरकारें ऐसा क्यों करती हैं?



अवधेश राजपूत

उसकी वजह इन सबको अच्छी तरह से पता है। इस सच्चाई को जानकर ही राजनीतिक दल और नेता हिंदुओं को अपमानित भी करते हैं और वोट भी लेते हैं, क्योंकि हिंदू कभी हिंदू की तरह नहीं सोचता। वह अपनी धार्मिक अस्मिता पर जातीय अस्मिता को वरीयता देता है। वह सामान्य तौर पर जातीय पहचान के अनुरूप ही आचरण करता है। हिंदुओं के मन में अपने धर्म के प्रति एक तरह की उदासीनता का भाव है। उन्हें जाति चले जाने का जैसा दर्द या डर होता है, वैसा धर्म के चले जाने से नहीं होता। जाति से लगाव है, धर्म सामाजिकता है। जाति से प्रेम करते हैं और धर्म का निर्वाह।

मुसलमान इसके ठीक उलट है। उनके लिए धर्म पर खतरा अस्तित्व पर खतरा है। वह संगठन की शक्ति को पहचानता है। इसलिए वह समाज, सरकार से लेकर न्यायालय तक ज्यादा प्रभावी है। इसलिए अदालत भी उनके बारे में किसी विषय पर विचार करते हुए यह तसल्ली कर लेना चाहती है कि इस मुद्दे पर शरिया या इस्लाम में क्या कहा गया है? संविधान की नजर में सभी भारतीय नागरिक बराबर हैं, पर दोनों समुदायों के लिए उसी संविधान के प्रविधानों की व्याख्या अलग-अलग की जाती है। हिंदुओं के रीति-रिवाज पर्यावरण और लोगों की सुविधा-असुविधा की कसौटी पर कसे जाते हैं। बाकियों के रीति-रिवाज, त्योहार उनकी धार्मिक मान्यताओं की कसौटी पर। यह इस देश का न्यू नार्मल हो गया है। यही एक नई परिपाटी बन गई है। हमने स्वीकार कर लिया है कि यही वास्तविकता है और इसे बदला नहीं जा सकता। देश की सर्वोच्च अदालत भी हिंदुओं के बारे में कोई फैसला देती है तो संविधान की नाक की सीध में चलती है। जैसे ही मुसलमानों का मामला आता है, जज साहबान कुर्सी पर कसमसाने लगते हैं कि इस फैसले का असर क्या होगा?

भाजपा को हिंदुत्ववादी कहा जाता है। उसका मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय संस्कृति की बात करता है। संघ हिंदू संस्कृति बोलने से बचता है। दरअसल हिंदू या सनातन संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है, यह कहना पोलिटिकली करेक्ट नहीं माना जाता। भाजपा को भी वोट हिंदू के नाम पर नहीं मिलता। उसे भी चुनावी बिसात पर जातियों का गणित बिठाना पड़ता है। धर्म आत्मा है और राजनीति शरीर, यह बात जब तक सनातन धर्म को मानने वालों की समझ में नहीं आएगी तब तक वे पिटते और पिछड़ते रहेंगे।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
response@jagran.com

बंगाल पुलिस के पतन की पराकाष्ठा



यशपाल सिंह

बंगाल में पुलिस का जो पतन वामपंथियों के समय शुरू हुआ था, वह ममता बनर्जी के राज में भी जारी रहा

पुलिस प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ है, किंतु अगर वही रीढ़ रोगग्रस्त हो जाए तो फिर प्रशासनिक व्यवस्था का क्या होगा? बस वही जो आज बंगाल में हो रहा है। देश में कानून का राज है। कानून बिना भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए समान है, पर बंगाल में जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया या समर्थन किया, उनके साथ सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता बेखौफ होकर कुछ इस तरह व्यवहार कर रहे हैं जैसे वे देशद्रोही हों। शर्मनाक यह है कि पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है। कई मामलों में तो वह अराजकता फैलाने वाले गुंडों का ही साथ दे रही है। इसीलिए मानवाधिकार आयोग को यह कहना पड़ा कि बंगाल में कानून का नहीं, शासकों का कानून चल रहा है। बंगाल के हालात हमारे संघीय ढांचे पर कुठाराघात हैं। इसके परिणाम अत्यंत घातक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह सब रातोंरात हो गया। बंगाल पुलिस के पतन के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं।

बंगाल में पुलिस का पतन 30-35 साल पहले तब प्रारंभ हुआ था जब राज्य में वामपंथियों की पकड़ मजबूत हुई और वे सत्ता में आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं का एक मजबूत कैडर खड़ा किया और जिले के पार्टी सचिव के पद को अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया। प्रारंभ में पार्टी सचिव पुलिस अधीक्षक से समय लेकर मिलते और समस्याएं रखते, परंतु बाद में उन्हें ही अपने पास बुलाने लगे। बात और आगे बढ़ी तो जब नया पुलिस अधीक्षक किसी जिले में जाता तो उसे पहले से ही चार-पांच लोगों के नाम बता दिए जाते कि उनसे वह स्वयं जाकर मिले। इससे पार्टी पदाधिकारी बहुत मजबूत हुए। वे पुलिस से जो चाहते, करा लेते। पुलिस का भय धीरे-धीरे कम होता गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अकेले दम पर संघर्ष छेड़कर वामपंथियों को परास्त तो कर दिया, लेकिन वही वामपंथी नेता-कार्यकर्ता धीरे-धीरे उनकी पार्टी से जुड़ गए, क्योंकि उन्होंने सत्ता का स्वाद चख लिया था। इस प्रक्रिया ने पुलिस का इकबाल ध्वस्त कर दिया। अब तो तृणमूल कांग्रेस की ओर से यहां तक कहा जाता है कि पुलिसिंग हम करेंगे।

जब पुलिसिंग सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता करेंगे तो फिर प्रशासन कहां जाएगा? हाल के चुनावों के बाद भाजपा समर्थकों का जो भीषण उत्पीड़न हुआ, वह इसी का परिणाम है। गृहमंत्री, राज्यपाल की चेतावनियों के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ, क्योंकि बंगाल में पुलिस का मतलब कुछ नहीं रह गया है। ऐसे माहौल में पुलिस में भ्रष्टाचार खूब पनपा। उच्च अधिकारी भी इससे अछूते नहीं रहे। स्वाभाविक है कि पूरे प्रदेश के प्रशासन पर इसका बुरा असर पड़ा। पुलिस का पतन तो सड़क पर दिखाई पड़ने लगता है, औरों का दिखाई नहीं पड़ता, परंतु वह दीमक की तरह व्यवस्था को खोखला कर देता है। आम तौर पर क्षेत्रीय पार्टियों का एकमात्र उद्देश्य केवल सरकार बना लेना ही होता है। उनकी सरकारों में हर प्रकार के माफिया खूब फलते-फूलते हैं। इसके बाद भी जनप्रतिनिधि प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे किसी भी अधिकारी को पार्टी विरोधी बताकर हटवा देते हैं। अपने क्षेत्र के थानों को वे निजी थाना समझते हैं।



सवालों के घेरे में बंगाल पुलिस। फाइल

बंगाल गई मानवाधिकार आयोग की टीम ने अपनी जांच में तमाम शिकायतों को सही पाया और यह सिफारिश की कि हत्या, दुष्कर्म आदि मामलों की जांच सीबीआइ द्वारा कराई जाए ताकि दोषियों को सजा दी जा सके, परंतु मुख्यमंत्री ने आयोग की रिपोर्ट को ही दरकिनार कर दिया। आखिर नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों और कानून के राज का मतलब क्या है? पुलिस और प्रशासन का कार्य क्या है?

देश के प्रथम गृहमंत्री सरदार पटेल ने अखिल भारतीय सेवाओं को देश के संघीय ढांचे के लिए 'स्टील फ्रेम' कहा था। एक अर्से से कहा जा रहा है कि अब इस स्टील फ्रेम में जंग लग गई है। अधिकारी प्रशिक्षण समाप्ति के समय संविधान की शपथ लेते हैं और लोकसेवक के रूप में सेवा प्रारंभ करते हैं, परंतु पार्टियां उन्हें पार्टी कार्यकर्ता के रूप में प्रयोग करना चाहती हैं। जो इसका विरोध करते हैं, उनका वे उत्पीड़न करती हैं, क्योंकि उन्हें न्यायपालिका की तरह कोई विधिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। उत्तर प्रदेश में 2006-07 में एक पुलिस अधिकारी को नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा था, क्योंकि उसने मुख्तार अंसारी गैंग द्वारा अवैध रूप से खरीदी लाईट मशीन गन को बरामद कर लिया था। इस बरामदगी के बाद उसने मुख्तार समेत कई पर एफआइआर करा दी। बाद में उस पर उच्चतम स्तर से दबाव डाला जाने लगा कि एफआइआर वापस लो। यह असंभव था। फिर उसका उत्पीड़न प्रारंभ हुआ और उसने इस्तीफा दे दिया। उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने के साथ लोग इस मामले को भूल गए, परंतु बंगाल में वही सरकार काफी दिनों तक रहीं, अतः ऐसी अनेक घटनाएं छोटे-बड़े पैमाने पर होती रहीं और आज वे प्रशासनिक कैंसर बन गई हैं।

अखिल भारतीय सेवाओं का स्टील फ्रेम स्वरूप बनाए रखना केंद्र का दायित्व है। उसे हर हाल में इस दायित्व का पालन करना होगा, चाहे नियमावली बदलनी पड़े। आइपीएस अधिकारी प्रकाश सिंह द्वारा इस संबंध में दायर की गई जनहित याचिका का उद्देश्य यही था कि पुलिस का पतन रुके। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए सितंबर 2006 में दिशानिर्देश भी जारी किए, लेकिन प्रदेश सरकारों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वे पुलिस को हमेशा अपनी पार्टी का लठैत बनाकर रखना चाहती हैं। कानून का राज समाज में विश्वास और सुरक्षा का वातावरण बनाता है, जिससे उसके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। यह सही समय है कि केंद्र सरकार बंगाल के पुलिस-प्रशासन के पतन के मूल कारणों का पता लगाने के लिए एक आयोग गठित करे, जो गहन समीक्षा कर अपनी आख्या दे, ताकि इस राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने संबंधी कदम समय रहते उठाए जा सकें। संवैधानिक प्रजातंत्र को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ऐसे कदम आवश्यक हैं। अन्यथा इन सेवाओं की गुणवत्ता के साथ ही गवर्नेंस का गणित भी बिगड़ता जाएगा।

(लेखक उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

संगति का प्रभाव

साधु-संतों की संगति आम जन के लिए लाभदायी, पुण्यदायी और मोक्षदायी मानी गई है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तरह सृजन, पोषण एवं कल्याण के अधिष्ठाता साधु-संत ही होते हैं। समाज और राष्ट्र में संस्कार का सृजन, शुभ विचारों से व्यक्तित्व का उत्थान करना, वैचारिक पोषण और दिव्य कर्मों से जन-जन के कल्याण का काम साधुओं द्वारा होता है। जब मानव का जीवन कामना और वासना के वशीभूत होकर पतित हो जाता है तब साधु-संतों के उपदेश मानव के अंतर्मन में ज्ञान की ज्योति जलाकर और अंतःकरण के अंधियारे को मिटाकर उसे भटकने से बचाते हैं। वास्तव में साधु-संतों के पास उत्कृष्ट विचारों का दिव्य स्त्रोत होता है। उनके माध्यम से वे परोपकार, सेवा, सत्कर्म, यज्ञ, पूजा, प्रवचन और सत्संग कर मानव को सही दिशा दिखाकर उसका कल्याण करते हैं। उनकी संगति जन-जन के कल्याण के लिए दिव्य कर्मों की प्रेरणा देकर पोषण व उत्प्रेरणा प्रदान करती रहती है। साधु-संतों के प्रभाव से मानव में दिव्य कर्म करने की आदत बन जाती है जो और निखरती रहती है।

साधु-संत पारस पत्थर की तरह अपनी संगति का लाभ देते हैं। जैसे कुरूप और मूल्यहीन लोहा पारस पत्थर की संगति से मूल्यवान स्वर्ण बन जाता है। उसी प्रकार तुच्छ व्यक्ति साधु की संगति से स्वर्ण की तरह मूल्यवान ही नहीं, अपितु महान बन जाता है। जिस तरह चंदन वन के आसपास का परिवेश भी उसकी सुगंध से महक उठता है, उसी तरह सामान्य जन भी साधु संगति की सुगंधि का लाभ पाकर जीवन को सुगंधित कर लेते हैं। देवर्षि नारद की संगति से रत्नाकार डाकू और भगवान बुद्ध की संगति से अंगुलिमाल जैसे डाकू संत बन गए। कहा भी गया है, 'संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। बास-फास मिसरी सब एके भाव बिकात।' अच्छी और बुरी संगति का प्रभाव उनके अनुसार पड़ता ही है। इसलिए जीवन को सुखी बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अच्छी संगति को ही माध्यम बताया है। वही जीवन को सुवासित करती है।

मुकेश ऋषि

सावधानी से चुनने होंगे अपने आदर्श

डा. लक्ष्मीकांत त्रिपाठी

कोई समाज वैसा ही बनता है जैसे वह अपने लिए आदर्श चुनता है। इसलिए इसमें खासी सतर्कता बरतनी चाहिए

महान लोग जिस मार्ग पर चलें वही सबसे उत्तम माना जाता है। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए यही राय सुझाई है। इस बीच यक्ष प्रश्न यही है कि बड़ा या महान कौन है? यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि आज के निरंतर पतित होते समाज में बड़े या महान की परिभाषा भी विरूपित हुई है, जिन्हें आम लोग अपने आदर्श मानते हैं। अब संस्कार और मूल्य गौण हो गए हैं। चमक-दमक एवं साधन-संसाधन जैसे पहलू ही मुखर होकर लोगों को आकर्षित करते हैं, जिनका संबंध अक्सर ग्लैमर जगत से होता है। इस बीच कई हालिया घटनाओं को देखते हुए अब इन आदर्शों को लेकर नए सिरे से विचार करने का समय आ गया है।

ऐसी ही एक घटना के साथ राज कुंद्रा का नाम जुड़ा है। कुंद्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उन्होंने एक जानी-मानी सिने तारिका शिल्पा शेट्टी से शादी की है। इसी पहलू ने उन्हें उन लोगों की पांत में ला खड़ा किया, जिन्हें हमारा समाज प्रसिद्धि के आधार पर बड़ी शख्सीयत मानने लगता है। बीते दिनों उजागर हुए इस तथ्य ने इस चमक-दमक भरे संसार की कड़वी हकीकत को अनावृत्त कर दिया, जब पता चला कि कुंद्रा की संलिप्तता अश्लील फिल्मों में है। यह कितने शर्म की बात है कि जिनके तौर-तरीके और रहन-सहन की नकल हमारे समाज के तमाम लोग करने को उतावले रहते हैं, उनके पैर पतन की कितनी गहरी दलदल में धंसे हैं और उनकी इस चकाचौंध के स्रोत कितने स्याह हैं। कुंद्रा के माथे पर मैच फिक्सिंग का कलंक पहले से ही लगा हुआ था। इसके बावजूद यह शख्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अनिल कपूर भी इन दिनों मांसाहार से जुड़े एक ब्रांड के आक्रामक प्रचार में लगे हुए हैं। मांसाहार का जिस रूप में वह महिमामंडन कर रहे हैं, उसका इंटरनेट मीडिया पर भारी विरोध हुआ है। इसके बावजूद कपूर की ओर से कोई संवाद न होना उनकी असंवेदनशीलता को ही दर्शाता है। जबकि इन हस्तियों की जिम्मेदारी बनती है कि यदि लोग उनकी अभिनय क्षमता या हुनर के कारण उन्हें असाधारण प्रेम एवं सम्मान देते हैं तो वे भी लोगों की भावनाओं का ध्यान रखें।

हमारे समाज के समक्ष अब यह सोचने का समय आ गया है कि वह अपने आदर्शों का उचित रूप से चयन करे। याद रहे कोई समाज वैसा ही बनता है जैसे वह आदर्श चुनता है। आजकल ऐसे लोगों को आदर्श की तरह पेश किया जा रहा है जो अवसरवादी, स्वार्थी और बेशर्म हैं। वे जो गलत कारणों से ही चर्चा में रहते हैं। इससे हम नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं। कायदे से हमें उनका साक्षात्कार अपनी संस्कृति के असल नायकों से कराना चाहिए। उन्हें याद दिलाना होगा कि यदि भौतिक सुखों के लिए प्रभु श्रीराम, राजा हरिश्चंद्र, महाराणा प्रताप, शिवाजी और शहीद भगत सिंह ने हालात से समझौता किया होता तो आज हम कहां होते?

(लेखक आयुर्वेदाचार्य हैं)

मतांतरण पर रोक जरूरी

आए दिन देश के तमाम हिस्सों से मतांतरण के समाचार आते रहते हैं। बीते दिनों इस संदर्भ में कई आलेख भी पढ़ने को मिले। ऐसे ही एक आलेख में लेखक दिव्य कुमार सोती ने सदियों पुराने उस सत्य को ही उजागर किया कि जिस-जिस क्षेत्र में मतांतरण हुआ, वहीं भारत विरोधी अलगाववाद पनपा और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ गई। हजार साल पहले अफगानिस्तान भारत का भाग था। कैकेयी और गांधारी यहीं की थीं। प्राचीन पुरुषपुर (अब पेशावर) तथा भरत के पुत्र तक्ष द्वारा बसाया गया तक्षशिला इससे लगे क्षेत्र में ही हैं। सीमांत गांधी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वस्तुतः वे आर्य थे और उनका जबरिया मतांतरण कराकर उनमें मूल भारत भूमि के खिलाफ जहर भरा गया। खान साहब में अपनी आर्य विरासत का गौरव विद्यमान था। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण का विरोध किया था। जिन्ना ने जब कहा कि पाकिस्तान तो वास्तव में उसी दिन बन गया था, जब सिंध में पहला हिंदू इस्लाम में मतांतरित हुआ। उनका यह कथन सच्चाई से बहुत दूर नहीं था। मतांतरण का अर्थ राष्ट्रांतरण ही है। यह स्वामी विवेकानंद ही नहीं, बल्कि बाबा साहब भीमराव आंबेडकर और वीर सावरकर ने भी कहा है। यह इस्लाम ही नहीं ईसाइयत के संदर्भ में भी सही है। गांधीवादी विचारक जेसी कुमारप्पा ने लिखा है कि पश्चिमी ईसाई विस्तारवाद की सेना के चार अंग हैं-थल सेना, वायुसेना, नौसेना और ईसाई मिशनरी। पश्चिमी सरकारों के लिए भारत में मतांतरण करा रहे मिशनरी बड़े बेशकीमती लोग हैं। भारत को यदि उनके संगठित अभियान और मजहबी विस्तारवाद से बचाना है तो मतांतरण प्रतिबंधित करने वाला एक सख्त केंद्रीय कानून इस समय बेहद आवश्यक हो गया है। साथ ही उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी किसी सक्षम एजेंसी को दी जानी चाहिए।

अजय मित्तल, मेरठ

मेलबाक्स

राजनीति का विदेशी भ्रमजाल

इजरायल की 2009 में बनी साइबर सिक्योरिटी कंपनी, जिसका नाम क्यू साइबर टेक्नोलाजीज है, एनएसओ ग्रुप द्वारा पेगासस स्पाइवेयर तैयार किया गया। इस स्पाइवेयर का इस्तेमाल अधिकृत व स्वीकृत देशों की 51 फीसद जांच एजेंसियां, 38 फीसद विधि प्रवर्तन एजेंसियां और 11 फीसद सेना सुरक्षा की दृष्टि से आतंकवाद व अपराधियों के लिए करते हैं। एनएसओ के अनुसार पेगासस स्पाइवेयर के लाइसेंस देने की प्रक्रिया केवल अधिकृत सरकारों द्वारा ही की जाती है। पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल अधिकतर मेक्सिको, पनामा, बांग्लादेश और सऊदी अरब जैसे देशों में किया जाता है। रही बात भारत में इसके इस्तेमाल की तो भारत सरकार ने इसे सिरे से नकार दिया है। पेगासस स्पाइवेयर के माध्यम से भारतीय पत्रकारों व नामचीन हस्तियों की फोन जासूसी के सुबूत भी नहीं मिले हैं। यह केवल एक सियासी दांव-पेच भर लगता है। निःसंदेह इस कोरोना काल में भी देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता, विकास कार्यों और कुशल नेतृत्व की वजह से वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते कद की वजह से परेशान कुछ अंतरराष्ट्रीय तत्वों की यह शरारत लगती है। संसद के मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले पेगासस स्पाइवेयर से फोन जासूसी का बम विस्फोट, संसदीय कार्यवाही के ठप होने की वजह से विकास कार्यों के विधेयकों का पारित न होना, भारतीय राजनीति में अफरा-तफरी, भारतीय विपक्ष को हैक कर देश में अराजकता व भ्रमजाल की स्थिति बना केंद्र सरकार की छवि को बिगाड़ना इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। यह प्रकरण पुरानी बोतल में नई शराब जैसा ही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा मानवाधिकार के नाम पर विदेश से वैध अवैध फंड प्राप्त करना, भारत सरकार की जासूसी करना, प्रवर्तन निदेशालय की जांच में संदिग्ध पाया जाना और बढ़ते जांच के दायरे के कारण भारत से रातों-रात बोरिया-बिस्तर समेटकर भाग जाना और वर्तमान में पेगासस प्रकरण का झूठ फैलाना केवल भड़ास निकालने का एक जरिया है। रूस, चीन, अमेरिका, वियतनाम आदि देशों ने भी समय रहते एमनेस्टी इंटरनेशनल पर गंभीर कार्रवाई की थी।

दीपक गौतम, सोनीपत।

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

87 प्रतिशत मुनाफे की सीमा निर्धारित की है हाल में सरकार ने कैंसर के उपचार में उपयोगी तमाम दवाओं को अधिसूचित करते हुए। अभी तक कैंसर से जुड़ी इन दवाओं पर एक हजार प्रतिशत से भी अधिक मुनाफा कमाया जा रहा है।

आजकल

अनैतिक मुनाफा और व्यवस्था की बेबसी



डा. अजय खेमरिया
लोकनीति विश्लेषक

कोविड वैश्विक संकट ने स्वास्थ्य क्षेत्र की ऐसी अनेक विसंगतियों को भी उजागर किया है जो आम आदमी के नजरिये से व्यवस्था में एक संगठित शोषण तंत्र की सशक्त मौजूदगी को प्रमाणित करती दिखती हैं। एक तरफ जहां हर लोकप्रिय सरकार सस्ती स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा करती है तो दूसरी तरफ आम आदमी दवाओं और मेडिकल उपकरणों के नाम पर लागत से कई गुना अधिक दाम चुकाने को विवश है। व्यवस्था की त्रासदी का आलम यह है कि देश में दवाओं एवं मेडिकल उपकरणों से संबद्ध लागत, मुनाफा और साक्ष्य केंद्रित मूल्य नियंत्रण का कोई जनोन्मुखी तंत्र ही नजर नहीं आता है



दवाओं और मेडिकल उपकरणों की कीमतों पर सरकारी नियंत्रण और उसकी पर्याप्त निगरानी की हो व्यवस्था। फाइल

राष्ट्रीय औषधि मूल्य नियामक प्राधिकरण ने बीते दिनों पांच मेडिकल उपकरणों के दाम निर्धारित कर दिए हैं। पल्स आक्सीमीटर, बीपी मानिटरिंग मशीन, नेबुलाइजर, डिजिटल थर्मामीटर और ग्ल्यूकोमीटर ऐसे उपकरण हैं जिनकी आवश्यकता कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान प्रायः हर घर में महसूस की गई। अब सरकार ने इनके अधिकतम मूल्य को 70 फीसद मुनाफे की सीमा में बांध दिया है। 20 जुलाई से 31 जनवरी 2022 तक इनके खुदरा मूल्य एनपीपीए यानी राष्ट्रीय औषधि मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण की निगरानी में रहेंगे। एनपीपीए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ निकाय है जो देश में दवाओं के मूल्य विनियमन का कार्य रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मातहत करता है। महत्वपूर्ण बात इन उपकरणों के मूल्य नियंत्रण से कहीं अधिक बड़ी है। यह जानकर आपको आश्चर्य हो सकता है कि अभी तक ये पांचों उपकरण देश में लागत से करीब 700 प्रतिशत अधिक कीमत पर नागरिकों को बेचे जा रहे थे। यानी सबसे बुरे दौर में जब मानवता कराह रही थी, तब देश का फार्मा उद्योग आपदा को अवसर मानकर आम आदमी की सांसों की कीमत पर मुनाफा कमा रहा था।

हैरानी यह कि करीब साढ़े चार लाख जिंदगियों के खत्म हो जाने के बाद सरकार के इस स्वतंत्र निकाय को मूल्य नियंत्रण की याद आई है। इस बीच महज 300 से 500 रुपये लागत वाले पल्स आक्सीमीटर के लिए करोड़ों लोगों ने दो हजार से लेकर पांच हजार रुपये तक चुकाए। थर्मामीटर और अन्य तीन उपकरण भी लागत से हजार प्रतिशत अधिक दामों पर बिके हैं, यह सर्वविदित है।

लागत के मुकाबले सात गुना तक अधिक कीमत वसूले गए : असल में करीब 700 प्रतिशत अधिक दाम में बिक्री को तो एनपीपीए ने लागत और एमआरपी के आधार पर आंकलित किया है। सच्चाई तो यह है कि इनकी बिक्री 10 गुना से भी अधिक कीमतों पर हुई है। आक्सीजन कंसंट्रेटर जो न तो एनपीपीए के मूल्य नियंत्रण सूची में था और न ही अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में, लागत मूल्य से कई हजार गुने दामों पर पिछले कुछ दिनों तक बिका है। यानी देश में दवाओं के साथ मेडिकल उपकरणों के नाम पर भी एक संगठित लूट का शिकार आम आदमी लंबे अरसे से हो रहा है। दुर्भाग्यवश कानूनों, अधिनियमों का अंतहीन अंबार अंततः फार्मा इंडस्ट्री की तरफ ही झुका है।

कोरोना की आपदा केवल कालाबाजारी करने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि सभ्य और अभिजन कहे जाने वाले स्वास्थ्य क्षेत्र के बड़े वर्ग के लिए भी अवसर से कम साबित नहीं हुई है। यह तब जब भारत वैश्विक मोर्चे पर फार्मा इंडस्ट्री में तीसरी बड़ी ताकत है। अकेले मेडिकल उपकरणों का कारोबार हमारे यहां सालाना करीब 75 हजार करोड़ रुपये का है। सवाल यह है कि क्या देश में एक संगठित लाबी दवा एवं उपकरणों के नाम पर बेखौफ होकर आमजन को लूटती आ रही है? अनुभव और आंकड़े इसी की तस्दीक करते हैं।

कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिकित्सकों की पेशेगत नैतिकता पर सवाल उठाया था। अमेरिका में दिए गए उनके बयान पर हमारे देश में बड़ा बवाल मचा था। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह उपकरणों एवं दवाओं के नाम पर आम भारतीयों की जेबें खाली की गई हैं, उसने एक बार फिर समग्र चिकित्सकीय व्यवसाय की नैतिकता और सरकारी नियंत्रण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा नागरिक मूल अधिकार भले ही न हो, लेकिन लोककल्याणकारी राज्य की प्रतिस्पर्धी राजनीति में हर दल स्वास्थ्य सेवाओं को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में दिखाने की कोशिश करता है। जमीनी सच्चाई यह है कि लोकप्रिय राजनीति और शासन आज भी जनस्वास्थ्य के मोर्चे पर एक ताकतवर लाबी के आगे कठपुतली की तरह ही है।

कोविड संकट ने स्वास्थ्य क्षेत्र की बुनियादी खामियों के समानांतर नैतिक पक्ष को भी बेनकाब किया है। संबंधित विनियमन के लाख दावों के बीच किस तरह की लूट निजी अस्पतालों में हर स्तर पर की गई है, उसका कोई प्रमाणिक उपाय आज भी हमारी सरकारों के पास नहीं है। मेडिकल उपकरणों के मामले में तो स्थिति दवाओं से भी बुरी है, क्योंकि यह सेक्टर करीब 70 फीसद आयात पर निर्भर है और 99 फीसद वस्तुएं कीमत के मामले में सरकारी नियंत्रण से बाहर है। औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन कानून 1940 के तहत विनियमन के प्रविधानों के तहत केवल 20 उपकरण ही अधिसूचित हैं, यानी हजारों करोड़ का यह कारोबार पूरी तरह उत्पादकों, डीलरों और डाक्टरों के हवाले चल रहा है।

अब मूल सवाल नैतिकता का है जिसने इस कारोबार को नियंत्रित किया हुआ है। वर्ष 2017 में सरकार ने हृदय में लगने वाले स्टेंट के दाम अधिसूचित किए थे। तब इसे बड़ा कल्याणकारी कदम बताया गया था, क्योंकि देश में दो तरह के स्टेंट उपयोग में लाए जाते थे। बीएमएस यानी बेयर मेटल स्टेंट जिसकी कीमत थी 45 हजार रुपये और दूसरा ड्रग एल्युटिंग स्टेंट (डीईएस) जो 1.2 लाख रुपये में मिलता था। एक जनहित याचिका के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एनपीपीए ने बीएमएस स्टेंट के लिए 7,260 रुपये एवं डीईएस स्टेंट के लिए 29,600 रुपये दाम निर्धारित किए। इस दौरान वर्षों तक आम आदमी से हृदय रोग और इस उपचार प्रविधि के नाम पर लागत की तुलना में एक हजार प्रतिशत तक अधिक दाम वसूले जाते रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों सरकार ने स्टेंट की कीमतों में बढ़ोतरी को स्वीकृति दी, लेकिन यह मामूली है। जाहिर है स्टेंट जैसे उपकरण के नाम पर कितने व्यापक स्तर पर जनता का शोषण हुआ है, इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। इन दोनों स्टेंट के प्रयोग में नैतिकता का वही सवाल स्वयंसिद्ध होता है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया था।

दरअसल डीईएस स्टेंट का चलन ठीक सिजेरियन प्रसव को प्रोत्साहित किए जाने की तरह ही क्लिनिकल सलाह के माध्यम से बढ़ाया गया। लिहाजा वर्ष 2002 से 2018 के मध्य निजी अस्पतालों में हृदय की शल्य क्रिया में डीईएस स्टेंट डालने का प्रतिशत 22 से बढ़कर 65 हो गया है। बीएमएस एवं डीईएस स्टेंट लगवाने वाले करीब दस हजार लोगों पर उनके अगले छह साल के जीवन पर किए गए शोध में पाया गया है कि संक्रमण या मौत के मामले में दोनों स्टेंट से खास अंतर नहीं रहा। उपरोक्त संदर्भ में एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे आफिस की रिपोर्ट को यहां ध्यान से समझने के आवश्यकता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में हर पांचवां मरीज दिल की बीमारी के इलाज के लिए कर्ज लेता है और यह कर्ज ऐसा है जिसे वह अपनी आमदनी से चुका नहीं पाता है। नतीजतन घर या फिर कोई अन्य संपत्ति बेचना हर पांचवें आदमी की मजबूरी बन जाती है। इन परिस्थितियों के बीच केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में जब स्टेंट की कीमतें अधिसूचित कर दी तो अस्पतालों ने प्रक्रियागत चार्ज दोगुने से भी ज्यादा कर दिया। ऐसा होने से इसके उपचार का बिल अस्पतालों ने मरीज को तीन से चार लाख रुपये तक पहुंचाना शुरू कर दिया। सरकार दावा करती है आयुष्मान योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त है, लेकिन दिल की बीमारी के करीब 67 फीसद आपरेशन निजी अस्पतालों में हो रहे हैं।

इस साल के बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण में भी निजी अस्पतालों की कई महंगी सेवाओं का उल्लेख किया गया है। एनपीपीए ने खुद दिल्ली एनसीआर के चार बड़े निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों को दिए गए बिलों का अध्ययन करते हुए यह स्वीकार किया है कि मरीजों से सलाह, दवा और उपकरणों के मामले में 17 गुना तक अधिक राशि वसूली गई है। असल में हजारों की संख्या में प्रचलित दवा एवं उपकरणों की एमआरपी तय करने का कोई साक्ष्य आधारित समग्र तंत्र नहीं होने का फायदा कारोबारी उठा रहे हैं। हाल ही में सरकार ने कैंसर के उपचार में उपयोगी तमाम दवाओं को अधिसूचित करते हुए 87 प्रतिशत मुनाफे की सीमा तय की है। अभी तक कैंसर से जुड़ी इन दवाओं पर हजार गुना से ज्यादा मुनाफा कमाया जा रहा है। सच्चाई यह है कि एलोपैथी में हजारों दवाएं एवं उपकरण ट्रायल के रूप में भी चलते रहते हैं। सरकार के पास सुव्यवस्थित डाटा बैंक न होने से मामूली दवाएं और उपकरण अधिसूचित न होने से लागत की तुलना में कई गुना महंगे दामों पर जनता को बेचे जाते हैं।

उचित दरों पर दवाओं की उपलब्धता

देश में दवाओं और मेडिकल उपकरणों को लागत से सात गुना से भी अधिक कीमतों पर बेची जाने वाली गंभीर समस्या का दूसरा पहलू यह भी है कि कानूनन दाम नियंत्रित करने से दवा या उपकरणों की सस्ती उपलब्धता सुनिश्चित हो, ऐसा भी नहीं हो पा रहा है। मसलन वर्ष 1995 में सरकार ने करीब 195 दवाओं के मूल्य निर्धारित किए जो एपीआइ (एक्टिव फार्मास्युटिकल इनग्रेडिएंट) दवा निर्माण के लिए कच्चा माल श्रेणी के थे। इसके बाद निर्माताओं ने इनके निर्माण से हाथ खींच लिए। नतीजतन आज करीब 70 फीसद एपीआइ के लिए हम चीन एवं अन्य देशों पर निर्भर हैं। कमोबेश मेडिकल उपकरणों के मामले में भी आज यही हालत है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है कि भारत में जो निकाय इस काम के लिए बने हैं वे फार्मा लाबी के हितों का एक लंबे अरसे से परोक्ष संरक्षण करते रहे हैं। परिणामस्वरूप जो दवा या उपकरण दस रुपये में मिलनी चाहिए उसके लिए हमारे नागरिक हजारों रुपये चुकाने पर विवश हैं।

तथ्य यह है कि नीतिगत स्तर पर दंड और जुर्माने से समावेशी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अनुकूल माहौल नहीं बनाया जा सकता है। इसके लिए दंड के साथ विनिर्माण की दिशा में भी ठोस कदम आवश्यक है। आखिर कोई भी कारोबारी सस्ते आयात के विकल्प को छोड़कर भारत में स्टील फ्रेम ब्यूरोक्रेसी की प्रेतछाया में फैक्ट्री लगाने का संकट क्यों मोल लेगा? इसलिए आवश्यक है कि सरकार मेडिकल उपकरणों के 70 हजार करोड़ रुपये के इस सालाना कारोबार के लिए जमीन पर 'मेक इन इंडिया' को साकार करे। मोदी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं केरल में मेडिकल डिवाइस पार्क निर्माण को अनुमति प्रदान की है। सवाल फिर उस नीयत और इच्छाशक्ति का है जो भारत में जड़ प्रशासन की दुरभिसंधि को बयां करता है। क्या मजबूत फार्मा लाबी इन पार्कों को जनोत्पादकीय बनने देगी?

खरी-खरी

सीढ़ी दर सीढ़ी

अरविंद तिवारी

कठिन डगर है पनघट की। वही पनघट, जहां स्थापित लेखकों का जमघट है। ऊंचे भवन की छत है वह। उस छत पर स्थापित लेखकों के लिए शानदार सोफे हैं, जिन पर बैठने के बाद, लिखे बिना ही लेखक बने रह सकते हैं। दर्जनों बने हुए हैं। वह भी घटिया लिखकर ऊंचा मुकाम चाहते थे। उस छत पर जाने के लिए मकानों वाली लिफ्ट काम नहीं आती। जो काम आती है, वह आसानी से नहीं मिलती। उनका शातिर दिमाग लिखने में जितना नहीं चलता, उतना काम आने वाली लिफ्ट को खोजने में चलता था। वहां सभी लोग अपनी सीढ़ी बनाकर पहुंचे हैं। सीढ़ी बनाना आसान नहीं है। फिसलती सीढ़ियों पर चढ़ना आसान नहीं होता, यह उन्हें अच्छी तरह ज्ञात था। चढ़े बिना, साहित्य में अज्ञात ही रहना पड़ेगा, यह भी वह जानते थे।

वह ऊंची सीढ़ी नहीं बना सकते थे, पर इतनी ऊंची तो बना ही सकते थे कि उनका असफल प्रयास सभी देख लें। अपने कस्बे में एक संस्था बनाकर वह, बाप की कमाई का सदुपयोग करने लगे। यह संस्था हर साल कार्यक्रम कर मठाधीशों को पुरस्कृत करने लगी। मिशन एक ही था, सोफे पर बैठे स्थापित लोग, उनकी छोटी सी सीढ़ी की ओर झांक कर देख लें। वह वार्षिक पत्रिका छापने लगे, जो वार्षिक पुरस्कार के साथ ही विमोचित होने लगी। उनका लक्ष्य कम समय में ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचना था। दिमाग ने कहा, 'प्रकाशकों को पुरस्कृत करो।' वह हर साल एक प्रकाशक को पुरस्कृत करने लगे। परिणामस्वरूप वह उन प्रकाशनों के प्रकाशन में छपने लगे।

जान-पहचान बढ़ी तो वह अपने आप को अखिल भारतीय साहित्यकार मान बैठे। साहित्य के विद्यार्थी थे, इसलिए साहित्यिक शब्दों का खूब इस्तेमाल करने लगे। लेकिन अपनी सीढ़ी से वह ज्यादा ऊंचे नहीं पहुंच पाए। इतना जरूर हुआ कि उनकी सीढ़ी से उनकी पहचान बन गई। एक मठाधीश ने उन्हें अपनी सीढ़ी पर चढ़ा लिया। वह उसके साथ साहित्यिक यात्राएं करने लगे। उन्हें लगा, यह सीढ़ी भी उन्हें गंतव्य तक नहीं पहुंचाएगी तो वह जंप करके दूसरी, तीसरी, चौथी पर चढ़ने लगे। उन्हें इसमें मजा आने लगा। वह अब ऐसी सीढ़ी तलाश रहे हैं, जो उन्हें फाइनली ऊपर ले जाकर सोफे पर बैठा दे।

ट्वीट-ट्वीट

हमें संसद सुचारु रूप से चलते देखनी है। हमें गली-मुहल्ले सी चीख-चिल्लाहट नहीं, बल्कि अच्छी बहस सुननी है। हमें विपक्ष के आरोप और उसका चिंतन सुनना है। सरकार की सफाई सुननी है। संसद चलाने में जनता का पैसा लगता है। सोमवार को संसद में मनसुख मंडाविया और मनोज कुमार झा ने जो किया, वह संसद सत्र के हर दिन होना चाहिए।

मीनाक्षी जोशी@IMinakshiJoshi



कोविड महामारी के चलते बंद पड़े स्कूलों और कालेजों के कारण भारत में पठन-पाठन की स्थिति चिंताजनक हो रही है। चूंकि कोविड संक्रमण के मामलों में निरंतर कमी आ रही है और टीकाकरण की रफ्तार भी बढ़ रही है तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार स्कूलों को फिर से खोलने के लिए स्पष्ट रणनीति बनाए। हमें इस बढ़ते नुकसान के प्रति कुछ जोखिम तो लेना ही होगा।

प्रो. शमिका रवि@ShamikaRavi

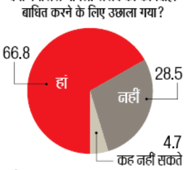
ड्यूटी के दौरान करीब डेढ़ महीने बाद मेरे सामने कोविड संक्रमण के दो नए मामले सामने आए। निश्चित तौर पर इसका यही मतलब होना चाहिए कि जल्द ही हमारा सामना कोरोना की तीसरी लहर से हो सकता है। इसे देखते हुए आप सुरक्षित रहिए और कोविड अनुशासन का कड़ाई से पालन करिए।

डा. मोनिका लांगे@drmonika_langeh

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या पेगासस मामला संसद की कार्यवाही बाधित करने के लिए उछाला गया?



सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या राज्य सरकारें यह नहीं बताना चाहतीं कि उनके यहां कितने लोग आक्सीजन की कमी से मरे?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

उन्हें सताने लग गया जासूसी का भूत,
जाने किस श्मशान से उन्हें मिला यह झूठ।
उन्हें मिला यह झूठ बुलाओ कोई ओझा,
कर दे आय इलाज कम-स-कम उतरे बोझा।
जो अपना ही 'भूत-काल' बिल्कुल ना जाने,
आ जाते हैं भूत नित नए उन्हें सताने!

- ओमप्रकाश तिवारी

मध्य प्रदेश डायरी

निष्प्रभावी होता एक उपयोगी कानून



सद्गुरु शरण
संपादक, नई दुनिया, मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़

बात ज्यादा पुरानी नहीं है, जब मध्य प्रदेश सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाकर इस गंभीर समस्या और इसके समाधान के प्रति देश का ध्यान आकृष्ट किया था। कहा जा सकता है कि इस पहल से कई अन्य राज्य प्रेरित हुए और उसी तर्ज पर कानून बनाया। उम्मीद जगी थी कि सरकार की सचेष्टता से बेटियों के खिलाफ इस घृणित साजिश पर अंकुश लग सकेगा, पर पिछले कुछ महीनों का अनुभव और लव जिहाद की लगभग हर दिन नई वारदात से स्पष्ट है कि प्रदेश का गृह विभाग इस कानून को अपेक्षानुसार धार देने में विफल साबित हुआ। जब कानून बना था तो लव जिहादियों के हमदर्द यह आशंका जता रहे थे कि इसका दुरुपयोग किया जाएगा, पर कानून लागू होने के बाद इस आशय की एक भी शिकायत नहीं सुनाई दी। कोई संवेदनशील सरकार किसी कानून के दुरुपयोग की अनुमति नहीं दे सकती। अच्छी बात है कि कानून के दुरुपयोग की कोई शिकायत नहीं आ रही, पर इसका सदुपयोग तो होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य का गृह विभाग अपनी पुलिस को कानून की मंशा का वास्तविक संदेश देने में विफल रहा है।

इंदौर में अफजल नामक एक शातिर लव जिहादी ने गोलू नाम रखकर एक किशोरी को प्रेमजाल में फंसाया। उसे धोखा देकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे रुपये-गहने समेट लाने के लिए उसके घर वापस भेजा तो परिवारजनों ने उसे पकड़ लिया और एफआइआर करवाने थाने गए। लव जिहाद के इतने स्पष्ट मामले में पुलिस ने यह तर्क देकर महज छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया कि किशोरी मत परिवर्तन का आरोप नहीं लगा



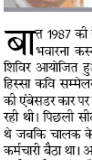
लव जिहाद पर कसे शिकंजा। प्रतीकात्मक

रही है। बाद में सामाजिक संगठनों के तमाम प्रयास के बाद पुलिस ने इसे लव जिहाद का मामला माना। ऐसा लगभग हर मामले में होता है। पुलिस लव जिहाद के स्पष्ट मामलों को भी संबंधित कानून की धाराओं में दर्ज करने में आनाकानी करती है। इसका परिणाम सामने है। प्रदेश में सख्त कानून के बावजूद लव जिहाद की घटनाएं जारी हैं। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी मध्य प्रदेश के लगभग साथ ही यह कानून अस्तित्व में आया, पर वहां इसे अधिक प्रभावशाली ढंग से लागू किया गया, लिहाजा लव जिहाद की घटनाओं में कमी दिख रही है। मध्य प्रदेश के नजरिये से पुलिस का यह रवैया इसलिए भी चिंताजनक माना जाना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में अधिकतर आदिवासी जिले छलपूर्वक मतांतरण करवाने वाले संगठनों और लव जिहादियों के निशाने पर हैं। शायद इसे ध्यान में रखकर ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सख्त कानून बनवाया, यद्यपि इसके अपेक्षित परिणाम आने बाकी हैं। हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फांसकर उनका छलपूर्वक मतांतरण करवाना और उनका जीवन बर्बाद कर देना इस साजिश का मकसद है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के हजारों मामले सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद इस पर कड़ाई से अंकुश लगाने में गृह विभाग की उदासीनता हैरतअंगेज है। यह परिस्थिति इसलिए भी विचित्र है, क्योंकि मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के तमाम फैसलों की वजह से कन्या-हितैषी राज्य माना जाता है। अपनी बहुचर्चित लाड़ली लक्ष्मी योजना और ऐसी कई अन्य योजनाओं की वजह से शिवराज सिंह को स्नेहपूर्ण मामा संबोधन हासिल है। इसके बावजूद प्रदेश की तमाम लड़कियां लव जिहाद के जाल में फंसकर प्रताड़ित हो रही हैं। प्रदेश के गृह विभाग को समझना चाहिए कि लव जिहाद एक घृणित अभियान है, इसलिए उसका मुकाबला भी अभियान चलाकर ही किया जा सकता है। इस कानून के क्रियान्वयन के लिए भी वैसी ही राजनीतिक इच्छाशक्ति अपेक्षित है, जैसी कुछ महीने पहले इस कानून के गठन के वक्त परिलक्षित हुई थी। यह आवश्यक है कि प्रदेश सरकार इस कानून के पिछले कुछ महीनों के अनुभव की समीक्षा करे और इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया के सूराख की पहचान करे। इसके लिए प्रदेश सरकार उचित समझे तो अन्य राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश के माडल का अध्ययन भी कर सकती है।

कानून से आगे समाज की भी अहम भूमिका है। दोनों पक्षों के मान्य संगठनों और व्यक्तियों को मिल-बैठकर विचार करना चाहिए कि यह राष्ट्र और समाज विरोधी समस्या किस तरह मिटाई जा सकती है। लव जिहाद मध्य प्रदेश समेत सभी राज्यों में सामाजिक सद्भाव के लिए बड़ा खतरा साबित हो रहा है। इससे पहले कि हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाएं, समाज और सरकार को मिल-जुलकर इसे नियंत्रित कर लेना चाहिए। सिर्फ मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो यह इसलिए भी जरूरी है, ताकि यह प्रदेश बेटियों के लिए सर्वाधिक सुरक्षित प्रदेश के रूप में यशस्वी बना रहे।

हिमाचल प्रदेश डायरी

आइएएस का क्या मतलब होता है



नवनीत शर्मा
राज्य संपादक, हिमाचल प्रदेश

बात 1987 की है। कांगड़ा जिला के भवारना कस्बे में एक चिकित्सा शिविर आयोजित हुआ। शिविर का एक हिस्सा कवि सम्मेलन भी था। सफेद रंग की एंबेसडर कार पर डीसी की झंडी लहरा रही थी। पिछली सीट पर जिलाधीश बैठे थे जबकि चालक के बराबर एक पुलिस कर्मचारी बैठा था। अचानक एक चौक पर गाड़ी रुकी। मुझे और पिता जी को उस गाड़ी में बिठा लिया गया। गाड़ी से अच्छी महक आ रही थी। 15 मिनट में शिविर तक पहुंच गए। कविता पाठ हुआ। शिविर की पहल करने वालों की प्रशंसा भी हुई। डीसी साहब ने साहित्य और काव्य पर अलग से आधा घंटा बात की। यह भी बताया कि व्यक्ति स्वस्थ होगा तो उसका साहित्य भी। फिर एक मेहरबान के घर भोज हुआ। लौटते हुए हमें घर तक छोड़ा गया। घर पहुंच कर पिता जी से पहला सवाल किया, 'यह तो आम आदमी की तरह सामान्य बात और व्यवहार कर रहे थे। क्या यह सच में डीसी थे?' पिता जी ने कहा, 'हां, यह असली डीसी थे, इसीलिए ऐसे बात कर रहे थे। इन्हें ब्यूरोक्रेट भी कहते हैं। कुछ जनता से घुल मिल जाते हैं और समाज को समझते हैं, कुछ अपने अहं की मीनारों पर टंगे रहते हैं।' वह डीसी थे पूर्ण चंद डोगरा।

इस घटना के 34 साल बाद बीते दिनों शिमला के एक होटल में धुत हो कर हंगामा मचाने वाले ब्यूरोक्रेट के बारे में सामने आया ही था और यह पता चल ही रहा था कि सचिवालय में उच्च आसन पर बैठे यह साहब कौन हैं... कि अचानक एक और आइएएस एक महिला की शिकायत के कारण घिर गए। पता चला ब्यूरोक्रेट हैं और महिलाओं से ही जुड़े किसी विभाग का जिम्मा संभाल रहे थे। आरोप जांचे जाएंगे, कौन सही है, कौन गलत, यह जांच करने वाले ही जानें। जिस अधिकारी का हुड़दंग कैमरे में कैद हो गया, उस पर कार्रवाई क्यों न हो। आखिर कितने स्कूल-कालेज होंगे जहां बतौर मुख्य अतिथि नैतिकता का पाठ पढ़ाते होंगे और पढ़ाएंगे। क्या युवाओं के रोल माडल उन्हें धोखा दे रहे हैं?



प्रशासन असल में नौकरशाही ही चलाती है। राजनीतिक नेतृत्व उसे बेहतर दृष्टि प्रदान करता है। फाइल

ब्यूरोक्रेट....। यह शब्द जेहन में वर्षों से बैठा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में अक्सर यह सुना कि अमुक जी की ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ बेहद अच्छी थी, फलां जी की पकड़ बहुत ढीली थी। यह वाक्य भी प्रायः सुनने को मिलता है, 'सरकारें तो काम करती हैं, पर ब्यूरोक्रेसी नहीं करने देती।' उदाहरण के लिए अब पंजाब में यह आकलन सामने आ रहा है कि चूंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ब्यूरोक्रेसी पर ध्यान नहीं देते थे और कई मंत्रियों के काम नहीं होते थे, इसलिए आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू नामक तेज कैंची लेकर बुजुर्ग नेता के पर कतरने की योजना बनाई।

यह सच है कि नौकरशाही ही प्रशासन चलाती है। राजनीतिक नेतृत्व अगर उसे दृष्टि दे दे तो सोने पर सुहागा हो जाता है। लेकिन किसी समय दिल्ली के मैटकाफ हाउस में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को मिलने वाला प्रशिक्षण क्या कालांतर में मसूरी में मिलने वाले प्रशिक्षण से अलग हो गया है? क्या सिविल सेवाएं वास्तव में उतनी सिविल रह गई हैं? या इन्हें भी यह छूट दी जाए कि 'विघटन तो हर क्षेत्र में हुआ है, नौकरशाही में भी हुआ हो तो क्या नई बात है?' लेकिन जहां हर सरकारी चिट्ठी की शुरुआत, 'एंड वेयरएज आइ... अमुक आइएएस...' से होती हो, वहां 'हर क्षेत्र में व्याप्त विघटन' से बचना भी तो इन्हीं का दायित्व है। यह कैसी विसंगति है कि आम आदमी शांति भंग करे तो उसकी रात थाने में कटे और एक नौकरशाह हुड़दंगी हो जाए तो कोई बात नहीं?

इसी हिमाचल ने कई हिम्मत वाले और अच्छे कारणों से चर्चा में रहने वाले अधिकारी देखे हैं। नूरपुर में एसडीएम रह चुके एनएन वोहरा अब तक अपने अधीनस्थों के साथ पत्राचार के जरिये जुड़े हैं। कश्मीर के मुख्य वार्ताकार, जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल रह चुके एनएन वोहरा। जनजातीय जिले लाहुल-स्पीति को अपने जवां खून से सींच चुके मनोहर सिंह गिल चीन को 1962 की जंग से पहले भारत का झंडा दिखाने के लिए बैठे थे, लेकिन बाद में राजीव, नरसिंह राव और मनमोहन सरकारों में जिस पद पर रहे, लाहुल-स्पीति को हमेशा सींचते रहे। उसके बाद भी कई नाम हैं जो गिनाए जा सकते हैं, यह बताने के लिए कि आदर्शों की कमी नहीं है।

मनोहर सिंह गिल कहते हैं, 'मैं जिस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को जानता हूं, वह हमारी पीढ़ी के साथ खत्म हो गई। मैं एमए अंग्रेजी का एक पेपर लुधियाना में देता था और आइएएस का पेपर अगले दिन पटियाला में। फिर लौट कर लुधियाना आता था। देश भर में 58 लोग चुने गए और मेरा क्रम 10वां था। उस समय 21 से 23 साल के बीच तीन मौके मिलते थे। जो आ गया, वह आ गया, जो रह गया वह रह गया। अब लगता है कि जब तक कोई अंदर न आ जाए, इंतजार करो।'

तथ्य यह है कि देश में सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 32 वर्ष है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 35 और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 37 वर्ष है। हालांकि नीति आयोग ने संघ लोक सेवा आयोग को सिफारिश भेजी है कि चरणबद्ध तरीके से भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के लिए आयु सीमा 27 वर्ष की जाए। क्या होता है, यह देखना होगा।

यही एक ऐसा क्षेत्र है जहां गाड़ी, बंगला और सुरक्षा सहायक निश्चित होता है। यही ऐसा क्षेत्र है जिससे लोगों के भले के लिए काफी कुछ किया जा सकता है। यही वह क्षेत्र है जहां कोई चाहे तो लाल फीते की अकड़ ढीली की जा सकती है।

केंद्र सरकार में शिक्षा सचिव रहे हिमाचल काडर के वरिष्ठ आइएएस अधिकारी एमके काव (अब दिवंगत) के कुछ साल पहले के शब्द गूंजते हैं, 'अब अधिकारी सामने आकर श्रेय लेना चाहते हैं... प्रचार चाहते हैं... हमारा समय नींव के पत्थरों का समय था। वह समय था जब स्वयं पीछे रह कर एक आइएएस अधिकारी राजनेता को नियमों के दायरे में रहते हुए सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे की तरकीब बताता था।'

सवाल यही है कि कतिपय लोग लाठी संभालें, सांपों को मारें या स्वयं संभलें।

74 फीसद इनपुट 18 से 34 वर्ष आयु वर्ग के लोग भेजते हैं रेडियो पर हर महीने प्रसारित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात के लिए। लोगों की ओर से स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्र पर अधिक सुझाव मिलते हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 22 जुलाई, 2021

उत्तराखंड

रियायत के साथ सजगता जरूरी

उत्तराखंड में भले ही सरकार ने कोविड कर्फ्यू की अवधि में एक सप्ताह का इजाफा और किया हो, लेकिन इस बार छूट का दायरा ज्यादा विस्तृत किया है। बाजार खोलने के समय में दो घंटे का इजाफा कर रात नौ बजे तक कर दिया है। इसके साथ ही 50 फीसद क्षमता के साथ माल, सिनेमाघर, वाटर पार्क और मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति भी दे दी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जीवन को पटरी पर लाने के उपाय तेज करना वक्त की जरूरत है। कोरोना काल में पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को संवारना किसी चुनौती से कम नहीं है। व्यापारी भी लंबे समय से बाजार खोलने की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। दूसरा प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण के मामले भी काफी कम हो गए हैं। ऐसे में सरकार ने इस दिशा में और आगे कदम बढ़ाए हैं। प्रदेश की आर्थिकी का काफी कुछ दारोमदार पर्यटन पर निर्भर है तो सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को भी रियायत दी है।

नई व्यवस्था के तहत ऐसे यात्रियों को कोरोना जांच की रिपोर्ट से छूट दी गई है, जिन्होंने यात्रा के 15 दिन पहले तक वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों। वैक्सीनेशन न कराने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके अलावा राज्य के भीतर आवाजाही को जांच की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। निसंदेह सरकार के इस कदम से परिवहन व्यवसायियों को भी राहत मिलेगी। जाहिर है इन रियायतों से व्यापार की स्थिति बेहतर होगी। बावजूद इसके कुछ सवाल अपनी जगह बरकरार हैं। चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ तीन सप्ताह बाद कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से चिंतित हैं। उनकी इस आशंका के पीछे ठोस आधार भी है। ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देश इन दिनों डेल्टा वैरिएंट से जूझ रहे हैं।

सरकार ने रियायत का दायरा विस्तृत कर कोविड कर्फ्यू की अवधि एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। यह आम जन का दायित्व है कि छूट का सदुपयोग जिम्मेदारी के साथ करे

हमारे देश में भी इस तरह के केस देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अभी इनकी संख्या अधिक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समय-समय आम जन से सतर्कता की अपील कर चेतावनी दे रहे हैं। जाहिर है जान के साथ जहान भी जरूरी है। यह तभी संभव है जब सतर्कता का साथ न छोड़ा जाए।

विडंबना है कि छूट का दायरा बढ़ने के साथ ही सड़क से लेकर बाजार तक जो नजारा देखने को मिल रहा है, उससे यह प्रतीत नहीं होता कि कोरोना को लेकर लोग सजग हैं। ज्यादातर लोग अब न तो मास्क लगा रहे हैं और न ही शारीरिक दूरी के मानकों का पालन किया जा रहा है। इस मामले में सरकार को तो अपना दायित्व निभाना ही है, लेकिन आम जन की जिम्मेदारी कहीं ज्यादा है। इसलिए सभी को इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए।

हरियाणा

सरकार की पीड़ा समझें

हरियाणा में कोरोना लगभग नियंत्रित हो गया है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। कम ही सही, कोरोना से संक्रमित नए रोगी प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। प्रदेश में अब भी लगभग 800 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। अच्छी बात यह है कि अब तक एक करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और प्रतिदिन लगभग एक लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है। इससे भय का माहौल समाप्त हुआ है। जनजीवन लगभग सामान्य हो चुका है। लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत से लोगों ने कोविड प्रोटोकाल की उपेक्षा करनी प्रारंभ कर दी है। यह स्थिति चिंताजनक है।

प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का यह कहना उचित ही है कि यदि लोग अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति अपना दायित्व नहीं समझेंगे तो सरकार को विवश होकर कठोर प्रतिबंध लगाने ही होंगे। सरकार मात्र बचाव की तैयारियां कर सकती है। अस्पतालों को चिकित्सा सुविधाओं से लैस कर सकती है। आक्सीजन की व्यवस्था कर सकती है, लेकिन बचाव के नियमों का पालन तो जनसामान्य को ही करना होगा। कोरोना की तीसरी लहर आएगी, इसको लेकर लगभग सभी संस्थाएं और उनके



बाजारों में शारीरिक दूरी के नियमों का पालन अभी जरूरी है। फाइल

कोरोना संक्रमण वर्तमान में भले ही काफी हद तक नियंत्रण में दिख रहा है, लेकिन इससे बचाव के नियमों का पालन सतत करते रहना जरूरी है

चिकित्सा विज्ञानी एकमत हैं। हां, इसपर मतभेद अवश्य है कि तीसरी लहर अधिक भयावह होगी अथवा पहली लहर से भी कम दुष्प्रभावों वाली होगी। तीसरी लहर को सबको गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार तो ले ही रही है। वह प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सालयों में आक्सीजन प्लांट लगा रही है, जिससे तीसरी लहर में वैसी दिक्कतें न आएं, जैसी दूसरी लहर के दौरान आई थीं। इसलिए जैसे सरकार तीसरी लहर की आशंका को गंभीरता से ले रही है, सबको वैसी ही गंभीरता से लेना चाहिए। यदि प्रतिबंधों में छूट दी गई है तो इसलिए कि आर्थिक गतिविधियां प्रभावित न हों। आखिर कितने दिनों तक उद्यमों को, बाजारों को और शिक्षण संस्थाओं को बंद रखा जा सकता है? एक सीमा तक ही, और ऐसा भी नहीं कि इन्हें खुले रखकर कोरोना से बचाव न किया जा सकता हो। इसलिए सभी को सरकार की दुश्वारियां भी समझनी चाहिए और उसका सहयोग करना चाहिए।

बिहार

किसानों के लिए सराहनीय प्रयास

कोरोना काल में किसानों को उनके घर तक बीज की होम डिलीवरी करने वाले बिहार राज्य बीज निगम की सराहना की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने भी निगम के प्रयास की तारीफ करते हुए देश के सभी राज्यों से इस नवाचार को अपनाने की सिफारिश की है।

देखा जाए तो किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उचित बाजार व्यवस्था, तकनीकी सहायता के साथ समय पर उन्नत बीज की उपलब्धता जरूरी है। इसे ध्यान में रखकर बीज निगम ने उत्पादित बीजों में पेस्टीसाइड अवशेष एवं हैवी मेटल अवशेष की जांच अधिकृत प्रयोगशाला में कराई है, जो मानक स्तर पर खरा उतरा है। इसके साथ ही किसानों को मिट्टी जांच के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए। प्रदेश में उपजाऊ मिट्टी और पानी की समुचित उपलब्धता होने के बावजूद कुल 53 लाख हेक्टेयर खेती योग्य जमीन में अभी सिर्फ 23 लाख हेक्टेयर में ही एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। शेष 30 लाख हेक्टेयर में सिर्फ एक फसल होती है। इसके पीछे वजह है मिट्टी जांच और किसानों को प्रोत्साहित

किसानों के लिए न्यूनतम आमदनी की व्यवस्था करते हुए कृषि कारोबार को बढ़ाने का उचित प्रयास किया जाना चाहिए


बीजों की होम डिलीवरी से किसानों को होगा फायदा। प्रतीकात्मक

करने की लचर कार्यप्रणाली। वर्तमान में जिला स्तर पर मिट्टी जांच प्रयोगशाला है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोगशाला खोलने की मुहिम अब तक परवान नहीं चढ़ सकी। इस योजना को यथाशीघ्र मूर्त रूप देने की कोशिश करने के साथ किसानों से जुड़ी समस्त योजनाओं को धरातल पर उतारने की जरूरत है। किसानों के लिए न्यूनतम आमदनी की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए कृषि कारोबार को बढ़ाने का उचित प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि उनकी आय बढ़ती रहे। भूमि सुधारों पर भी गंभीरता से काम करने और किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू करने की जरूरत है। जमीन, पानी, जलवायु स्रोत और जैव विविधता की सुरक्षा के साथ ही इनकी हालत में सुधार के लिए तेजी से काम करना होगा। कृषि उत्पादकता में वृद्धि और किसानों का मुनाफा बढ़ाने सहित कृषि कारोबार को सुरक्षित बनाए रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि से जुड़े पाठ्यक्रम में भी अपेक्षित बदलाव पर जोर दिया जाना चाहिए। इससे कृषि शिक्षा बेहतर होगी। सरकार इस दिशा में प्रयासरत है, लेकिन जब तक राज्य के सभी कृषि विश्वविद्यालय अपने स्तर से पूरी तरह सजग-सक्रिय नहीं होंगे, तब तक इस दिशा में निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता।

बंगाल

भाजपा के विरुद्ध फिर मोर्चाबंदी का प्रयास

विधानसभा चुनाव में तीसरी बार जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री व तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने एक बार फिर खुद को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश के साथ भाजपा के खिलाफ मोर्चाबंदी का प्रयास शुरू किया है। यही नहीं, बुधवार को जिस तरह उन्होंने वर्चुअल रैली से भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से हटाने की बात कही उससे और भी साफ हो गया है कि ममता बनर्जी स्वयं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी सबसे बड़ा नेता मानने लगी हैं।

वैसे यह पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने भाजपा विरोधी दलों को एकजुट होकर मुकाबला करने की बात कही हैं। इससे पहले 2016 में जब दूसरी बार सत्ता में ममता आईं तो उन्होंने उसी वर्ष 21 जुलाई की रैली से भाजपा को हराने की बात कही थीं। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले देशभर के मोदी विरोधी 23 दलों के नेताओं के साथ ब्रिगेड परेड मैदान में रैली की और एकजुटता के संकेत दिए थे। परंतु चुनाव आते-आते सब बिखर गए। विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर भाजपा के अन्य नेताओं को बाहरी कहते हुए थक नहीं रही थीं। वह अपने राज्य के बाहर किस तरह लोगों के बीच जाएंगी, यह तो वक्त बताएगा। ममता ने कहा कि अभी से ही 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा।

यह पहली बार नहीं है जब ममता ने भाजपा विरोधी दलों को एकजुट होने की बात कही है। 2016 में सत्ता में आने के बाद भी ममता ने भाजपा को हराने की बात कही थी

बुधवार की रैली में दिल्ली के कंस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम में एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सुप्रियो सुले, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, पी चिदंबरम, सपा नेता रामगोपाल यादव, जया बच्चन, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, राजद के मनोज झा जैसे भाजपा विरोधी नेता जुटे थे।

खबर है कि आगामी कुछ दिनों में ममता बनर्जी भी दिल्ली जाने वाली हैं और वहां विभिन्न दलों के नेताओं से मुलाकात कर आगे की रणनीति पर चर्चा करने वाली हैं। परंतु यहां बड़ा सवाल यह है कि देश में विभिन्न क्षेत्रीय दलों के कई क्षत्रप हैं जिनके मन में पीएम की कुर्सी पर बैठने की इच्छा वर्षों पुरानी है। ममता भले ही अपने मुंह से न कहे, लेकिन वह भी पीएम बनने का सपना संजोये हुए हैं। यही वजह है कि इस बार अपनी वर्चुअल रैली का प्रसारण बंगाल तक ही सीमित नहीं रखा। पहली बार तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, त्रिपुरा, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों में भी प्रसारण किया गया। ममता ने बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी में संबोधित किया, ताकि अन्य प्रदेश के लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। परंतु उनके लिए दिल्ली की राजनीति आसान नहीं है।

राजुला ने नक्सलवाद की राह छोड़ी तो पुलिस ने पकड़ाई कलम-किताब

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की 17 वर्षीय राजुला हिडामी पुलिस की मदद से न सिर्फ नक्सलवाद की राह छोड़ने में कामयाब हुई, बल्कि इस वर्ष दसवीं की परीक्षा भी 51.08 फीसद अंकों के साथ पास करने में सफल हुई है। अब राजुला की इच्छा पुलिस विभाग में भर्ती होने की है।

साथ ले गए थे नक्सली: राजुला नक्सलवाद प्रभावित गढ़चिरौली जिले के आदिवासी गोंड समाज से आती है। पिता नहीं हैं। जब वह मात्र 15 वर्ष की थी, तभी उसके गांव लव्हारी में नक्सलियों का एक दल आया और रास्ता दिखाने के बहाने राजुला को अपने साथ ले गया। दल ने उसे वापस नहीं आने दिया और अपने साथ ही लेकर चला गया। माओवादियों ने राजुला को पहले वाकी-टाकी चलाना सिखाया, फिर उसे हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। जल्द ही वह नक्सलियों के कोरची-खोब्रामेंडा-कुरखेड़ा दलम की सदस्य बन गई। कच्ची उम्र में ही राजुला ने पुलिस के विरुद्ध कुछ अभियान में भी हिस्सा लिया। इसी दलम में राजुला के रिश्ते का चाचा भी सक्रिय था। अगस्त 2018 में राजुला के चाचा ने गोंदिया पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया तो राजुला भी उसके साथ ही नक्सलवाद छोड़कर आ गई।

तब एक दर्जन मामले दर्ज थे : उस समय गोंदिया के पुलिस अधीक्षक (एसपी) रहे

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 17 वर्षीय बालिका ने पास की दसवीं की परीक्षा


स्कूल में प्रवेश मिलने के समय राजुला हिडामी। सौ. पुलिस विभाग

हरीश बैजल बताते हैं कि जब वह 17 वर्षीय बालिका उनके सामने लाई गई तो उस पर करीब एक दर्जन मामले दर्ज थे। उसकी मां भी दूसरी शादी करके नए पति के साथ रहने चली गई थी। घर पर कोई नहीं था। उसे भेजते भी तो कहां? सातवीं कक्षा तक पढ़ी राजुला आगे पढ़ाई करना चाहती थी। बैजल ने उसकी यह इच्छा पूरी करने की ठानी और यह जिम्मेदारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) संदीप आटोले को सौंपी।

नहीं थे पढ़ाई से संबंधित दस्तावेज : राजुला के पास उसकी पढ़ाई-लिखाई से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। उसके अतीत को देखते हुए कोई स्कूल उसे दाखिला देने को भी तैयार नहीं था, लेकिन देवरी के एक आदिवासी विद्यालय एवं हास्टल में आठवीं कक्षा में पुलिस उसका दाखिला करवाने में सफल रही। एएसपी आटोले ने उसके लिए कापी-किताबें, बस्ता, कपड़े और साइकिल खरीदी। पुलिस के नक्सल सेल ने अध्यापकों से भी उसकी मदद करने की सिफारिश की ताकि उसे नए माहौल में रचने-बसने में दिक्कत न हो। पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ तो राजुला ने आठवीं, नौवीं और अब दसवीं की परीक्षा पास कर ली है।

नक्सल सेल के पुलिसकर्मी अब भी रखते ध्यान : इस बीच हरीश बैजल का स्थानांतरण मुंबई एवं संदीप आटोले का पुणे हो चुका है, लेकिन स्थानीय अभिभावक के तौर पर गोंदिया नक्सल सेल के कुछ पुलिसकर्मी अब भी राजुला की मदद के लिए तैयार रहते हैं। स्कूल की छुट्टियां होने पर सब बच्चे हास्टल छोड़कर अपने-अपने घर चले जाते हैं। तब राजुला एक परिवार के सदस्य की भांति कभी संदीप आटोले के घर आ जाती है, तो कभी नक्सल सेल का ही कोई और साथी उसे अपने घर ले जाता है। पुलिस विभाग चाहता था कि दसवीं के बाद राजुला कोई डिप्लोमा करके अपने जीवनयापन की राह निकाल ले, लेकिन वह आगे पढ़कर पुलिस विभाग में काम करना चाहती है। आटोले कहते हैं कि देवरी में ही उसके स्नातक तक पढ़ने की सुविधा है। आदिवासी होने के कारण उसकी शिक्षा पर भी बहुत खर्च नहीं आता। इसलिए वह अपनी इच्छानुसार पढ़ाई जारी रखकर भविष्य बना सकती है।

टिहरी झील पर बनेगा पारदर्शी ग्लास ब्रिज

अनुराग उनियाल, नई टिहरी : चीन के हुनान प्रांत में टियानमेन माउंटेन नेशनल पार्क में दो चोटियों से जोड़ने वाले 1410 फीट लंबे और छह मीटर चौड़े ग्लास ब्रिज की तर्ज पर टिहरी झील के ऊपर भी पारदर्शी ग्लास ब्रिज का निर्माण होगा। इसके अलावा झील के बीच टापू में भगवान शिव की मूर्ति व हाट बजार और टिपरी रोपवे का आधुनिकीकरण भी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी टिहरी झील समग्र विकास योजना के तहत किया जाएगा।

टिहरी झील में 800 करोड़ की लागत से पर्यटन विकास के कार्य होने हैं। इसके लिए बीते माह कार्यदायी संस्था वैपकोस की टीम ने झील का निरीक्षण किया था और अब डीपीआर बनानी शुरू कर दी है। योजना के तहत प्रतापनगर वासियों की सुविधा के लिए टिहरी झील में टिपरी रोपवे का विकास भी किया जाएगा। फिलहाल इस रोपवे में सामान्य डिब्बा लगाया गया है। लेकिन योजना के तहत डिब्बे में काफी हाउस और बेहतर फर्नीचर रखा जाएगा। जिला पर्यटन अधिकारी सोबत सिंह राणा ने बताया कि पर्यटक टिपरी से मदन नेगी तक रोपवे से जाएंगे और वहां से धारकोट के बीच टिहरी झील के ऊपर करीब 800 मीटर लंबे ग्लास ब्रिज का निर्माण होगा। धारकोट पहुंचने के बाद छह किमी के पैदल ट्रैक से सीधे टिहरी रियासत की राजधानी रहे प्रतापनगर महल तक पहुंचा जा सकेगा। टिहरी के जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि टिहरी झील के ऊपर ग्लास ब्रिज निर्माण का प्रस्ताव है। कार्यदायी संस्था प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार कर रही है।

मतांतरण में पैसे और छद्म लड़ाई का जोर, संघर्ष कर रहे हिंदू संगठन

संजय कुमार, रांची

झारखंड सहित पूरे देश में जिस रफ्तार से ईसाई मिशनरियां मतांतरण में लगी हुई हैं, उससे यह स्पष्ट है कि हिंदू संगठन अपने समाज को टूटने से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन संगठनों की मानें तो ईसाई मिशनरियां पैसे और झूठ का सहारा लेकर लोगों को बरगलाती हैं। उन्हें बेहतर जिंदगी के सपने दिखाए जाते हैं। आर्थिक मदद दी जाती है। इससे लोग उनके प्रभाव में आ जाते हैं। हालांकि चमकधमक कुछ ही दिनों के लिए होती है, मतांतरण के बाद ज्यादातर परिवार आज भी वैसी ही जिंदगी जी रहे, यह भी सच है। हिंदू संगठन स्वीकारते हैं कि इन मिशनरियों से लोहा लेने के लिए और अधिक प्रयास की जरूरत है। जरुरतमंदों को आर्थिक रूप से मदद के साथ ही सेवा कार्य बढ़ाने पर भी जोर देना होगा।

विहिप के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे का कहना है कि 400 वर्षों से भारत में ईसाई मिशनरियां मतांतरण के काम में लगी हैं। पैसा के बल पर हजारों लोगों को उन्होंने इस काम में लगा रखा है। मतांतरण के काम के लिए ही उनके पास विदेश से धन आता है। पूरे देश में ईसाई मिशनरियों से प्रभावित हजारों स्वयंसेवी संस्थाएं भी विदेशी पैसे के बल पर इस काम में लगी हैं। हम लोगों के पास उनके मुकाबले पैसे की कमी है। बावजूद यह भी सच है कि इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि भारत इस

चिंता की बात

- विहिप के महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा, जरूरतमंदों तक सेवा कार्य बढ़ाना होगा
- हिंदू समाज को भी होना होगा जागृत, आंखें खुली रखनी होंगी


विहिप के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे का दावा, 400 वर्षों से भारत में ईसाई मिशनरियां मतांतरण के काम में लगी हैं। फाइल/इंटरनेट मीडिया

छद्म लड़ाई के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, जबकि विश्व के 126 देश ईसाई बन गए।

जागरुकता से लड़नी होगी लड़ाई : परांडे ने कहा कि राम मंदिर निधि संग्रह अभियान के समय हमलोग देश के 5.50 लाख गांवों तक पहुंचे। वहां उत्साही लोगों को अपने साथ जोड़ा। अब गांवों में पादरियों का विरोध शुरू हुआ है, हम तक सूचना पहुंच रही है। छद्म लड़ाई में माहिर मिशनरियां अलर्ट हो गई हैं, अब वे गेरुआ वस्त्र धारण कर लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। रूद्राक्ष की माला पहनकर उसमें क्रॉस लगाते हैं। लोग धीरे-धीरे अब इनकी धूर्तता को समझने लगे हैं। जर्मनी में तो दो लाख लोगों ने कैथोलिक चर्च को छोड़ दिया है। अपने देश में भी जागरुकता फैल रही है, इसमें और तेजी लाने के लिए समाज को आगे आना होगा। हिंदू समाज का हर व्यक्ति अपने समाज को संगठित रखने के लिए सिपाही बन जाए। अगर उसके आसपास मतांतरण का खेल हो रहा है तो उसका विरोध करे। हम तक बात पहुंचाए। बस आंखें मूंद कर नहीं रहे। समझना होगा कि समाज कमजोर होगा, परिवार कमजोर होगा तो विदेशी ताकतें हावी हो जाएंगी।

केंद्र सरकार जल्द से जल्द बनाए कानून : हिंदू जागरण मंच के क्षेत्र संगठन मंत्री डा. सुमन कुमार कहते हैं, जब मतांतरित आदिवासियों को नौकरियों में मिलने वाले आरक्षण का लाभ सहित अन्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा तब उनकी आंखें खुलेंगी। हमने केंद्र सरकार से मांग की है कि मतांतरित आदिवासियों को आरक्षण के लाभ से वंचित करने के लिए जल्द से जल्द कानून बनाए। कानून नहीं बनने से ये लोग सरना आदिवासियों का हक मार रहे हैं। हालांकि माना कि कानून बनाना सरकार काम है, यह बनता रहेगा। परंतु हमें सुदूर ग्रामीण इलाकों में अपना काम तेजी से बढ़ाना होगा।

जागरण विशेष

सेहत को गोमाता का 'अनादि' आशीर्वाद, देशी घी में बिल्व पत्र की पौष्टिकता

फरीदाबाद के वृद्धाश्रम में 30 लीटर दूध से तैयार होता है एक लीटर घी, दुबई, अमेरिका, हांगकांग और सिंगापुर तक भेजा जा रहा

अनिल बेताब • फरीदाबाद

'अनादि' देशी घी, वह भी बिल्व पत्र के साथ माटी की हांडी में पका हुआ। दावा है कि यह घी न तो कोलेस्ट्राल बढ़ाता है और न ही शुगर। कई वर्षों से मुंबई, नोएडा, नागपुर, असम के साथ ही दुबई, अमेरिका, हांगकांग, सिंगापुर में बसे भारतीय और वहां के स्थानीय निवासी भी इसे पसंद करते हैं। फरीदाबाद के अनादि सेवा प्रकल्प वृद्धाश्रम में वयस्क, बुजुर्ग महिलाएं गायों की सेवा करती हैं, दूध दुहती हैं, उनकी देखभाल करती हैं और फिर विशेष तरीके से घी तैयार करती हैं। इस घी की कीमत 2,640 रुपये प्रति लीटर है।

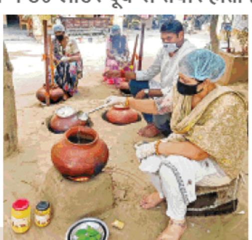
रोजाना मिलता है करीब तीन सौ लीटर दूध: वृद्धाश्रम के संचालक प्रणव शुक्ला बताते हैं कि गोधाम में गीर, साहीवाल और डांगी नस्ल की 35 गाय ऐसी हैं, जिनसे रोजाना करीब 300 लीटर दूध प्राप्त होता है। इस तरह महीने में लगभग नौ हजार लीटर दूध निकलता है। करीब तीन हजार लीटर दूध आसपास के क्षेत्र के लोग 70 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से खरीदते हैं और छह हजार लीटर दूध से लगभग 200 लीटर देशी घी बनाया जाता है। घी की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उसके साथ बिल्व पत्र पकाया जाता है। आश्रम में 37 बुजुर्ग हैं। इनमें से 21 महिलाएं हैं। हर सोमवार और गुरुवार को पांच महिलाएं आशा, कृष्णा, रामलली, अंगूरी तथा हरनंदी मिट्टी के चूल्हे पर दूध से घी बनाने के काम में जुटी रहती हैं। करीब 67 वर्षीय रामलली कहती हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हम गोमाता की सेवा में इस तरह से जुड़े हैं।

वृद्धाश्रम की गाय करती हैं खास चारे का सेवन: गायों के आहार में नीम के पत्ते और चूना के अलावा जयवंती पंचांग तथा सतावर भी मिलाया जाता है। वृद्धाश्रम में गायों को गेहूं का दलिया, चने की दाल, जौ और मक्का भी खाने को दिया जाता है। यहां गायों को अक्टूबर से मार्च तक सर्दी के मौसम में चारे में हल्दी का सेवन भी कराया जाता है।

ऐसे 30 लीटर दूध से बनता है देशी घी: मक्खन तैयार करने में व्यस्त रामलली घी बनाने की विधि को बड़ी सहजता से बताती हैं। सबसे पहले 30 लीटर दूध को हांडी में तीन-चार घंटे हल्की आंच पर पकाया जाता है। इसमें लगभग दो लीटर दूध पक जाता है। यानी 28 लीटर दूध बचता है। इसे ठंडा करने के बाद दही जमा दिया जाता है। दही को मथा जाता है। करीब सवा घंटा मथने की प्रक्रिया चलती है, तब जाकर इसमें से मक्खन निकाला जाता है। मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता। इस दौरान दो से तीन बार ठंडा पानी और बर्फ भी डाली जाती है। इस प्रक्रिया के बाद सवा लीटर मक्खन निकलता है। सवा लीटर मक्खन को चूल्हे पर पकाया जाता है और इस तरह लगभग 30 लीटर दूध से एक लीटर देशी घी तैयार होता है।

इसलिए है इतनी कीमत

- अनादि सेवा प्रकल्प के देशी घी की कीमत अधिक होने के कारण भी हैं।
- 30 लीटर दूध की कीमत : 2,100 रुपये
- चूल्हे पर हल्की आंच पर घी तैयार करने को उपले, पैकिंग, थर्माकोल और कांच के जार का खर्चा : 300 रुपये
- एक लीटर घी का मुनाफा : 240 रुपये, इससे वृद्धाश्रम और गोधाम का खर्चा चलता है।
- इस तरह कुल कीमत 2,600 रुपये से ऊपर पहुंच जाती है।


फरीदाबाद के अनादि सेवा प्रकल्प वृद्धाश्रम में इस तरह तैयार किया जाता है घी • जागरण

"मेरा शुगर लेवल 240 रहता था, कोलेस्ट्राल भी बढ़ा रहता था। डाक्टर ने चिकनाई बिलकुल बंद करा दी। आप तो जानते ही हैं, बड़े बुजुर्ग घी, दूध के मोह से निकल नहीं पाते। मेरे साथ भी यही दिक्कत थी। फिर मेरे बेटे ने मुझे अनादि घी लाकर दिया। इसे खाते हुए पांच-छह साल हो गए हैं। अब मेरा शुगर लेवल भी सामान्य रहता है और कोलेस्ट्राल की भी कोई दिक्कत नहीं है।


-डीएस यादव, 83 वर्ष

अगर हम प्रतिदिन इस प्रक्रिया के अनुरूप गाय के दूध से तैयार घी का 10 से 15 ग्राम सेवन करते हैं तो इससे विटामिन ए और डी मिलता है। फेफड़े मजबूत रहते हैं, पेट और त्वचा संबंधी बीमारियों से बचाव होता है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द में भी लाभकारी है।


-डा. पंकज छाबड़ा, सीनियर कंसलटेंट, मेट्रो अस्पताल

अन्य घी भी इस्तेमाल किए लेकिन उनमें शुद्धता का अभाव था। बटर आयल मिलाते हैं। यहां कैसी शुद्धता के साथ घी बनता है, यह मैंने खुद देखा है। -**निकिता शर्मा**, मेकअप आर्टिस्ट, दुबई

मुझे इस घी में जो स्वाद मिला, वह और ब्रांड में नहीं मिला। विशेष बात इसमें बिल्व पत्र को पकाकर इसे तैयार किया जाता है। इसकी खुशबू और महीन दाने शुद्धता को प्रमाणित करते हैं। -**डेबरा जिलबट**, न्यूयार्क"

इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें

नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा अब 11 अगस्त को

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : जेईई मेन और नीट के बाद शिक्षा मंत्रालय ने नवोदय विद्यालय की छठवीं कक्षा में दाखिले के लिए शैक्षणिक सत्र 2021-22 की प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा की तारीख का एलान कर दिया है। यह परीक्षा 11 अगस्त को देश भर के 11 हजार से ज्यादा केंद्रों पर आयोजित होगी। देश के लगभग सभी जिलों में एक नवोदय विद्यालय है। खास बात यह है कि इन विद्यालयों में दाखिला प्रवेश परीक्षा के जरिए लिया जाता है। यह विद्यालय आवासीय होते हैं।

कोरोना संकट के चलते अब तक इस परीक्षा का आयोजन टलता रहा है। लेकिन कोरोना संक्रमण की स्थिति को सामान्य होते देख शिक्षा मंत्रालय ने इसकी तारीख का एलान कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर प्रवेश परीक्षा से जुड़ी तारीख की जानकारी दी है। परीक्षा के दौरान कोरोना प्रोटोकाल का पूरा ध्यान रखने के भी निर्देश दिए हैं। इस परीक्षा के जरिए 47,320 बच्चों का छठवीं कक्षा में दाखिले के लिए चयन किया जाता है।

24 जुलाई को पृथ्वी के पास से एक उल्का पिंड गुजरेगा। यह जानकारी नासा ने दी है। इस उल्का पिंड का नाम 2008 जीओ20 है। यह एक अपोलो क्लास एस्टेरायड है। इसका आकार ताज महल से करीब तीन गुना अधिक है।

न्यूज गैलरी

दुष्कर्म आरोपित वेइंस्टेन को कैलिफोर्निया लाया गया

लास एंजिलिस : न्यूयार्क जेल के अधिकारियों ने दुष्कर्म आरोपित हार्वे वेइंस्टेन को कैलिफोर्निया को सौंप दिया है। यहां वह दुष्कर्म के चार मामलों समेत यौन हमले के 11 मामलों का सामना करेगा। इसके साथ ही पूर्व फिल्मी हस्ती के प्रत्यर्पण की लंबी लड़ाई का अंत हो गया। रिकार्ड से पता चलता है कि मंगलवार को 69 वर्षीय वेइंस्टेन को लास एंजिलिस की जेल में भेज दिया गया। उसके वकील मार्क वेर्क्समैन के अनुसार, बुधवार से उसके खिलाफ सुनवाई शुरू होनी है। (एपी)

हांगकांग पुलिस ने एपल डेली के वरिष्ठ संपादक को गिरफ्तार किया

हांगकांग : हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा पुलिस ने बंद हो चुके लोकतंत्र समर्थक अखबार एपल डेली के पूर्व संपादक को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों द्वारा संपत्ति जब्त किए जाने के बाद करीब एक महीने पहले यह अखबार बंद हो चुका है। पुलिस ने कहा कि 51 वर्षीय पूर्व संपादक को बुधवार को जून के जैसे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। जून में समाचारपत्र के कार्यालय पर छापेमारी कर पुलिस ने सुबूत के तौर पर हार्ड ड्राइव और लैपटाप जब्त कर लिए थे और इसके शीर्ष एग्जिक्यूटिव संपादकों और पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया था। (एपी)

उत्तर कोरिया के खिलाफ मिलकर काम करेंगे तीन देश

टोक्यो : अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण एवं अन्य क्षेत्रीय खतरों पर मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, लेकिन दोनों अमेरिकी सहयोगियों को करीब लाने में कोई प्रगति नहीं दिखाई है। अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शेरमैन ने टोक्यो में अपने समकक्ष जापानी उप विदेश मंत्री टाकेओ मोरी और दक्षिण को रिया के चोई जोंग-कुन के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि उनका गठबंधन शांति, सुरक्षा और समृद्धि का समर्थक बना हुआ है। (एपी)

जेल में बंद म्यांमार के राजनेता का कोरोना से निधन

यंगून : सैनिकों द्वारा तख्तापलट में सत्ता से बेदखल की गई म्यांमार की नेता अंग सान सू की के वरिष्ठ सलाहकार न्यान विन की मंगलवार को एक अस्पताल में मौत हो गई। जेल में बंद रहने के दौरान वह कोरोना से संक्रमित हो गए थे। (रायटर)

राष्ट्रपति की हत्या के बाद हैती ने नया पीएम नियुक्त किया

पोर्ट-औ-प्रिंस : हैती सरकार ने मंगलवार को एरिएल हेनरी को औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। करीब दो सप्ताह पहले राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संदेह है कि राष्ट्रपति की हत्या की साजिश कैरेबियाई देश की सीमा से बाहर रची गई। (रायटर)

चीन में हजार साल की सबसे भीषण बारिश से तबाही

- सेना ने हेनान प्रांत में उफनती नदी के पानी को मोड़ने के लिए क्षतिग्रस्त बांध को उड़ाया
- सुरंग में डूबती मेट्रो में सैकड़ों लोगों को बचाने की जद्दोजहद, हजारों लोग रास्तों में फंसे, अब तक 25 की मौत

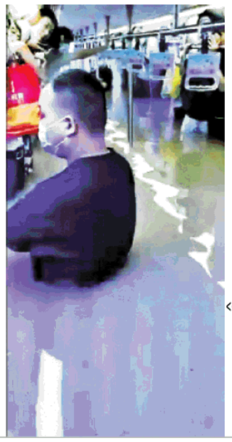
बीजिंग, प्रेट्र : चीन के हेनान प्रांत में मौसम का कहर टूटा है। एक हजार साल की सबसे भीषण बारिश से भयावह बाढ़ के हालात बन गए हैं। एक दर्जन से अधिक शहर जलमग्न हो गए। टनल में फंसी मेट्रो में पानी भर गया और स्टेशनों से लोग निकल नहीं पाए। यिचुआन में उफनती नदी के पानी को मोड़ने के लिए सेना को एक क्षतिग्रस्त बांध को उड़ाना पड़ा है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।

ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 12 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पौने दो लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, इनमें मेट्रो ट्रेन में पानी भरने से मरने वाले 12 लोग शामिल हैं। मेट्रो सुरंगें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं। राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा है कि राहत कार्य मुश्किल भरा है।

झेंगझोऊ रेलवे स्टेशन से जाने वाली करीब 160 ट्रेन रोक दी गई हैं। हजारों लोग बिना बिजली-पानी के रहने को मजबूर हैं। सैकड़ों फ्लाइट रद कर दी गई हैं। बाढ़ में बौद्ध भिक्षुओं का शाओलिन मंदिर भी घिरा हुआ है। यह मंदिर मार्शल आर्ट के कारण विश्व प्रसिद्ध है।

रायटर के अनुसार, सबवे ट्रेनों में फंसे यात्री जान बचाने के लिए हैंडलबार से चिपककर राहत दल का इंतजार कर रहे थे। ये लोग गर्दन तक पानी में डूबे हुए थे। बाढ़ से घिरी सबवे ट्रेनों से 500 लोगों को राहत दलों ने निकाला है। हेनान प्रांत के एक दर्जन शहरों में पानी भरा हुआ है।

मौसम विभाग का अगले तीन दिनों तक बारिश का अनुमान है। झेंगझोऊ में शनिवार से मंगलवार तक 617.1 मिमी. तक बारिश हो गई थी। यह पूरे साल की औसतन 640.8 मिमी. बारिश के लगभग बराबर है। ऐसी बारिश हजार साल बाद हुई है।





चीन के हेनान प्रांत के झेंगझोऊ में बारिश के बाद आई बाढ़ में सैकड़ों वाहन बह गए। एएफपी

हेनान प्रांत में तीन दिन की बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहां इतनी बारिश हो रही है, जितनी एक हजार साल में नहीं हुई। हेनान की राजधानी जेंगजू में सबवे लाइन पूरी तरह डूब गई और मेट्रो ट्रेन में पानी भर गया। ट्विटर से



झेंगझोऊ में बारिश के बाद आई बाढ़ में फंसी महिला को ले जाता युवक। रायटर

वर्जीनिया सैन्य अड्डे में रखे जाएंगे अफगान सहयोगी

फैसला ▸ सेना की मदद करने वाले अफगानियों को मिली राहत

काबुल पर राकेट हमले की अमेरिका ने की निंदा

काबुल, एएनआइ : अमेरिका अपनी सेना के साथ काम करने वाले अफगान सहयोगियों को वीजा प्रक्रिया पूरी होने तक वर्जीनिया ले जाकर वहां के सैन्य अड्डे पर रखेगा। अफगानिस्तान में ईद के कारण हिंसा की वारदातें थमी रहीं। काबुल में राष्ट्रपति पैलेस को निशाना बनाकर हमले की अमेरिका ने निंदा की है।

बाइडन प्रशासन ने सीनेट में अवगत कराया है कि दुभाषिए, ड्राइवर या इंजीनियर जैसे पदों पर रहकर अमेरिकी सेना की मदद करने वाले ढाई हजार अफगान सहयोगियों और उनके परिवार को वर्जीनिया के सैन्य अड्डे फोर्ट ली में शरण दी जाएगी। उन्हें वीजा प्रक्रिया शुरू होने के तुरंत बाद ले जाया जा रहा है। सभी को वीजा प्रक्रिया पूरी होने तक वहां रहना पड़ेगा। अमेरिकी सेना के साथ काम करने वाले इन अफगान सहयोगियों को तालिबान के द्वारा निरंतर धमकी दी जा रही है। इनके लिए अमेरिका ने विशेष आव्रजन योजना शुरू की है।

प्रेट्र के अनुसार, अमेरिका ने ईद पर राष्ट्रपति अशरफ गनी के पैलेस को निशाना बनाकर किए राकेट हमलों की निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि हिंसा मूर्खतापूर्ण है और इस समस्या का जल्द से जल्द राजनीतिक समाधान निकाला जाना चाहिए।

पाकिस्तान में खुले आम घूम रहे हैं तालिबान व अन्य आतंकी : एएनआइ के अनुसार, पाकिस्तान के विपक्षी सांसद मोहसिन डावर ने कहा है कि तालिबान व अन्य आतंकी संगठन के लोग देश में खुलेआम घूम रहे हैं। यह काम बिना सरकारी संरक्षण के नहीं हो सकता है। यहां आए दिन तालिबान की जीत पर जश्न मनाया जा रहा है। तालिबान के झंडे फहराकर नारेबाजी की जाती है।



वर्जीनिया सैन्य अड्डा। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

हमने कभी खुशी नहीं, हमेशा संघर्ष के दिन देखे

एएनआइ के अनुसार अफगान सेना और तालिबान के बीच चल रहे संघर्ष में हजारों परिवार विस्थापित हो गए हैं। टोलो न्यूज के अनुसार कुंदुज की रहने वाली जीबा ने बताया कि उसने अपने सभी बच्चों को इस लड़ाई में खो दिया। हमने कभी खुशी का दिन नहीं, हमेशा संघर्ष के दिन देखे हैं। मोहम्मद हसन ने बताया कि वह संघर्ष में चौथी बार विस्थापित हो रहे हैं। एक विस्थापित महफूजा ने बताया कि उन्हें नहीं मालूम कि ईद कब है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक अब तक पौने तीन लाख परिवार विस्थापित हो चुके हैं।

अफगान राजदूत की बेटी के अपहरण का इल्जाम भारत पर

इस्लामाबाद, एएनआइ : इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के राजदूत की बेटी के अपहरण मामले में पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने अजीबोगरीब बयान दिया है। कहा है कि इस अपहरण कांड के पीछे भारत और अफगानिस्तान हैं। दोनों देश जान-बूझकर वारदात से संबंधित तथ्यों को छिपा रहे हैं और उन्हें गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने घटना और पाकिस्तानी मंत्री के बयान पर नाखुशी जाहिर की है।

रावलपिंडी में मीडिया से बातचीत में शेख राशिद ने कहा, राजनयिक की बेटी का अपहरण कोई आपराधिक वारदात नहीं है। वास्तव में यह पाकिस्तान को बदनाम और उसे अस्थिर करने की साजिश है। पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी साजिशें सिलसिलेवार हो रही हैं। अफगान राजनयिक नजीबुल्ला अलीखिल की बेटी सिलसिला अलीखिल शुक्रवार को कई घंटों के लिए अगवा हो गई थीं। घटना के समय वह अपने घर लौट रही थी। जबर्दस्ती रोके जाने के दौरान अज्ञात लोगों ने सिलसिला का कई घंटे उत्पीड़न किया। शेख राशिद ने कहा कि जांच में अफगान राजदूत की बेटी का अपहरण होने का कोई सुबूत नहीं मिला है। जियो न्यूज के मुताबिक मंत्री ने कहा है कि अफगान राजदूत के बेटी की गुमशुदगी की मामला उसके अपहरण से जुड़ा नहीं है। राजदूत की बेटी का अपहरण नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि शेख राशिद भारत को लेकर अजीबोगरीब बयानों के लिए जाने जाते हैं। वह लंबे समय से सरकार में मंत्री हैं और उनका भारत विरोधी रुख भी पुराना है।



शेख राशिद अहमद फाइल/इंटरनेट मीडिया

पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने दिया अजीबोगरीब बयान

जबकि पीड़ित लड़की के अनुसार शुक्रवार को वह इस्लामाबाद की एक बेकरी शॉप में गई थी। दोपहर बाद जब वह टैक्सी से वापस अपने घर लौट रही थी, तभी ड्राइवर को हटाकर एक अन्य आदमी ने टैक्सी कब्जे में ले ली और उसे अनजानी जगह पर ले गया। वहां पर उसे गालियां दी गईं और उसकी पिटाई की गई। बाद में उसे बेहोशी की दशा में सड़क के किनारे फेंक दिया गया। शेख राशिद ने कहा है कि टैक्सी को किसी अन्य व्यक्ति ने कब्जे में नहीं लिया था। अपहरण जैसी कोई वारदात नहीं हुई। अफगान और भारतीय मिलकर तथ्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

पाकिस्तानी मंत्री का बयान गैर पेशेवर : अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुहम्मद हनीफ अतमार ने पाकिस्तानी समकक्ष शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोन पर वार्ता कर शेख राशिद के बयान पर विरोध और चिंता जताई। कहा कि राजदूत की बेटी के अपहरण मामले में पाकिस्तानी गृह मंत्री का बयान गैर पेशेवर और चिंताजनक है। इससे दोनों देशों के संबंधों और विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है।

अमेरिका में कमीशन लेने में फंसे दो भारतीय डाक्टर

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका में दो भारतीय डाक्टर और एक बड़ा अस्पताल चलाने वाली कंपनी महंगे इलाज और कमीशनखोरी के आरोप में फंस गए हैं। ये डाक्टर उक्त अस्पताल में मरीज भेजते थे और बदले में मोटी रकम कमीशन के तौर पर लेते थे। इनमें एक डाक्टर अस्पताल के मालिक हैं। न्याय विभाग के अनुसार, अब इन आरोपों को सुलझाने के लिए दोनों डाक्टर और कंपनी को 3 करोड़ 75 लाख डालर (करीब 280 करोड़ रुपये) का भुगतान करना होगा, जो उन मरीजों को वापस किया जाएगा, जिनसे इलाज के लिए अनाप-शनाप रकम ली गई।

यह मामला कैलिफोर्निया के कार्डियोलाजिस्ट डा. शिव अरुणाशलम और प्राइम हेल्थ केयर सर्विस के सीइओ डा. प्रेम रेड्डी का है। ये दोनों डाक्टर कैलिफोर्निया के विक्टर विले स्थित डेजर्ट वैली अस्पताल में मरीजों को भर्ती कराते थे। जहां उन मरीजों के अनाप-शनाप बिल बनाए गए। मरीजों से लिया गया यह भुगतान निर्धारित किए गए इलाज की रकम से ज्यादा है। मीडिया में जारी बयान के अनुसार कानूनी प्रक्रिया शुरू होने के बाद दोनों डाक्टर व अस्पताल चलाने वाली कंपनी प्राइम हेल्थकेयर सर्विस ने समझौते के तहत तीन करोड़ 75 लाख डालर का भुगतान करने पर सहमति दे दी है। न्याय विभाग ने कहा है कि मरीजों को अस्पताल में भेजने के बदले डाक्टरों का कमीशन लेना स्वास्थ्य ढांचे को कमजोर करना है। यह मरीजों के साथ भी नाइंसाफी है।

रूसी निर्माताओं ने नए लड़ाकू जेट की प्रतिकृति का किया अनावरण



मास्को के बाहरी इलाके जुकोवस्की स्थित माक्स-2021 इंटरनेशनल एविएशन एंड स्पेस सैलून में प्रदर्शित संभावित युद्धक विमान की प्रतिकृति। एपी

मास्को, एपी : रूसी विमान निर्माताओं ने गत दिवस को एक नए लड़ाकू जेट की प्रतिकृति का अनावरण किया। इसमें स्टील्थ क्षमताओं के साथ अन्य उन्नत विशेषताएं हैं और इसे विदेशी खरीदारों के सामने पेश किया जाएगा।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गत दिवस मास्को के बाहर जुकोवस्की स्थित माक्स-2021 इंटरनेशनल एविएशन एंड स्पेस सैलून में संभावित युद्धक विमान का निरीक्षण किया था। रूसी विमान निर्माता कंपनी सुखोई ने एलटीएस कार्यक्रम के तहत नया लड़ाकू विमान विकसित किया, जो लाइट टैक्टिकल एयरक्राफ्ट के लिए संक्षिप्त रूसी नाम है। इसके निर्माताओं ने कहा कि प्रोटोटाइप 2023 में अपनी पहली उड़ान भरने के लिए तैयार है और इसका वितरण 2026 में शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि नए डिजाइन को बिना पायलट वाले संस्करण और दो सीटों वाले माडल में बदला जा सकता है। इस संभावित युद्धक विमान में एक इंजन है और यह रूस के ही एक अन्य विमान एसयू-57 से छोटा और सस्ता है।

नार्वे की संसद पर साइबर अटैक के मामले में चीन के राजदूत तलब

- 10 मार्च को ईमेल प्रणाली से छेड़छाड़ की जानकारी सामने आई
- इस हरकत के लिए नार्वे की सरकार को चीन पर संदेह

ओस्लो, एएनआइ : नार्वे के विदेश मंत्री इने एरिक्सन ने मंत्रालय को सूचित किया है कि देश की संसद पर साइबर हमले को लेकर चीन के राजदूत को तलब किया गया है। 10 मार्च को स्टोरिंग (नार्वे की संसद) ने बताया था कि उसकी ईमेल प्रणाली के साथ छेड़छाड़ की गई है। माइक्रोसाफ्ट एक्सचेंज साफ्टवेयर की नाजुक सुरक्षा में सेंध लगाई गई थी।

विदेश मंत्रालय ने एरिक्सन के हवाले से कहा है, 'सभी साइबर आपरेशन विभिन्न तरह के निशान छोड़ते हैं और तब अन्य बातों के अलावा हमारी सुरक्षा एजेंसियां उसका आकलन करती हैं और उसकी सूचनाएं जुटाती हैं। उसी सूचना के आधार पर सरकार ने एक आकलन किया है कि वह हमला चीन से किया गया था।' एरिक्सन ने कहा है, 'यह एक गंभीर घटना है थी जिसने हमारी सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संस्था को प्रभावित किया है। हम उम्मीद करते हैं कि चीन इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सुनिश्चित करेगा कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी।' मार्च में चीन के हैकरों ने आस्ट्रेलिया के पश्चिमी संसदीय ईमेल नेटवर्क पर हमला किया था। यह माइक्रोसाफ्ट साफ्टवेयर से दुनिया के सबसे बड़े हमले के तहत किया गया था। चार मार्च को चुनाव प्रचार के बीच में इस आनलाइन हमले का पता चला और इसके बाद कैनबेरा में आस्ट्रेलिया के साइबर सिक्यूरिटी वाचडाग को आनन-फानन में हस्तक्षेप करना पड़ा।

चीन ने अफगानिस्तान में नया विशेष दूत नियुक्त किया

बीजिंग, प्रेट्र : चीन ने बुधवार को अफगानिस्तान में अपने विशेष दूत को बदलने की घोषणा की। युद्ध से जर्जर देश से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का चीन के शिनजियांग प्रांत पर बुरा प्रभाव पड़ने की चिंता के बीच बीजिंग ने यह कदम उठाया है। शिनजियांग में उइगर मुस्लिम आतंकियों से खतरा पैदा हो गया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिआन ने घोषणा की कि अफगानिस्तान में वर्तमान विशेष दूत लिउ जिआन की जगह कतर, जार्डन और आयरलैंड में चीन के राजदूत रह चुके यूए सिआओ योंग को विशेष दूत नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक की बेटी की इस्लामाबाद में हत्या

- अफगानिस्तान के राजदूत की बेटी के अपहरण के बाद दूसरी बड़ी घटना

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान के एक पूर्व राजनयिक की बेटी की इस्लामाबाद में हत्या कर दी गई। इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के राजदूत की बेटी के अपहरण और यातना देने को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पैदा हुए बड़े कूटनीतिक विवाद के बाद यह दूसरी बड़ी घटना हुई है।

पाकिस्तानी अखबार डान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, शौकत मुकादम की 27 वर्षीया बेटी नूर मुकादम राजधानी के सेक्टर एफ-7/4 इलाके में मंगलवार को मृत पाई गईं। शौकत मुकादम दक्षिण कोरिया और कजाखिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत रह चुके हैं। पुलिस के अनुसार, नूर की गोली मारकर हत्या की गई है। हत्या के सिलसिले में नूर के एक मित्र को गिरफ्तार किया गया है।

समा टीवी ने इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से कहा है, 'जाहिर जफर नाम का एक व्यक्ति हत्या में संलिप्त था। उसे घटनास्थल से गिरफ्तार कर थाने लाया गया।'

यह हत्या पाकिस्तान में राजनयिक मिशन और इसके कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर मचे घमासान के बीच हुई है। 16 जुलाई को पाकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत नजीबुल्लाह अलीखिल की 26 वर्षीया बेटी सिलसिला अलीखिल को इस्लामाबाद में अगवा कर बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। पिछले सप्ताह अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने एक बयान जारी कर इस घटना पर विरोध दर्ज कराया था। इस घटना को लेकर दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच कूटनीतिक विवाद पैदा हो गया। अमेरिकी और नाटो सैनिकों की वापसी के अंतिम चरण में पहुंच जाने के कारण दोनों देश तालिबान के फिर से सिर उठाने का सामना कर रहे हैं।

कोरोना से जंग

अमेरिका में अब भी 50 लाख से ज्यादा सक्रिय केस

बाइडन ने कहा, मौत के मामले घटे, लेकिन डेल्टा से रहें सावधान, टोक्यो में ओलिंपिक शुरू होने से पहले कोरोना के मामले उच्च स्तर पर

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका में कोरोना के सक्रिय मामले दुनिया में रिकार्ड स्तर पर हैं। यहां वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 50 लाख से ज्यादा है, जबकि भारत में सक्रिय मामले महज चार लाख सात हजार हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर जब पीक (चरम) पर थी, तब यहां सक्रिय मामले करीब 38 लाख तक पहुंच पाए थे।

अमेरिका में कोरोना के दैनिक मामले फिर बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान यहां 44 हजार से ज्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में नए मामलों में ब्रिटेन पहले नंबर पर है, जहां 46 हजार से ज्यादा मामले आए हैं। भारत तीसरे नंबर पर है, यहां एक दिन में करीब 42 हजार मामले रहे। 38 हजार से ज्यादा मरीजों के साथ इंडोनेशिया चौथे नंबर पर है।

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या में कमी आई है। यह कमी तेजी से लग रही वैक्सीन के कारण है, लेकिन अभी भी कोरोना के डेल्टा वैरिएंट से सावधान रहना चाहिए। देश में होने वाली मौत और अस्पताल में भर्ती होने वाले वही हैं, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है।

एपी के अनुसार, जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक शुरू होने से पहले यहां कोरोना के मामले छह माह के उच्चतम स्तर पर हैं। यहां एक दिन में 1832 नए मामले आए हैं। टोक्यो में फिलहाल कोरोना संक्रमण को देखते हुए इमरजेंसी लगी हुई है। जापान मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष तोशियो नाकागावा ने कहा है कि पहले जिस बात की चिंता थी, अब वही हो रहा है। जापान में अभी तक 23 फीसद ही टीकाकरण हो पाया है।

ब्राजील : पिछले 24 घंटे के दौरान 1424 लोगों की मौत हो गई।

आस्ट्रेलिया : लाकडाउन के बीच यहां नए संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

रूस : 23 हजार से ज्यादा एक दिन में नए मामले मिले हैं।



फ्रांस की राजधानी पेरिस में कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोकथाम के लिए काफी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। म्यूजियम देखने आए लोगों के हेल्थ पास चेक करके ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। अमेरिका सहित अन्य कई देशों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। रायटर

यूएई का एजेंट होने के आरोप में ट्रंप के खास सहयोगी गिरफ्तार

न्यूयार्क टाइम्स से

- खाड़ी देश के लिए अमेरिका में करते थे लाबिंग

वाशिंगटनः अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें बढ़ने के साथ ही उनके करीबी दोस्तों के भी मामले खुल रहे हैं। अब ट्रंप के प्रमुख सहयोगी थामस जे बराक पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उन्हें गत मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। बराक पर आरोप है कि उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के लिए लाबिंग की और अमेरिकी नीति को प्रभावित करने की कोशिश की। एक तरफ से उन्होंने यूएई एजेंट बनकर काम किया।

सांता मोनिका, कैलिफोर्निया के रहने वाले बराक उन तीन लोगों में शामिल हैं, जिन पर न्यूयार्क की संघीय अदालत में यूएई के हितों के लिए एक एजेंटे के रूप में काम करने का मुकदमा चलाया जा रहा है। इसी संबंध में उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये मामले 2016 से बाद के हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे। ट्रंप के संयुक्त अरब अमीरात से बहुत ही मधुर संबंध माने जाते रहे हैं। बराक पर इस मामले की जांच के दौरान 2019 में संघीय अधिकारियों को जांच में बाधा डालने और झूठे बयान देने का भी आरोप है। अन्य आरोपितों में बराक की कंपनी के पूर्व कार्यकारी मैथ्यू ग्रिम्स, संयुक्त अरब अमीरात के एक व्यवसायी राशिद अल मलिक हैं। इन तीनों पर यूएई के हितों के लिए अमेरिका में लाबिंग करने और लाभ पहुंचाने का आरोप है। अधिकारियों ने बताया कि बराक और ग्रिम्स को कैलिफोर्निया से गिरफ्तार किया गया है। बराक के वकील रौनक देसाई ने संभावना व्यक्त की है कि उन्हें सोमवार तक हिरासत में रखा जा सकता है।

एक नजर में

पैरालिंपिक के लिए नहीं चुने जाने पर हाई कोर्ट से गुहार

नई दिल्ली : पांच बार के पैरालिंपिक निशानेबाज और अर्जुन अवार्डी नरेश कुमार शर्मा ने चयन समिति पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। टोक्यो पैरालिंपिक के लिए निशानेबाजी टीम में नहीं चुने जाने पर नरेश ने आरोप लगया है कि चयन समिति ने नियमों को ताक पर रखते हुए उनकी जगह किसी अन्य खिलाड़ी को चुन लिया, जबकि वह सभी मापदंड पर खरे उतरते हैं। इस याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई हो सकती है। नरेश को राजीव गांधी राज्य खेल अवार्ड भी मिला हुआ है। उन्होंने याचिका में मांग की है कि पैरालिंपिक चयन समिति को आदेश दिया जाए कि उन्हें भी आर-7 निशानेबाजी स्पर्धा के लिए चुना जाए, क्योंकि वह इसके लिए सभी मापदंड पूरे करते हैं। याचिका में कहा गया है कि निशानेबाजी टीम के चयन की प्रक्रिया सही नहीं है और इसमें भेदभाव किया गया है। इसका असर उनके भविष्य पर पड़ेगा। (जासं)

टोक्यो में स्वर्ण की प्रबल दावेदारों में होंगी सिंधू : गोपी

नई दिल्ली: भारतीय बैडमिंटन के मुख्य कोच पुलेला गोपीचंद को उम्मीद है कि इस बार भारतीय एथलीट ओलिंपिक में पदकों की दोहरी संख्या तक पहुंच सकते हैं और उन्होंने विश्व चैंपियन पीवी सिंधू को स्वर्ण पदक जीतने की प्रबल दावेदारों में से एक करार दिया। गोपीचंद ने कहा, 'मेरा यह भी मानना है और उम्मीद करता हूं कि इस बार भारत अब तक की सबसे ज्यादा पदकों की संख्या जीतने में सफल होगा। लंदन में भारतीय टीम ने छह पदक जीतकर जो किया, हम उसे पीछे छोड़ सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि दोहरी संख्या में पदक जीत सकते हैं।' उन्होंने कहा, 'बैडमिंटन में हमारे पास मौके हैं, निश्चित रूप से रियो और लंदन के प्रदर्शन से बेहतर करने के। इसलिए मुझे उम्मीद है कि सिंधू जीत सकती हैं, वह निश्चित रूप से ओलिंपिक में दावेदारों में से एक होंगी। साथ ही चिराग और सात्विक भी, हालांकि उनका ड्रा काफी कठिन है। (प्रेट्र)

दर्शकों के स्टेडियमों में आने की उम्मीद

टोक्यो : बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलिंपिक की तैयारियों का निरीक्षण कर रहे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघा यानी आइओसी के अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि दुनिया भर के प्रशंसकों को अगले शीतकालीन ओलिंपिक देखने के लिए निजी तौर पर चीन जाने की स्वीकृति दी जाएगी। (प्रेट्र)

कम खिलाड़ियों के बीच में होगा उद्घाटन समारोह

न्यूनतम भारतीय खिलाड़ी होंगे शामिल, छह अधिकारी ही करेंगे शिरकत

टोक्यो, प्रेट्र : भारत के मिशन उप प्रमुख प्रेम कुमार वर्मा ने कहा कि शुक्रवार को होने वाले ओलिंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में कोरोना के कारण न्यूनतम भारतीय खिलाड़ी शामिल होंगे जबकि दल से सिर्फ छह अधिकारियों को हिस्सा लेने की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने साथ ही कहा कि जिन खिलाड़ियों को अगले दिन प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है, उन्हें उद्घाटन समारोह में हिस्सा नहीं लेने की हिदायत दी गई है। हालांकि कितने भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, इस पर फैसला गुरुवार को होगा। वहीं, ब्रिटेन ने फैसला लिया है कि वह उद्घाटन समारोह में 30 से ज्यादा खिलाड़ी नहीं भेजेगा।

खेलों में भारत के 127 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं जबकि भारतीय दल में अधिकारियों, कोचों और अन्य सहयोगी स्टाफ सहित कुल 228 सदस्य शामिल हैं। वर्मा ने यहां मिशन प्रमुखों की बैठक के बाद कहा, 'समारोह में छह अधिकारियों (प्रत्येक देश से) को हिस्सा लेने की स्वीकृति दी गई है। हालांकि जिन खिलाड़ियों की अगले दिन प्रतियोगिता है, उन्हें हमने सलाह दी है कि वे समारोह में हिस्सा नहीं लें और अपने खेल पर ध्यान लगाएं। समारोह के आधी रात तक चलने की उम्मीद है इसलिए यह बेहतर होगा कि वे अगले दिन होने वाली अपनी प्रतियोगिताओं के लिए आराम करें।' वहीं, भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता ने कहा कि खिलाड़ियों को कोरोना नहीं हो इसलिए हम न्यूनतम खिलाड़ियों को ही शामिल करेंगे। निशानेबाजों, मुक्केबाजों, तीरंदाजों के अलावा पुरुष और महिला हाकी टीमों को उद्घाटन समारोह के अगले दिन प्रतिस्पर्धा पेश करनी है। भारत ने उद्घाटन समारोह के लिए पुरुष हाकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और छह बार की विश्व चैंपियन महिला मुक्केबाज एम सी मेरी कोम को ध्वजवाहक बनाया है। मेरी कोम को अगले दिन खेलों में हिस्सा नहीं लेना है लेकिन, मनप्रीत अगले दिन न्यूजीलैंड के खिलाफ पूल-ए मैच में भारतीय टीम की अगुआई करेंगे। वर्मा ने हाल में जापान के शहर पहुंचे खिलाड़ियों और अधिकारियों के संदर्भ में कहा, 'जो लोग क्वारंटाइन में हैं, उन्हें भी हिस्सा लेने की स्वीकृति नहीं होगी।'


टोक्यो ओलिंपिक खेल गांव में अभ्यास करती भारतीय महिला हाकी टीम की खिलाड़ी • साई

धावक अरोकिया राजीव बोले, टोक्यो में हम लंदन ओलिंपिक से ज्यादा पदक जीतेंगे: भारतीय फर्राटा धावक अरोकिया राजीव का मानना है कि आगामी टोक्यो ओलिंपिक में पदकों की संख्या के मामले में देश 2012 के लंदन ओलिंपिक से बेहतर प्रदर्शन करेगा। 30 साल के राजीव चार गुणा 400 मीटर रिले टीम का हिस्सा हैं और वह शुक्रवार को टोक्यो रवाना होने वाले 26 एथलेटिक्स खिलाड़ियों में शामिल हैं। उन्होंने कहा, 'हम टोक्यो 2020 में निश्चित तौर पर लंदन 2012 से ज्यादा पदक जीतेंगे।'

हाकी इंडिया ने खिलाड़ियों के लिए हीरोज कनेक्ट लांच किया : हाकी इंडिया ने पुरुषों और महिलाओं के खेल में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के विस्तृत डेटाबेस को तैयार करने के लिए वेब-आधारित मंच, हीरोज कनेक्ट लांच किया। इस मंच के जरिये पूर्व और वर्तमान भारतीय हाकी खिलाड़ी खेल के बारे में रचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। भारत के लिए खेलने वाले सभी पूर्व और वर्तमान हाकी खिलाड़ी इस मंच पर अपना प्रोफाइल पंजीकृत कर सकते हैं, जिसे राष्ट्रीय महासंघ द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

ओलिंपिक के दौरान लगभग 5000 डोप नमूने लिए जाएंगे

टोक्यो, एपी : अंतरराष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (आइटीए) ने अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति (आइओसी) को कहा है कि तोक्यो ओलिंपिक के समय प्रतियोगिता के दौरान और इसके इतर डोप परीक्षण के लिए करीब 5000 नमूने लिए जाएंगे। आइटीए ने कहा कि वह पहले ही खेल से पूर्व अब तक का सबसे विस्तृत डोपिंग रोधी कार्यक्रम लागू कर चुका है। आइटीए ने आइओसी के 138वें सत्र के दौरान यह जानकारी दी। खेलों का उद्घाटन समारोह 23 जुलाई को होगा। आइओसी ने डोपिंग रोधी कार्यक्रम पर विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) और आइटीए दोनों से नवीनतम अपडेट की जानकारी ली। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय खेल पंचाट (आइसीएएस) की रिपोर्ट भी चर्चा के लिए पेश की गई।

भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ियों के लिए मुश्किल ड्रा

टोक्यो: भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ियों को टोक्यो ओलिंपिक में मुश्किल ड्रा मिला जिसमें शरत कमल और मनिका बत्रा की जोड़ी को शुरुआती मुकाबले में ही तीसरी वरीय जोड़ी से भिड़ना होगा। शरत और मनिका शनिवार को लिन युन जू और चेंग आई चिंग की चीनी ताइपे की तीसरी वरीय जोड़ी के खिलाफ अभियान शुरू करेंगे। हालांकि मनिका (62 रैंकिंग) को सिंगल्स के पहले दौर में आसान ड्रा मिला है जिसमें वह ब्रिटेन की हो टिन टिन से भिड़ेंगी जो उनसे रैंकिंग में 32 पायदान नीचे हैं। पुरुषों के ड्रा में शरत और साथियान ज्ञानशेखरन को क्रमशः 20वीं और 26वीं वरीयता मिली है और दोनों को पहले दौर में बाई मिली है। महिला सिंगल्स में सुतीर्था मुखर्जी पहले दौर में स्वीडन की लिंडा बर्गस्ट्रोम से भिड़ेंगी।

ताइक्वांडो, स्केटबोर्ड खिलाड़ी कोरोना पाजिटिव

चिली की ताइक्वांडो खिलाड़ी फर्नांडा एग्वायर और नीदरलैंड्स की स्केटबोर्ड खिलाड़ी केंडी जेकब्स कोविड-19 पाजिटिव पाए जाने के कारण ओलंपिक से बाहर हो गईं। फर्नांडा यहां हवाई अड्डे पर पहुंचने पर हुए परीक्षण में पाजिटिव पाई गईं।

गलती के कारण पोलैंड के छह खिलाड़ी वापस भेजे गए

पोलैंड के छह रिले तैराक अपने दल के साथ टोक्यो पहुंचे थे। पोलैंड तैराकी महासंघ ने क्वालीफिकेशन जमा कराने की प्रक्रिया के दौरान गलती कर दी। प्रशासनिक गलती के कारण पोलैंड ने ओलिंपिक नियमों का उल्लंघन करते हुए स्वीकृत खिलाड़ियों से अधिक के नाम भर दिए। इसके बाद छह खिलाड़ियों को टोक्यो से वापस भेज दिया गया।

ईस्ट बंगाल फुटबाल क्लब के समर्थक भिड़े, 50 हिरासत में

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : देश के सबसे बड़े फुटबाल क्लबों में शुमार ईस्ट बंगाल के समर्थकों के दो गुट बुधवार को आपस में ही भिड़ गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्थिति को नियंत्रित किया। 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक गुट क्लब की कार्यकारी समिति के अधिकारियों के समर्थन में तो दूसरा विरोध में है।

विरोधी गुट के सदस्य क्लब के वरिष्ठ अधिकारी देवब्रत सरकार के इस्तीफे और प्रायोजक के साथ क्लब के जल्द से जल्द करार की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रायोजक के साथ करार नहीं होने से क्लब के भविष्य पर सवालिया निशान लगता जा रहा है। इसकी वजह क्लब के वरिष्ठ अधिकारी देवब्रत सरकार हैं। उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। मालूम हो कि कुछ दिन पहले प्रायोजक श्री सीमेंट ने भी आरोप लगाया था कि क्लब के कुछ अधिकारियों के कारण करार पर हस्ताक्षर में विलंब हो रहा है।

ब्रिसबेन करेगा 2032 ओलिंपिक की मेजबानी

टोक्यो, एपी : अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति (आइओसी) ने बुधवार को ब्रिसबेन को 2032 ओलिंपिक की मेजबानी के लिए चुना। ब्रिसबेन के खिलाफ किसी शहर ने मेजबानी की दावेदारी पेश नहीं की। सिडनी में 2000 में खेलों के आयोजन के बाद ओलिंपिक 32 साल बाद एक बार फिर आस्ट्रेलिया लौटेंगे।

आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्काट मौरिसन ने अपने कार्यालय से आइओसी के मतदाताओं को कहा, 'हमें पता है कि आस्ट्रेलिया में सफल खेलों के आयोजन के लिए क्या करने की जरूरत है।' बाद में जब पुष्टि हुई की ब्रिसबेन ने मतदान में 72-5 से मेजबानी हासिल कर ली है तो मौरिसन ने दोनों हाथ हवा में उठाए और जीत की मुद्रा में दोनों हाथों के अंगूठे दिखाए। मतदान में जीत की खुशी में ब्रिसबेन में आतिशबाजी की गई और इसका प्रसारण आइओसी के सदस्यों को टोक्यो के पांच सितारा होटल में दिखाया गया।

2032 ओलिंपिक की मेजबानी के लिए भारत सहित इंडोनेशिया, कतर, स्पेन और जर्मनी ने भी रुचि दिखाई थी। हालांकि, इनकी दावेदारी आइओसी में बोर्ड स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई

2000 में दूसरी बार आस्ट्रेलिया में ओलिंपिक हुए थे और यह 15 सितंबर से एक अक्टूबर तक चले थे। इस बार मेजबान शहर सिडनी था। अब 2032 में ब्रिसबेन में ओलिंपिक होंगे

2028 में लास एंजिलिस : ब्रिसबेन से पहले 2028 में लास एंजिलिस, जबकि 2024 में पेरिस में ओलिंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। शुक्रवार को शुरू होने वाले टोक्यो खेलों से पूर्व बैठक में आइओसी सदस्यों के आधिकारिक मुहर लगाने से महीनों पहले आस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय शहर का 2032 खेलों का मेजबान बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया था।

अन्य देश निराश : आइओसी ने फरवरी में ब्रिसबेन को बातचीत का विशेष अधिकार दिया था। इस फैसले से कतर, हंगरी और जर्मनी के ओलिंपिक अधिकारी सकते में थे क्योंकि उनकी स्वयं की दावेदारी की योजना पर पानी फिर गया था। ब्रिसबेन को मेजबानी मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन इसके बावजूद आस्ट्रेलिया ने कोविड-19 महामारी के बीच अपना शीर्ष स्तरीय प्रतिनिधिमंडल टोक्यो भेजा, जिसे मंच पर भाषण देने थे।

गाबा का होगा आधुनिकीकरण : नए बोली प्रारूप के तहत ब्रिसबेन खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया पहला शहर है। नए प्रारूप में आइओसी संभावित दावेदार से संपर्क करता है और निर्विरोध उनका चयन करता है। प्रचार अभियान के खर्चे को कम करने के अलावा आइओसी को अधिक नियंत्रण देने और मत खरीदने के खतरे को हटाने के लिए इस प्रक्रिया को तैयार किया गया है।

ब्राजील और ब्रिटेन की फुटबाल टीमें जीतीं

रीफू, एपी : टोक्यो ओलिंपिक का आगाज शुक्रवार से होगा लेकिन महिला फुटबाल मैचों की शुरुआत बुधवार से हो गई। ब्राजील और ब्रिटेन की महिलाओं ने टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया। मार्टा के दो गोल की मदद से ब्राजील ने चीन को 5-0 से शिकस्त दी। मार्टा इस तरह लगातार पांच ओलिंपिक में गोल करने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं। दुनिया की सातवीं रैंकिंग की खिलाड़ी मार्टा के अलावा देबिंहा, आंद्रेसा एल्वेस और बीट्रिज ने भी गोल किए। मार्टा ने 111 अंतरराष्ट्रीय गोल दागे हैं जो ब्राजील के किसी महिला या पुरुष खिलाड़ी में सबसे ज्यादा हैं। नौंवे मिनट में किए गए उनके गोल के बाद देबिंहा ने 22वें मिनट में ब्राजील को 2-0 से आगे कर दिया। मार्टा ने अपना दूसरा गोल 74वें मिनट में किया। इसके बाद एल्वेस ने पेनाल्टी पर और बीट्रिज ने 89वें मिनट में गोल किया।

आस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड महिला फुटबाल टीम को हराया : आस्ट्रेलिया की महिला टीम ने बुधवार को यहां न्यूजीलैंड की महिला फुटबाल टीम को ग्रुप-जी के मैच में 2-1 से हराकर टोक्यो ओलिंपिक में जीत के साथ आगाज किया। आस्ट्रेलिया ने पहले हाफ में दो गोल दागे। तमेका यालोप ने 20वें मिनट में गोल करके आस्ट्रेलिया का मैच में खाता खोला। फिर केर समांता ने 33वें मिनट में गोल करके स्कोर 2-0 कर दिया। दूसरे हाफ में न्यूजीलैंड की टीम वापसी करने में जरूर सफल रही लेकिन, जीत नहीं हासिल कर पाई। न्यूजीलैंड की गाबी रेनी मैच के इंजुरी समय (90+1वें मिनट) में गोल करके हार का अंतर ही कम कर पाईं।


>> आस्ट्रेलिया के खिलाफ गोल करने के बाद न्यूजीलैंड की गाबी रेनी • रायटर

इस समय इससे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता था


सानिया मिर्जा कलम से



मैं अपने चौथे ओलिंपिक के लिए उत्साहित हूं। तैयारियां काफी अच्छी रही हैं। महामारी के बीच इससे अच्छा नहीं हो सकता था। पिछले कुछ हफ्तों में कुछ मैच खेलना भी अच्छा रहा। अंकिता (रैना) को भी कुछ दिन के लिए अच्छा अभ्यास मिल गया। महामारी की वजह से सामने आई चुनौतियों के बावजूद ओलिंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है। एथलीटों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी सावधानियां और कोविड प्रोटोकाल्स का पालन किया जा रहा है।

टोक्यो 2020 में भारतीय खिलाड़ियों के हिस्सा लेने में कोई बाधा ना आए, इसका पूरा ध्यान रखा गया। सरकार द्वारा चलाई गई वैक्सीनेशन ड्राइव और ओलिंपिक ट्रेनिंग के लिए खिलाड़ियों के लिए बायो-बबल्स इसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। सरकार ने ऐसा वातावरण बनाया, जिसमें जोखिम बहुत ही कम था। यह अपने आप में शानदार है। हम सभी ओलिंपिक में हिस्सा लेकर अपना सर्वश्रेष्ठ देने को लेकर काफी उत्साहित हैं। टोक्यो के लिए चार्टर प्लेन एक उदाहरण है कि सरकार एथलीटों की राह आसान बनाने के लिए कितना कुछ कर रही है। अंतरराष्ट्रीय यात्रा को लेकर कई सारे प्रतिबंध हैं और अभी स्थिति आसान नहीं है। सरकार ने जितना संभव हो सकता था, हमारे लिए उतना सर्वश्रेष्ठ इन्फ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट मुहैया कराया है ताकि हम टोक्यो में अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें।

एथलीटों की यात्रा संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार की भूमिका को जानने का मुझे निजी तौर पर अनुभव मिला। विंबलडन जाने से पहले मुझे वीजा मिलने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन सरकार ने सही समय हस्तक्षेप किया और मेरी यात्रा को आसान कर दिया। अगर आप एक एथलीट होने के साथ मां भी हैं तो चीजें आपके लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं। खेल मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने मिलकर मेरे दो साल के बेटे का वीजा भी सुनिश्चित किया। इसी वजह से वह मेरे साथ यूरोप टूर पर रहा। सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि मैं शांत दिमाग के साथ अपने खेल पर ध्यान दे सकूं। अब हम टोक्यो में हैं, हम ओलिंपिक में काफी अच्छी स्थिति में होने वाले हैं। एक टीम के तौर पर हम काफी अच्छे हैं और हमें यह पता है कि 1.3 अरब भारतीय प्रशंसकों का समर्थन भी हमें मिला है। भारतीय प्रशंसक हमें ताकत देते हैं। दुनिया के सबसे बड़े खेल मंच पर वापसी को लेकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। यह एक लंबा सफर रहा है और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने की पूरी कोशिश करूंगी।

पदक की चाह में नीरज ने कटवाए बाल


कुछ समय पहले लंबे बाल रखते थे नीरज • ट्विटर

विजय गाहल्याण • पानीपत

ओलिंपिक पदक की चाह के लिए स्टार भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने अपने बालों को ही कटवा दिया। नीरज लंबे बाल रखने के शौकीन हैं लेकिन, अभ्यास के दौरान उनके बाल उन्हें परेशान कर रहे थे। नीरज ने जब फेडरेशन कप के दौरान 88.07 मीटर भाला फेंका था तब उनके लंबे बाल थे।

फिनलैंड में भाला फेंक चैंपियनशिप में भी वह लंबे बालों के साथ खेले थे। वह तीसरे नंबर पर थे। इस प्रतियोगिता में उन्होंने सिर पर टोपी पहन रखी थी। बड़े बाल होने के कारण दो बार टोपी भी गिरी। इससे असुविधा हुई थी। अभ्यास के दौरान भी बाल बार-बार आंखों के सामने आ जाते थे। ओलिंपिक में स्पर्धा के दौरान भाला फेंकने में असुविधा न हो, इसलिए नीरज ने बाल कटवा लिए ताकि वह ओलिंपिक पदक अपनी झोली में डाल सकें। इसकी तस्वीर भी उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर डाली है। वह स्वीडन में रहकर ओलिंपिक की तैयारी में जुटे हैं।


बाल कटवाने के बाद नीरज • ट्विटर

छोटे बाल देख अचंभित रह गए मित्र : महराणा गांव के दीपक नांदल स्वीडन के स्टाकहोम शहर में रहते हैं। उन्हें वहां की नागरिकता मिली हुई है। नीरज यहीं ओकसाला शहर में अभ्यास कर रहे हैं। पांच दिन पहले नीरज अपने मित्र दीपक से मिले थे। नीरज के छोटे बालों को देख दीपक अचंभित रह गए। उन्होंने नीरज से कहा कि लंबे बालों में अच्छे लगते हो। फिर बाल क्यों कटा लिए? नीरज ने हंसते हुए कहा कि बालों से प्रेम है, लेकिन इनकी वजह से अभ्यास में असुविधा हो रही थी। इसी वजह से छोटे करा लिए। ओलिंपिक के बाद फिर से बार बढ़ा लूंगा। नीरज ने बताया कि फिनलैंड में उन्होंने जोहनस वैटर और वोलकोट के साथ प्रतियोगिता में खेलना का मौका मिला। वह ओलिंपिक में पदक जीतने के लिए अपना 100 प्रतिशत देंगे।

चैंपियन की तरह जवाब दिया : राहुल

कोलंबो, प्रेट्र : श्रीलंका दौरे पर गई सीमित ओवरों की भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने दूसरे वनडे मैच में जीत के साथ तीन मैचों की सीरीज अपने नाम करने के बाद ड्रेसिंग रूम में अपने प्रेरक भाषण में कहा कि टीम ने चैंपियन की तरह जवाब दिया।

जीत के लिए 276 रन का पीछा करने उतरी भारतीय टीम मंगलवार को 36वें ओवर में सात विकेट पर 193 रन बनाकर संघर्ष कर रही थी। दीपक चाहर (नाबाद 69) और भुवनेश्वर कुमार (नाबाद 19) की 84 रन की अटूट साझेदारी से हालांकि टीम पांच गेंद शेष रहते तीन विकेट से जीत दर्ज करने में सफल रही। बीसीसीआइ डाट टीवी पर जारी गए गए वीडियो में द्रविड़ ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों को संबोधित करते दिख रहे है। उन्होंने कहा, 'जाहिर है मैच के परिणाम के मामले में हम सही जगह रहे। यह अविश्वसनीय और शानदार है, लेकिन अगर हम मैच हार भी जाते तो यह संघर्ष पूरी तरह से शानदार था। आप सभी ने बहुत अच्छा किया। हमने कहा था कि वे (श्रीलंका) वापसी करेंगे, उनसे ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, क्योंकि वे भी एक अंतरराष्ट्रीय टीम हैं।' द्रविड़ ने कहा, 'यह व्यक्तिगत प्रदर्शन के बारे में बात करने का सही समय नहीं है, जाहिर है कि कुछ शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन देखने को मिले, खासकर मैच के आखिरी पलों में। हमने इस बारे में बात की थी, हम इस खेल में हर खिलाड़ी के योगदान को स्वीकार करते हैं। अगर आप पूरे मैच पर नजर डालें तो टीम का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा।' इस वीडियो में सूर्यकुमार यादव, भुवनेश्वर और चाहर भी मैच को लेकर अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। मैच में 53 रन की पारी खेलने वाले सूर्यकुमार ने कहा, 'मेरे पास शब्द नहीं हैं। मैं जिन मैचों का हिस्सा रहा हूं, उसमें मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा मुकाबला रहा। यह एक अविश्वसनीय जीत है।' चाहर ने चुटिले अंदाज में कहा, 'हर बार गेंदबाजी करने के बाद हमें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिलता था। आज मिला, अच्छा लगा। 50 ओवर क्षेत्ररक्षण करने के बाद मैंने लगभग 25 ओवर तक बल्लेबाजी की।'

> हमारा लक्ष्य अंतिम गेंद तक खेलना था, इसलिए हम मैच को अंत तक ले जाना चाहते थे। दीपक द्रविड़ के मार्गदर्शन में भारत-ए की ओर से खेल चुके हैं और उन्होंने वहां भी रन बनाए थे। द्रविड़ को पता था कि वह बल्लेबाजी कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने चाहर को पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा। -भुवनेश्वर कुमार

कोच ने टीम इंडिया की जीत को बताया अविश्वसनीय, कहा, मैच हार भी जाते तो शानदार था यह संघर्ष


राहुल द्रविड़ • एएनआइ

स्टार्क के पंजे में फंसे कैरेबियाई बल्लेबाज

ब्रिजटाउन (बारबडोस), एपी : मिशेल स्टार्क (5/48) व जोश हेजलवुड (3/11) की घातक गेंदबाजी से आस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में यहां वेस्टइंडीज को 123 रन पर समेटकर 133 रन से जीत दर्ज की। बारिश से प्रभावित मैच में 49 ओवर में 257 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने आठवें ओवर में 27 रन तक ही छह विकेट गंवा दिए थे,

इंग्लैंड ने पाकिस्तान से जीती टी-20 सीरीज : लेग स्पिनर आदिल राशिद (4/35) के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी से इंग्लैंड ने मंगलवार को यहां तीसरे और अंतिम टी-20 मुकाबले में पाकिस्तान को तीन विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। पाकिस्तान ने मुहम्मद रिजवान (76 रन, 57 गेंद, 5 चौके, 3 छक्के) के अर्धशतक की मदद से छह विकेट पर 154 रन बनाए। जवाब में इंग्लिश टीम 19.4 ओवर में सात विकेट पर 155 रन बनाकर जीत दर्ज करने में सफल रही। जेसन राय ने 64 रनों की पारी खेली।

भारत के खिलाफ इंग्लिश टीम में रोबिनसन की वापसी

क्रिकेट डायरी

लंदन, प्रेट्र : चोट से उबर चुके अनुभवी आलराउंडर बेन स्टोक्स की भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के शुरुआती दो मैचों के लिए घोषित 17 सदस्यीय टीम में वापसी हुई है, जिसमें नस्ली ट्वीट को लेकर निलंबित हुए तेज गेंदबाज ओली रोबिनसन को भी जगह दी गई है। भारत के खिलाफ ही 2016 मे अपना पिछला टेस्ट खेलने वाले सलामी बल्लेबाज हसीब हमीद की भी टीम में वापसी हुई है।

कोहनी की सर्जरी से उबर रहे जोफ्रा आर्चर और एड़ी में चोट से पीड़ित क्रिस वोक्स अभी मैच के लिए फिट नहीं हैं। अनुभवी जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्राड के अलावा टीम में मार्क वुड और सैम कुर्रन अन्य तेज गेंदबाज हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में पदार्पण करने वाले रोबिनसन के सात साल पुराने नस्लवादी ट्वीट के सामने आने के बाद इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने उन्हें क्रिकेट के सभी प्रारूपों से निलंबित कर दिया था। जानी बेयरस्टो और जोस बटलर की भी जो रूट की अगुआई वाली टीम में वापसी हुई है। इन दोनों को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में विश्राम दिया गया था। टीम की बल्लेबाजी इकाई में रोरी बर्न्स, ओली पोप, जैक क्राउले, डोम सिब्ले और डैन लारेंस भी हैं। टीम में हमीद का नाम थोड़ा चौंकाने वाला है। यह 24 साल का सलामी बल्लेबाज फिलहाल डरहम में भारत के खिलाफ खेले जा रहे अभ्यास मैच में काउंटी एकादश टीम का हिस्सा है। सीरीज का पहला टेस्ट नाटिंघम में चार अगस्त से शुरू होगा।

इंग्लैंड टीम: जो रूट (कप्तान), जेम्स एंडरसन, बेन स्टोक्स, जानी बेयरस्टो, डोम बेस, स्टुअर्ट ब्राड, रोरी बर्न्स, जोस बटलर, जैक क्राउले, सैम कुर्रन, हसीब हमीद, डैन लारेंस, जैक लीच, ओली पोप, ओली रोबिनसन, डोम सिब्ले, मार्क वुड।

आवेश इंग्लैंड दौरे से हो सकते हैं बाहर : युवा तेज गेंदबाज आवेश खान डरहम में भारत के प्रथम श्रेणी अभ्यास मैच के पहले दिन काउंटी एकादश की ओर से खेलते हुए बायें अंगूठे में चोट के कारण मैच से बाहर हो गए और उनका इंग्लैंड दौरे से बाहर होना भी लगभग तय है।

शुरुआती झटकों के बाद काउंटी एकादश को हमीद ने संभाला

नई दिल्ली: सलामी बल्लेबाज हसीब हमीद ने भारत के खिलाफ सीरीज के लिए इंग्लैंड की टेस्ट टीम में वापसी का जश्न शतक जड़कर मनाया। हमीद के शतक से काउंटी एकादश (काउंटी सिलेक्ट इलेवन) की टीम शुरुआती झटकों के बाद भारत के खिलाफ तीन दिवसीय मैच के दूसरे दिन 220 रन पर आउट हुई। हमीद 246 गेंदों पर 13 चौकों की मदद से 112 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर की गेंद पर लपके गए। भारत की ओर से उमेश यादव ने तीन विकेट झटके। इससे पहले भारत की पारी 311 रन पर सिमटी थी।

धवन को मिला फायदा

दुबई, प्रेट्र : भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में नाबाद अर्धशतकीय पारी के बाद दो पायदान के फायदे से बुधवार को जारी ताजा आइसीसी वनडे रैंकिंग में 16वें स्थान पर पहुंच गए, जबकि विराट कोहली दूसरे स्थान पर बरकरार हैं।

धवन कोलंबो में खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में नाबाद 86 रन की मदद से 712 रेटिंग अंक तक पहुंच गए, जिससे वह दो पायदान का फायदा हासिल करने में सफल रहे, जबकि कोहली के 848 अंक हैं। भारत के एक अन्य सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा 817 अंक से सूची में तीसरे स्थान पर हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम (873) शीर्ष पर हैं। रैंकिंग में जिंबाब्वे और बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की सीरीज, दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड के बीच तीसरा मैच तथा भारत व श्रीलंका के बीच पहले दो वनडे के नतीजों को देखा गया है।

तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर स्वीकार किया गया



1947 में आज ही संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकार किया था। 1931 में तिरंगे को ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। आजादी के बाद इसी तिरंगे में चरखे की जगह पर अशोक चक्र को स्थान दिया गया।



भारत के पहले संचार उपग्रह एपल ने काम करना शुरू किया

आज ही 1981 में भारत के पहले भूस्थिर संचार उपग्रह एपल ने काम करना शुरू किया था। इसे 19 जून, 1981 को फ्रेंच गुयाना से यूरोपीय स्पेस एजेंसी के यान से प्रक्षेपित किया गया था। इसरो ने इसे बेंगलुरु के सेटेलाइट सेंटर में डिजायन किया था। इसने करीब दो साल तक अपनी सेवाएं दी थी।

मुकेश ने बालीवुड में बतौर अभिनेता की थी शुरुआत

'द मैन विद गोल्डन वाइस' के नाम से प्रसिद्ध मुकेश का जन्म आज ही 1923 में दिल्ली में हुआ था। 1941 में फिल्म निर्दोष में बतौर अभिनेता करियर शुरू किया था। इन्हें 1945 में फिल्म नजर में बतौर प्लेबैक सिंगर मौका मिला। जीना यहां मरना यहां, इक दिन मिट जाएगा माटी के मोल जैसे सुपरहिट गाने गाए। इन्हें चार फिल्मफेयर अवार्ड मिले। इनकी आवाज में करीब एक हजार गाने हैं। 27 अगस्त, 1976 को अमेरिका के मिशिगन में एक लाइव कंसर्ट के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई थी।



इधर-उधर की

जब न्यूयार्क में सांड़ ने हाईवे को किया जाम



20 मिनट तक हाईवे पर रुका रहा ट्रैफिक। इंटरनेट मीडिया

न्यूयार्क, एजेंसी : सड़कों पर खुले जानवर घूमने की समस्या सिर्फ भारत में ही नहीं है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की न्यूयार्क पुलिस भी सड़क में घूम रहे एक सांड़ को पकड़ने के लिए परेशान है। सफोक काउंटी पुलिस विभाग ने इस बारे में कहा, सांड़ के सनराइज हाईवे को जाम करने की जानकारी मिलने के बाद उसे पकड़ने के लिए टीम को भेजा गया था। 20 मिनट बाद हाईवे पर ट्रैफिक फिर से चालू हो गया। साथ ही इस इलाके के लोगों को घरों में ही रहने के लिए कहा गया है। वह फार्म का बाड़ा तोड़कर भागा है। पुलिस और कई संगठन उसे पकड़ने का अभियान चला रहे हैं।

बादल बढ़ाएंगे ग्लोबल वार्मिंग का असर

चिंताजनक ▶ ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने अध्ययन के आधार पर दी चेतावनी

लंदन, प्रेट्र : वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग धरती के सबसे बड़े खतरों में से एक है। इसके पीछे कई मानवीय गतिविधियां भी जिम्मेदार हैं। अब इस कड़ी में एक और चिंताजनक बात सामने आई है। एक नवीन अध्ययन के आधार पर चेताया गया है कि वैश्विक तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की आशंका है, जो कि यूएन द्वारा तय लक्ष्य डेढ़ डिग्री सेल्सियस से दोगुना है। इसके पीछे एक बड़ी वजह बादल भी बनेंगे, जो सौर विकिरण को कम प्रतिबिंबित कर ग्रीनहाउस प्रभाव को बढ़ाएंगे। सरल शब्दों में कहें तो बादलों की वजह से गर्मी कम मुक्त होगी, जिससे धरती के तापमान में अधिक बढ़ोतरी होगी।

प्रोसीडिंग्स आफ द नेशनल एकेडमी आफ साइंसेस नामक जर्नल पर प्रकाशित इस शोध बताया गया है कि अब तक के सबसे प्रबल साक्ष्य मिले हैं, जो ये बताते हैं कि बादल लंबे समय तक वैश्विक तापमान को बढ़ाएंगे और जलवायु परिवर्तन को और तेज करने का काम करेंगे।

ब्रिटेन के इंपीरियर कालेज लंदन और यूनिवर्सिटी आफ ईस्ट एंग्लिया के विज्ञानियों ने धरती पर आच्छादित बादलों की उपग्रह माप के विश्लेषण के लिए एक नए तरीके को अपनाया। अध्ययन के आधार पर विज्ञानियों ने बताया कि वायुमंडल में औद्योगिकीकरण से पूर्व की तुलना में वर्तमान में कार्बन डाइआक्साइड की सांद्रता में दोगुना वृद्धि होने की आशंका है। इसके अलावा तापमान में बढ़ोतरी के लक्ष्य को दो डिग्री सेल्सियस से कम रखने की बात कही जा रही है, उसके सफल होने की उम्मीद बहुत कम है। इसके विपरीत, वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी तीन डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है। औद्योगिकीकरण से पूर्व कार्बन डाइआक्साइड का स्तर 280 पाट्र्स पर मिलियन (पीपीएम) था, लेकिन वर्तमान में यह करीब 420 तक पहुंच चुका है।

शोधकर्ताओं का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कार्बन डाइआक्साइड की मात्रा के दोगुना होने के इस पूर्वानुमान को जलवायु संवेदनशीलता के रूप में जाना जाता है। यह हमें बताता है कि इस तरह के बदलाव से हमारी जलवायु कड़ी प्रतिक्रिया देगी। शोधकर्ता कहते हैं कि जलवायु संवेदनशीलता के पूर्वानुमान में बादलों के कारण बहुत अनिश्चितता है। साथ ही यह भी नहीं पता है कि बादलों में बदलाव से यह परिवर्तन कितना प्रभावित होगा। ऐसा इसलिए है, क्योंकि बादल वातावरण में उनके घनत्व और ऊंचाई जैसे गुणों के आधार पर वार्मिंग को घटा, बढ़ा सकते हैं।

कितना पड़ेगा असर, यह जानने के लिए और अध्ययन की जरूरत : इंपीरियल कालेज लंदन से अध्ययन के सह-लेखक पाउलो सेप्पी के मुताबिक, जलवायु संवेदनशीलता के कारण भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग किस दिशा में बढ़ेगी इसे लेकर अत्यधिक अनिश्चितता है। यह इस पर भी निर्भर करता है कि वैश्विक तापमान में डेढ़ डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी से पहले हम क्या कदम उठाते हैं। साथ ही यह बादलों पर भी निर्भर करेगा। हमारे अध्ययन के परिणाम यह तो स्पष्ट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग पर बादलों का असर पड़ेगा, लेकिन कितना इसकी सटीक जानकारी के लिए और अध्ययन की जरूरत है।



तीन डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि की आशंका, इसे डेढ़ डिग्री से कम रखने का है लक्ष्य। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

इस तरह असर डालते हैं बादल

विज्ञानियों के मुताबिक, यदि बादल नीचे होते हैं तो उनसे शीतलन प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में बाधा उत्पन्न करते हैं। वहीं, जो बादल ऊंचे होते हैं वे गर्म प्रभाव डालते हैं, क्योंकि जब सौर ऊर्जा धरती पर पहुंच जाती है और लौटने लगती है तो वे उसके लौटने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस ऊर्जा के बादलों में फंसने से ग्रीनहाउस प्रभाव बढ़ सकता है। अभी तक के अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि 3.2 डिग्री सेल्सियस के करीब हो सकती है। हालांकि, इसकी सटीकता जानने के लिए और अध्ययन की जरूरत है।

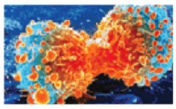


साइबर हार्स...

प्रौद्योगिकी के मामले में दुनिया में अग्रणी इजरायल की तेल अवीव यूनिवर्सिटी में छात्रों ने कंप्यूटर और मोबाइल वेस्टेज का उपयोग करके घोड़े का विशाल स्कल्पचर तैयार किया है। साइबर वीक कान्फ्रेंस स्थल के प्रवेश द्वार पर इसे लगाया गया है। इसमें मानिटर, कीबोर्ड, माउस, मदर बोर्ड और मोबाइल पाट्र्स का इस्तेमाल किया गया है। इलेक्ट्रनिक वेस्टेज आज पर्यावरण की दृष्टि से पूरी दुनिया में गंभीर चुनौती बन रही है। छात्रों ने इसका उपयोग करके संदेश दिया है कि वेस्टेज का भी इस्तेमाल संभव है। रायटर

खाद्य पदार्थों में केमिकल से बढ़ रहा स्तन कैंसर का खतरा

अनुसंधान



शरीर में हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ रहे केमिकल। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

रोजाना की दिनचर्या में खान-पान से लेकर अन्य उपभोक्ता उत्पादों में केमिकल का इस्तेमाल तेजी से प्रचलन में आया है। ये केमिकल स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। एक नए अध्ययन में सामने आया है कि खाने-पीने की चीजों से लेकर शरीर पर इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पादों में केमिकल के प्रयोग से स्तन कैंसर जैसी बीमारियों के खतरे बढ़े हैं। ये शरीर में हार्मोन के संतुलन को भी बुरी तरह बिगाड़ रहे हैं।

यह अध्ययन 'एनवायरमेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव' जर्नल में प्रकाशित हुआ है। अध्ययन में यह पता किया गया कि ये केमिकल स्तन कैंसर संभावना को किस तरह बढ़ा रहे हैं। साइलेंट स्प्रिंग इंस्टीट्यूट के रिसर्च डायरेक्टर और अध्ययन करने वाली टीम के प्रमुख और टोक्सिकोलाजिस्ट रूथान रुडेल ने बताया कि एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और स्तन कैंसर का संबंध पूरी तरह स्थापित है। इसी के आधार पर स्तन कैंसर का इलाज किया जा रहा है। इसलिए हमें ऐसे केमिकल के प्रयोग के प्रति सावधान रहना चाहिए, जो इन दोनों हार्मोन की शरीर में मात्रा को बढ़ाते हैं। अध्ययन में ऐसे 296 केमिकल की पहचान की गई, जो कोशिकाओं में एस्ट्राडियोल (एस्ट्रोजन का ही एक रूप) या प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ाते हैं। 71 ऐसे केमिकल थे, जो दोनों का स्तर बढ़ाते हैं। अभी अध्ययन में यह पता नहीं चला है कि केमिकल इन दोनों हार्मोन को किस तरह से बढ़ाते हैं, जिसके कारण स्तन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे पैदा होते हैं। - एएनआइ

समयपूर्व जन्मे बच्चों का स्क्रीन पर अधिक समय बिताना नुकसानदेह

वाशिंगटन, एएनआइ : मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट आदि पर अधिक समय बिताना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। इससे न केवल आंखों, बल्कि मस्तिष्क को भी कई समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। इस दिशा में किया गया एक नवीन अध्ययन समयपूर्व जन्मे बच्चों का स्क्रीन पर अधिक समय बिताने से उन्हें होने वाली समस्याओं के बीच संबंध बताता है।

शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में पाया कि छह से सात वर्ष की आयु के वे बच्चे, जिनका जन्म साढ़े सात माह या उससे पहले ही हो गया हो, वे यदि दिन में दो घंटे से अधिक समय कंप्यूटर, टेलीविजन आदि पर बिताते हैं तो उनके आइक्यू, एकाग्रता, कामकाज के तरीके आदि प्रभावित होते हैं। साथ ही उन्हें अपने आवेश पर भी नियंत्रण नहीं रहता। जामा पीडीएट्रिक्स नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि जिन बच्चों के कंप्यूटर, टेलीविजन आदि था, उनमें अपने आवेग को नियंत्रित करने में समस्या देखी गई और उनमें एकाग्रता की भी कमी पाई गई। अध्ययन में सामने आया कि समयपूर्व जन्मे बच्चों द्वारा ज्यादा समय स्क्रीन पर बिताने से उनमें व्यवहार के अलावा ज्ञान संबंधी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। यह अध्ययन बेट्टी आर. वोहर और उनके सहयोगियों द्वारा किया गया। पूर्व के अध्ययनों में सामने आ चुका है कि स्क्रीन पर अधिक समय बिताने का संबंध बच्चों के विकास, व्यवहार व अन्य प्रकार की समस्याओं से होता है। हालांकि, पूर्व के अध्ययनों को सामान्य बच्चों पर किया गया, लेकिन यह नवीन अध्ययन समयपूर्व जन्मे बच्चों को लेकर किया गया है। इस नवीन अध्ययन में गर्भावस्था में 28 सप्ताह या उससे पूर्व जन्मे 414 बच्चों के डाटा का विश्लेषण किया गया। इनमें से 238 बच्चे दो घंटे से ज्यादा समय स्क्रीन पर बिताते थे, जबकि 266 बच्चों के बेडरूम में टेलीविजन या कंप्यूटर लगा हुआ था।

जब इन बच्चों के डाटा की तुलना की गई तो पता चला कि वैश्विक स्तर पर क्रियाकलाप का जो मापदंड तय है उसकी तुलना में इन बच्चों का औसत स्कोर आठ प्वाइंट से कम आया, जो आवेश के मामले में करीब 0.8 होता है। साथ ही एकाग्रता की कमी के मामले में यह स्कोर तीन प्वाइंट अधिक आया। सरल शब्दों में कहें तो अध्ययन में स्पष्ट दिखा कि समयपूर्व जन्मे और स्क्रीन पर अधिक समय बिताने वाले बच्चों का अपने आवेश पर नियंत्रण नहीं होता है। यानी वे अधिक आक्रामक होते हैं। वहीं, उनकी एकाग्रता भी दूसरे बच्चों की तुलना में काफी कम होती है।

रखें ध्यान
- अमेरिकी शोधकर्ताओं ने अध्ययन के आधार पर दी सलाह
- बच्चे सीमित समय के लिए ही करें गैजेट्स का प्रयोग



स्क्रीन पर अधिक समय बिताने से एकाग्रता होती है प्रभावित। फाइल/इंटरनेट मीडिया

स्क्रीन शॉट

'मैंने जितेंद्र जी जैसा समय का पाबंद एक्टर नहीं देखा'



सिंगिंग रियलिटी शो में बतौर अतिथि पहुंचीं रीना। सौ. टीम सोनी

समय का पाबंद होना अपने आप में एक विशेष गुण है। अभिनेता जितेंद्र की इसी खासियत से उनके साथ कई फिल्मों में काम कर चुकीं अभिनेत्री रीना राय काफी प्रभावित हैं। रीना सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 के मंच पर आगामी एपिसोड की शूटिंग के दौरान बतौर मेहमान पहुंचीं। इस शो से जुड़े सूत्रों के अनुसार, शो के सभी प्रतिभागियों ने रीना से संबंधित फिल्मों के गानों पर परफार्म किया। मुजफ्फरनगर के प्रतिभागी दानिश खान ने जब साल 1977 में रिलीज हुई फिल्म अपनापन के गाने आदमी मुसाफिर है... गाने पर परफार्म किया तो रीना की इस फिल्म से जुड़ी यादें ताजा हो गईं। उन्होंने बताया कि यह गाना कश्मीर में शूट हुआ था। इसके लिए कलाकारों समेत सभी क्रू मैंबर लगभग एक महीने के लिए कश्मीर में ही रुके थे। उन दिनों क्रू मैंबर सेट पर अपने साथ अपने बच्चों को भी लेकर जाते थे। पैकअप के बाद हम एक साथ खूब खेलते और साढ़े सात बजे ही हम सब एक साथ बैठकर भोजन करते थे। वहीं, अपने सह अभिनेता जितेंद्र के बारे में रीना ने कहा, 'फिल्मकार जय ओम प्रकाश जी की अधिकतर फिल्मों में जितेंद्र जी मेरे सह-कलाकार रहे हैं। यकीन मानिए मैंने उनकी तरह समय का पाबंद इंसान कभी नहीं देखा है। यहां तक कि अमिताभ बच्चन जी भी नहीं। अगर कभी हमारा सुबह का शूट होता था तो जितेंद्र जी सभी को सुबह-सुबह पांच बजे फोन करते थे, जिससे सभी जल्दी से जल्दी सेट पर पहुंच जाएं। कई बार तो इसी वजह से हमने तय शेड्यूल से पहले ही शूटिंग पूरी कर ली।' इस एपिसोड का प्रसारण आगामी रविवार को सोनी चैनल पर होगा।

सलीम-जावेद के स्टार ब्रांड राइटर बनने का सफर दिखाएगी एंग्री, यंग मेन

हिंदी सिनेमा में जंजीर, शोले और दीवार जैसी सुपरहिट फिल्में लिखने वाले लेखक सलीम खान और जावेद अख्तर की जोड़ी पर हाल ही में डाक्यूमेंट्री बनाने की घोषणा की गई थी। एंग्री, यंग मेन शीर्षक वाली इस डाक्यूमेंट्री को सलीम खान के बेटे सलमान खान और जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर तथा बेटी जोया अख्तर प्रोड्यूस कर रहे हैं। नम्रता राव के निर्देशन में बन रही इस डाक्यूमेंट्री में जंजीर और शोले जैसी सुपरहिट फिल्मों के लेखन से जुड़े किस्से तथा साल 1982 में दोनों (सलीम-जावेद) के अलग होने के कारणों समेत कई पहलुओं को दिखाया जाएगा। इस बारे में दैनिक जागरण के सहयोगी अखबार मिड डे से बातचीत में फरहान ने कहा, 'सलीम-जावेद की कार्यशैली और नजरिये को समझने के लिए इस डाक्यूमेंट्री के सभी निर्माताओं के विचार काफी मिलते-जुलते हैं। इसी ने हमें एक साथ जोड़ा। यह डाक्यूमेंट्री दिखाएगी कि किस तरह से दो अलग-अलग पृष्ठभूमि से दो लोग फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं। वे किस तरह मिलते हैं और फिर एक साथ मिलकर एक अविश्वसनीय स्टार राइटर (लेखक) ब्रांड बनाते हैं। उनकी जोड़ी के अलग होने के बाद हिंदी सिनेमा में राइटर्स का ऐसा ब्रांड दोबारा नहीं बन पाया। यह डाक्यूमेंट्री उन विशेषताओं के बारे में बताती है, जिससे हिंदी सिनेमा में यह जोड़ी अविश्वसनीय बनी।' फरहान हाल ही में रिलीज हुई फिल्म तूफान में मुक्केबाज के किरदार में नजर आए हैं। जल्द ही वह अपने निर्देशन में बनने वाली अगली फिल्म की घोषणा करेंगे।



पिता के जीवन पर बन रही डाक्यूमेंट्री को प्रोड्यूस कर रहे हैं फरहान। इंस्टाग्राम

'आदित्य से पहले दोस्ती फिर हुआ प्यार'

गत जून में उरी : द सर्जिकल स्ट्राइक के निर्देशक आदित्य धर से अचानक शादी करके विकी डोनर अभिनेत्री यामी गौतम ने सबको चौंका दिया था। अब लगभग डेढ़ महीने बाद एक इंटरव्यू में यामी ने अपनी प्रेम कहानी के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि आदित्य के साथ मेरा पहली नजर वाला प्यार नहीं था। पहले हम अच्छे दोस्त थे। फिर रिश्ता प्यार में बदला। उरी : द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म के प्रमोशन के दौरान हमने बातें करनी शुरू की थीं। मैं इसे डेटिंग नहीं कहना चाहूंगी। हमारी दोस्ती शुरू हुई थी। यामी आगे बताती है कि उन्होंने आदित्य को अपना जीवनसाथी बनाने के बारे में कब सोचा। वह कहती हैं कि इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। बस पता चल जाता है। जब आप किसी इंसान के मूल्यों को समझने लगते हैं, वह किस परिवार से हैं, यह समझ जाते हैं तो अपने आप सब स्पष्ट हो जाता है। जरूरी नहीं है कि दो लोगों की दिलचस्पी एक जैसी हो। जिन मूल्यों में आप यकीन रखते हैं, वह एक जैसे होने चाहिए। मैं आदित्य की प्रोफेशनल के साथ एक अच्छे इंसान होने के लिए बहुत इज्जत करती हूं। मेरे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि तुम इतनी शांत कैसे हो, आवाज में नर्वसनेस क्यों नहीं है, क्योंकि मैं स्पष्ट थी कि मैं जो कर रही हूं वह सही है। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे आदित्य के परिवार में एक और परिवार मिल गया है। यामी की आगामी फिल्में दसवीं, अ थर्सडे, लास्ट और भूत पुलिस होंगी। वहीं, आदित्य फिल्म द इमोर्टल अश्वत्थामा पर काम कर रहे हैं।



आदित्य के साथ पहली नजर का प्यार नहीं था यामी का। इंस्टाग्राम

बकरीद पर सितारों ने की शांति के लिए प्रार्थना

महामारी के बीच त्योहारों की रौनक भले ही फीकी हो, लेकिन इंटरनेट मीडिया पर त्योहारों का मजा बिल्कुल कम नहीं हुआ है। बुधवार को ईद-उल-अजहा यानी बकरीद के मौके पर सितारों ने इंटरनेट मीडिया पर अपने प्रशंसकों को ईद की मुबारकबाद दी। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर लिखा, 'ईद-उल-अजहा मुबारक।' वहीं, माधुरी दीक्षित ने लिखा, 'अल्लाह का दिव्य आशीर्वाद आपके लिए आशा, विश्वास और आनंद लेकर आए। ईद-उल-अजहा मुबारक हो।' हिना खान ने लाल लिबास में अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए सबको बकरीद की मुबारकबाद दी। सारा अली खान ने पिता सैफ अली खान, भाइयों तैमूर, इब्राहिम और सैफ के तीसरे बेटे के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि अल्लाह सबको शांति, समृद्धि और सकारात्मकता प्रदान करें। सुरक्षित रहें। इस तस्वीर में सारा ने करीना कपूर खान और सैफ के दूसरे बच्चे की तस्वीर पर एक इमोजी लगा दी थी। हुमा कुरैशी ने इंस्टाग्राम पर भारतीय परिधान में अपनी एक तस्वीर साझा की और लिखा, 'ईद मुबारक, शांति, खुशी, रोशनी और कबाब। पूरी दुनिया के लिए मैं दुआ करती हूं।' रवीना टंडन ने भी अपनी तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि यह ईद आप सबके जीवन में सहानुभूति, प्यार और शांति ले आए। इसके अलावा कंगना रनोट, अनुभव सिन्हा, रकुल प्रीत सिंह समेत कई सितारों ने ईद की शुभकामनाएं दीं।



परिवार संग सारा ने मनाई ईद-उल-अजहा। इंस्टाग्राम

एक्टिंग मेरा काम है। मेरी फिल्म अगर पसंद आई तो आप टिकट लेकर फिल्म देखने जाएंगे। मैंने पैसे नहीं शायद लोगों के दिल जरूर चुराए होंगे। वो भी लौटा देता हूं।

दुबई में शादी और बेटी के सवाल का सलमान खान ने दिया जवाब

अभिनेता सलमान खान अपनी दरियादिली के साथ बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं। यूं तो 'दबंग' अभिनेता इंटरनेट मीडिया पर ट्रोलर्स को जवाब कम ही देते हैं, लेकिन अरबाज खान के शो पिंच के दूसरे सीजन में तो कई ट्रोल्स के जवाब उन्होंने खुलकर दिए। अरबाज ने सलमान के लिए एक ट्रोल का कमेंट पढ़ा, जिसे सुनकर सलमान भी हैरान हो गए। कमेंट में लिखा था 'कहां छुपा बैठा है डरपोक। भारत में सब जानते हैं कि तू दुबई में अपनी बीवी नूर और 17 साल की बेटी के साथ है। भारत के लोगों को कब तक मूर्ख बनाएगा'। इस पर सलमान ने पूछा कि यह कमेंट किसके लिए है? इन लोगों (ट्रोल्स) को बहुत पता है। यह बेफिजूल की बातें हैं। भाई साहब मेरी कोई पत्नी नहीं है। मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, गैलेक्सी अपार्टमेंट में नौ साल की उम्र से रह रहा हूं। आगे अरबाज ने एक और कमेंट पढ़ा जिसमें ट्रोल ने लिखा था हमसे और आपसे पैसे चुरा-चुरा के इतने सेटल हुए हैं। इस पर सलमान ने कहा पैसा नहीं शायद दिल चुराए होंगे। दिल लौटा भी देता हूं कई बार। एक ट्रोल ने सलमान के फार्महाउस को अय्याशी का अड्डा बताया था। इस पर सलमान ने कहा कि ऐसा क्या देख लिया उन्होंने? लाकडाउन में मेरे पोस्ट में वर्कआउट करते हुए या खेती करते हुए वीडियो थे।



अरबाज खान के शो पर पहुंचे सलमान • इंस्टाग्राम

18 दिन में शूटिंग पूरी हो गई : मनोज बाजपेयी



फिल्म डायल 100 में पुलिस अधिकारी के किरदार में नजर आएंगे मनोज • जागरण आर्काइव

कोरोना काल की वजह से फिल्मकारों की कार्यशैली में काफी बदलाव आए हैं। इन्हीं बदलावों के तहत पहले महीनों चलने वाली शूटिंग अब कुछ निर्माता-निर्देशक सुनियोजित तरीके से चंद सप्ताह में ही खत्म कर रहे हैं। कार्तिक आर्यन अभिनीत फिल्म धमाका की शूटिंग 16 दिनों में पूरी होने के बाद अब मनोज बाजपेयी और नीना गुप्ता अभिनीत फिल्म डायल 100 महज 18 दिनों में शूट हो गई। मंगलवार की रात इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। इस मौके पर आयोजित वर्चुअल कांफ्रेंस में फिल्म के कलाकार मनोज, नीना और साक्षी तंवर के साथ निर्देशक रेंसिल डिसिल्वा भी शामिल हुए। इस दौरान मनोज ने बताया, 'यह फिल्म दिखाती है कि कैसे सिर्फ एक फोन कॉल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। रेंसिल ने इसकी स्क्रिप्ट मात्र छह दिनों में लिखी, हमने बिना रुके लगातार सिर्फ 18 दिनों में इस फिल्म की शूटिंग खत्म की। जिसमें मैंने 10-12 दिनों तक शूट किया था।

हिंदी सिनेमा में पदार्पण कर सकती हैं नयनतारा...

पैन इंडिया फिल्मों की बढ़ती लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए अब निर्माता फिल्मों की कास्टिंग हिंदी और दक्षिण भारतीय सिनेमा के कलाकारों को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। अभिनेता शाह रुख खान के जल्द ही तमिल फिल्मों के निर्देशक एटली कुमार के साथ एक्शन थ्रिलर फिल्म करने की खबरें काफी दिनों से चर्चा में हैं। अब खबर है कि शाह रुख और एटली कुमार की इस फिल्म की अभिनेत्री का नाम भी तय कर लिया गया है। चूंकि, शाह रुख और एटली दोनों इस फिल्म का निर्माण हिंदी के साथ-साथ अन्य भाषाओं में भी करना चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने इस फिल्म के लिए दक्षिण भारतीय सिनेमा की अभिनेत्री नयनतारा को चुना है। अगर सब कुछ सही रहा, तो इस फिल्म से नयनतारा हिंदी सिनेमा में अपनी पारी का आगाज करेंगी। सूत्रों के मुताबिक, फिल्म के लिए नयनतारा ने स्वीकृति दे दी है। फिल्म में शाह रुख डबल रोल में होंगे, जबकि नयनतारा के किरदार के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।



दक्षिण भारतीय सिनेमा में डेढ़ दशक से ज्यादा समय से सक्रिय हैं नयनतारा • इंस्टाग्राम

लुका छुपी 2 जरूर बनेगी : लक्ष्मण उतेकर

आगामी दिनों में बनने वाली सीक्वल फिल्मों में लुका छुपी का नाम भी सामने आया था। साल 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ने किया था। लिव इन और उसकी दिक्कतों को लेकर बनी रोमांटिक कामेडी फिल्म लुका छुपी की सीक्वल की कहानी एक शादीशुदा जोड़े के आसपास बताई जा रही है, जो तलाक लेना चाहता है और उनके परिवार को इस बात की खबर नहीं है। इस फिल्म की सीक्वल को लेकर क्या तैयारियां हैं, इसे लेकर लक्ष्मण उतेकर ने दैनिक जागरण से बातचीत में बताया कि लुका छुपी 2 को लेकर कई खबरें हैं। लुका छुपी 2 जरूर बनेगी, लेकिन सिर्फ बनाने के लिए हम फिल्म नहीं बना देंगे। कहानी दिमाग में आना और सबका उसे पसंद करना भी उतना ही जरूरी है। कई बार लोग दबाव में सीक्वल बना लेते हैं, लेकिन फिर कहानी का सही रास्ता नहीं पकड़ पाते हैं। मेरा मानना है जब कहानी दिमाग में आएगी और लगेगा कि बनानी चाहिए, तो जरूर बनाएंगे। मुद्दे आधारित फिल्में बनाने को लेकर लक्ष्मण कहते हैं कि फिल्म में एक मुद्दा होना जरूरी है। हम बहुत लकी हैं, जो इस मीडियम में हैं। हमारी बनाई हुए क्रिएशन लोग सौ साल बाद भी देखते हैं। हमारी बनाई हुई फिल्में लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। हमारे पास एक जरिया है, जिसके जरिये हम लोगों को अच्छी बातें सिखाएं।



लुका छिपी का निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ने किया था • पीआर टीम